राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का १८वां दिवस [संख्या १४

बृहस्पतिवार ५ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री गिरधारीलाल।

टी. बी. हॉस्पिटल, बीकानेर

३१९. श्री गिरधारीलाल (नौखा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर टी. बी. हॉस्पिटल में इस समय कितने बैड्स और कितने डॉक्टर हैं ?

(२) क्या यह सही है कि टी. बी. हॉस्पिटल के मरीज़ों को खाना अच्छा नहीं दिया जाता व दूध पॉउडर का दिया जाता है ?

(३) क्या यह सही है कि इस हॉस्पिटल के मरीज़ों के साथ डॉक्टर व अन्य लोग अभद्र व्यवहार करते हैं ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त हॉस्पिटल की दवाइयां बाज़ार में बेच दी जाती हैं और मरीज़ों से कहा जाता है कि दवा बाज़ार से खरीदें ? अगर हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवायेगी और सम्बन्धित अधिकारी को दण्ड देगी ?

उप स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई):(१) बीकानेर टी. बी. अस्पताल में १०१ रोग शैय्या तथा तीन डॉक्टर हैं।

(२) जी नहीं, अच्छे दूध के अतिरिक्त उनको पॉउडर का दूध जो टी. बी. के बीमारों के लिये यूनिसेफ से प्राप्त होता है, दिया जाता है।

(३) इस प्रकार की शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(४) इस प्रकार की शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु बीमारों को कीमती तथा असाधारण औषधियां बाजार से खरीदनी पड़ती हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर नगर) : बाजार से खरीदना पड़ता है इसके लिये कोई आधार है कि कौनसी बाजार से खरीदना और कौनसी अस्पताल से मिलनी चाहिये ?

Page No 2

श्री भीखाभाई : जी हां, इसकी एक लिस्ट अस्पताल में रक्खी जाती है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या वह सूची बोर्ड पर भी टांगी जाती है जिससे जो देखना चाहे देख सके। नहीं टांगी जाती हो तो अब आदेश दिये जाएं कि अस्पताल के बोर्ड पर हिन्दी भाषा में टांग दी जावे।

(हंसी)

श्री गिरधारीलाल : क्या अस्पताल में खाना और दूध अच्छा मिलता है मरीज़ को ?

श्री मूलचन्द डागा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री): आपका प्रश्न इससे पैदा नहीं होता ?

श्री गिरधारीलाल : मेरे सवाल का जवाब दीजिये। आपको दूध सप्लाई कौन करता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आम तौर पर डाइट का ठेका होता है। दूध यूनिसेफ का भी हम देते हैं जो कि हमें फ्री सप्लाई में मिलता है और मरीज़ों को भी फ्री दिया जाता है।

कोटा से जयपुर, अजमेर तथा जोधपुर को बस सर्विस

३२०. **श्री रामेश्वरदयाल** (कोटा) : क्या यातायात मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) कोटा से जयपुर तक सीधी बस सर्विस चलाने का प्रश्न कितने माह से सरकार के विचाराधीन है और अब यह मामला किस स्टेज पर है ?

(ख) कोटा से अजमेर तक सीधी बस सर्विस क्यों नहीं चलाई जा रही है ?

(ग) क्या सरकार कोटा से जोधपुर सीधी बस सर्विस चलाने का विचार कर रही है ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) यह प्रश्न करीब २–३ साल से विचाराधीन है।

(ख) मामला विचाराधीन है।

(ग) ऐसा अभी कोई विचार नहीं है।

श्री रामेश्वर दयाल : यह बस सर्विस कब तक चालू हो जायेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, अब तो जोधपुर में हाईकोर्ट भी आ गया है इसलिए कोटा से जोधपुर डाइरेक्टर बस सर्विस जल्दी ही चालू होनी चाहिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी नेशनेलाइज़ेशन वाला मामला फाइनल होने वाला है। अब यह फाइनल होने पर आगे कितनी और बच रहेंगी और कितने रूट बाकी रह जायेंगे इन सब पर बाद में विचार करेंगे।

श्री रामेश्वरदयाल : इस सवाल के निर्णय नहीं होने के क्या कारण हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कारण मैंने बता

(श्री नाथूराम मिर्धा)

दिये हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि बड़े बड़े रूट्स को नेशनेलाइजेशन किया जाये। अब क्या किया जाय और कितना कर सकेंगे यह सब बाद में देखने के बाद मालूम होगा और कितने रूट्स बच जाते हैं उसका क्या इन्तज़ाम होगा, सब बाद में डिसाइड होगा।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कई दफा पूछा जा चुका है और हर दफा इस प्रश्न का उत्तर यही मिलता है, इसका क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो उत्तर है वही तो मिलेगा। आप बारबार पूछें तो कोई उत्तर थोड़े ही बदला जा सकता है।

श्री रामेश्वर दयाल : क्या सरकार राष्ट्रीयकरण होने तक टेम्पोरेरी पर्मिट्स इस शर्त के साथ देने के लिए तैयार है कि बस आपरेटर्स बिना किसी मुआवजे के जब सरकार चाहेगी तब बसेस वापिस ले लेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : टेम्पोरेरी पर्मिट्स नहीं दिये जाने चाहिए। कानून में भी लिखा हुआ है कि केवल दो तीन शर्तों पर ही टेम्पोरेरी पर्मिट्स दिये जा सकते हैं "Temporary permits are granted on temporary needs" और यह टेम्पोरेरी नीड्स के अन्दर नहीं आता है, टेम्पोरेरी अरेन्जमेंट नहीं हो सकता।

श्री रामेश्वर दयाल : क्या जनता की परेशानी को दूर करने के लिए राष्ट्रीयकरण होने तक कोई टेम्पोरेरी प्रबन्ध नहीं हो सकता ?

श्री अध्यक्ष : टेम्पोरेरी परेशानी थोड़े ही है।

श्री रामेश्वर दयाल : तो फिर इस सवाल को जल्दी ही तय किया जाना चाहिए, इसी साल ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो समय लगेगा वह तो लगेगा ही।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

सेजरासर पंचायत कार्यालय

३२१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) लूणकरणसर तहसील के सेजरासर गांव में पंचायत का कार्यालय कब से कार्य कर रहा है ?

(२) क्या सरकार ने यहां से पंचायत के कार्यालय को कुजटी में ले जाने का विचार किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) सेजरासर और कुजटी की आबादी कितनी कितनी है ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) दिनांक २–३–४६ से।

(२) जी हां। जन सुविधा की दृष्टि से।

(३) सेजरासर की जन संख्या ७८५ एवं कुजटी की २६३ है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो दो में कहा गया है कि क्या सरकार ने सेजरासर से

Page No 4

(श्री मुरलीधर व्यास)

पंचायत के कार्यालय को कुजटी में ले जाने का विचार किया है तो यह किस कारण से किया गया है या फिर विचार किया ही नहीं गया। सेजरासर में इस समय पंचायत और उस पंचायत का कार्यालय इस समय कहां पर है ?

श्री दौलतराम सारण : सेजरासर केन्द्र स्थान अन्य गांवों से बहुत दूर पड़ता था। लूणकरणसर तहसील के सेजरासर, खारी और कुजटी गांवों को, तीनों को मिला कर उनकी पंचायत बना दी गई और अब कुजटी पंचायत का केन्द्र कर दिया गया है क्योंकि सेजरासर से पहले कई गांव दूर पड़ते थे। यह तो ठीक है कि कुजटी की आबादी कम और सेजरासर की जनसंख्या ज्यादा है लेकिन इन तीनों गांवों में कुजटी जो है वह बीच में पड़ती है और इसके नज़दीक खारी गांव भी पड़ता है। इस प्रकार इन तीनों गावों की एक पंचायत बनाई गई। कुजटी पहले भी पंचायत का केन्द्र था और यहां पर सुविधायें भी अधिक थीं। यहां पंचायत का घर भी बना हुआ है और यह पटवारी का केन्द्र स्थान भी है और इस गांव के लोग इसको एक मॉडल विलेज भी बनाने का इरादा कर रहे हैं। एक नया कुंआ भी बना रहे हैं इसलिए उसे पंचायत का केन्द्र बनाया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : सेजरासर में बड़ी पंचायत थी वह कितने साल तक रही और फिर वहां से क्यों हटाई जा रही है ?

श्री दौलतराम सारण : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : उत्तर तो आप दे चुके हैं लेकिन मेरा सवाल यह है कि सेजरासर की जो पंचायत वहां पर इतने समय तक रही और कुजटी में सेजरासर के मुकाबिले में इतनी आबादी भी नहीं है तो फिर भी सेजरासर से पंचायत को क्यों हटाया जा जा रहा है ?

श्री दौलतराम सारण : आपकी जानकारी के लिए मैं फिर बतला दूं कि सेजरासर व और पंचायतों के जो गांव थे वह दस बारह मील दूर पड़ते थे उन्हें सभी पक्की पंचायतों में लगाने की और गांव वालों की मांग थी और यह भी मांग थी कि इन तीनों गांवों की सेजरासर, खारी और कुजटी एक पंचायत बना दी जाये। अब इन तीनों गांवों की एक पंचायत बना कर कुजटी को पंचायत का केन्द्र बना दिया। कुजटी की जन संख्या कम है परन्तु वहां पर और दूसरी सहूलियतें ज्यादा हैं। कुजटी केन्द्र में भी पड़ता है इसीलिए उसको पंचायत का केन्द्र बनाया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा कि लोगों की राय से बनाई मगर मैं आपको बताऊं कि सेजरासर के लोगों ने कुजटी में पंचायत को ले जाने पर उसका विरोध किया। फिर उसका विरोध होते हुए भी क्यों इस प्रकार का सरकार ने किया ?

श्री दौलतराम सारण : कुछ लोग विरोध करते हैं और कुछ लोग मांग करते हैं लेकिन सरकार को यह देखना पड़ता है कि जनसुविधा की दृष्टि से कौन से स्थान अधिक उपयुक्त हैं और वहां क्या क्या सुविधायें हैं। इस बात को देखकर निर्णय किया जाता है उसी लिहाज़ से जिन आधारों को

Page No 5

(श्री दौलतराम सारण)

मैंने बताया उनके अनुसार कुजटी में पंचायत को रखने का निर्णय लिया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : सेजरासर के ७५ पर्सेंट लोग इसका विरोध करते हैं तो फिर २५ पर्सेंट लोगों के लिए इतना परिवर्तन क्यों किया गया ?

श्री दौलतराम सारण : सेजरासर के लोग विरोध करते हैं या नहीं करते हैं, यह प्रश्न नहीं है प्रश्न तो यह है कि उस पंचायत में जो जो गांव थे वे सेजरासर से दूर पड़ते थे।

श्री अध्यक्ष : अभी जो पंचायत सर्किल है उसका केन्द्र कौन सा है ?

श्री दौलतराम सारण : कुजटी।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सेन्टर में पड़ता है ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां।

श्री अध्यक्ष : तो ठीक है।

श्री दौलतराम सारण : तीन गांवों की एक पंचायत है और कुजटी बीच में पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्सट

श्री मुरलीधर व्यास : इसका उत्तर तो मुझे अच्छी तरह से नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : उत्तर तो पूरा मिला लेकिन आपको संतोष नहीं हुआ तो क्या करें।

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

डूंगरपुर नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत

३२२. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या डूंगरपुर नगरपालिका अध्यक्ष श्री कुरीचन्द जैन के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायत हुई है कि उन्होंने नगर विकास के लिए मिले १,००,०००) रुपये के कर्जे की रकम में गोलमाल किया है ?

(२) क्या इन्हीं सज्जन के विरुद्ध जिला बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से बोर्ड के १५,०००) रु० अपने निजी काम में लेने की शिकायत सरकार के पास आई है ?

(३) यदि उपरोक्त शिकायतें राज्य सरकार के पास आई तो उन पर क्या कार्यवाही हुई है ?

(४) क्या नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत उनको कोई शो काज नोटिस दिया गया और क्या ऐसे व्यक्ति का अध्यक्ष बना रहना सार्वजनिक दृष्टि से तथा कानूनी दृष्टि से उचित है ?

मंत्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां।

(२) इस सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी प्राप्त नहीं है।

(३) सरकार ने श्री कुरीचन्द जैन को अध्यक्ष पद से अपदस्थ कर दिया है।

(४) जैसा (३) में उत्तर दिया गया है

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

श्री कुरीचन्द जैन को अध्यक्ष पद से अपदस्थ कर दिया गया है और मामला एन्टीकरप्शन में भेज दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १ लाख रुपये वाले केस को भेजा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो एक लाख वाला केस है उसको एन्टीकरप्शन में भेज दिया गया है और उसको अपने काम से अलग कर दिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपको बताऊं कि आपको शिकायत भी हुई है। प्रश्न संख्या २ में इन्हीं सज्जन के विरुद्ध जिलाबोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से बोर्ड के १५००० रुपये अपने निजी काम में लेने की शिकायत सरकार के पास आई और इसकी शिकायत तो आपके पास है। इसके लिए रिटन पर्चे बांटे गये थे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : निजी काम में आने की बात नहीं थी। ऑडिट रिपोर्ट में यह था कि वह कम्पनी में लगा दी। लेकिन वह सारा केस एन्टीकरप्शन को भेज दिया गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह कम्पनी तो उसकी खुद की थी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो एक्शन लेने की बात थी वह तो हमने ले लिया। उसको पद से हटा दिया और जो गबन किया है उसका केस एन्टीकरप्शन में भेज दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दोनों ही केस भेजे हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : केस किसकी रिपोर्ट के आधार पर भेजा गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

सांचौर सीड स्टोर में धान की कमी

३२३. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला जालौर के सांचोर सीड स्टोर में कितने मन धान की कमी है और इस कमी का क्या कारण है ?

उपमंत्री कृषि विभाग (श्री दौलतराम सारण): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न की पूरी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है इसलिए इसका उत्तर नेक्स्ट टर्न पर दे दिया जायेगा।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, हाउस के सामने यह डिफिकल्टी तो बतानी चाहिए कि पूरी सूचना क्यों नहीं प्राप्त हुई। अब यह सेशन तो १६ तारीख तक चल रहा है और फिर बाद में इस प्रश्न को रखेंगे। अभी अभी लोकसभा में बताया था कि एक प्रश्न के ऊपर ६० रुपये खर्च होते हैं। तो प्रश्नों का उत्तर यहां देने की माननीय मन्त्री महोदय तकलीफ करें तो अच्छा रहे।

मन्त्री कृषि विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा): सांचोर काफी दूर पड़ता है।

श्री श्रीभानसिंह : मैं अध्यक्ष महोदय को निवेदन कर रहा था।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय को तो मैं जानकारी दूंगा तभी तो होगा। सांचौर बहुत दूर पड़ता है फिर वहां पर टेलीफोन की फैसिलिटी भी नहीं है। वहां पर तार भी तीन दिन में पहुंचता है। मैंने आपको कहा कि नेक्स्ट टर्न पर उत्तर दे देंगे तो इसमें १९ तारीख की बात कहां आती है।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह सवाल रखे तो २० दिन हो गए हैं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

जयपुर नगर विकास मण्डल द्वारा प्लाट्स का अलॉटमेंट

३२४. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर नगर विकास मण्डल द्वारा निम्न व्यक्तियों को प्लॉट्स कब और किस स्कीम में अलॉट किये गये :

(क) श्री समर्थराज, संचालक, कृषि विभाग,

(ख) श्री के. सी. सत्संगी, सुपरिटेंडिंग इन्जीनियर।

(ग) श्री सुमेरनाथ गुर्टू।

(२) उपरोक्त व्यक्तियों ने दर्ख्वास्तें किस किस तारीख को दी और इनको प्लाट दिये जाने से पूर्व कुल कितनी दर्ख्वास्तें पेंडिंग थी ?

(३) क्या इनसे पहले दरख्वास्तें देने वालों को प्लाट नहीं देकर इनको पहले प्लाट दिया जाना अनियमितता एवं पक्षपात नहीं है ? यदि हां, तो क्या इनके अलॉटमेंट रद्द करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) श्री समर्थराज २९-११-५१ प्लाट सं० बी० १५, डी. बेनीपार्क।

(ख) श्री के. सी. सत्संगी २९-११-५१ प्लाट सं० बी० १,५ डी, बेनीपार्क।

(ग) श्री सुमेरनाथ गुर्टू २२-९-५५ प्लाट सं० एल, ५ बी स्कीम सी।

(२) श्री समर्थराज व श्री सत्संगी को प्रथमतः जब भूखण्ड अलॉट किये गये उस समय के विचाराधीन पत्रों, प्रार्थना-पत्रों का कोई रिकॉर्ड मन्डल के कार्यालय में नहीं हैं। इसका कारण यह है कि उस समय प्रार्थना-पत्र विशेष भूखण्डों के लिये दिये जाते थे। सरकार आवश्यक जांच के पश्चात् भूखण्ड अलॉट कर देती थी।

(३) राज्य सरकार द्वारा बनाये गये भूमि अलॉटमेंट विनियमों में राज्य कर्मचारियों को प्राथमिकता दिये जाने का विधान है अतः इन व्यक्तियों को प्राथमिकता दिये जाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई अनियमितता अथवा पक्षपात दृष्टिगत नहीं होता है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिन प्लाट्स के अलॉटमेंट के बारे में बताया, वे बेनीपार्क में हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बेनीपार्क में श्री समर्थराज और श्री के. सी. सत्संगी के प्लाटस

Page No 8

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

हैं और श्री सुमेरनाथ गुई का प्लाट सी, स्कीम में है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या श्री समर्थराज और श्री सतसंगी को एम. एल. एज. क्वार्टर्स के पास प्लाट्स अलॉट किये गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कैसे हो सकता है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वहां उनके मकान बने हुए है।

श्री पी० के चौधरी (फुलेरा) : एम. एल. एज. बंगलों के पास मकान बने हुए हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास जानकारी यह है। मैं दुबारा देखूंगा।

श्री पी० के० चौधरी : मेरे बंगले के पास ही उनके प्लाट्स हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा प्रश्न साफ है। जयपुर नगर विकास मंडल द्वारा निम्न व्यक्तियों को प्लाट्स कब और किस स्कीम में अलॉट किये गये ? जिन प्लाट्स का हवाला दिया गया है, वह यू. आई. बी. ने दिये हैं और विप्र विद्यालय की दो तरफ जो तीन प्लाट्स निकलते थे, वे प्लाट्स दिये गये हैं। सरकार ने जो अलॉटमेंट किये हैं उसके बारे में मैं नहीं पूछता हूं।

श्री अध्यक्ष : जो प्लाट्स बेनीपार्क में अलॉट किये है, उनको एक्स्चेंज कर लिया होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास जवाब यही आया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने पूछा है कि यू. आई. बी. ने कहां प्लाट्स अलॉट किये हैं और कितनी एप्लीकेशन्स पेंडिंग थी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने यू. आई. बी. की कम्प्लीट लिस्ट दे दी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १९५५ से पहले की नहीं है। जो १९५६–५७ में अलॉटमेंट किया है, उसकी है।

श्री अध्यक्ष : उसके लिए कह रहे हैं कि हम प्रायोरिटी दे रहे हैं सरकारी ऑफिसर्स को।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्वेश्चन इस बात का है कि इनको प्लाट्स अलॉट हुए या नहीं ? वे कहते हैं कि यू. आई. बी. से अलॉटमेंट नहीं हुआ है। मैं चैलेंज करता हूं कि उन्हें अलॉटमेंट हुआ है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं उसको दुबारा देखूंगा। मेरे पास जो यू. आई. बी. से जवाब आया है, वह जवाब दिया है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या इनके नाम में दो प्लाट्स अलॉट हुए हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपके कहने के मुताबिक यही मालूम होता है।

श्री श्रीभानसिंह : आपका कहना है कि उनको दो प्लाट्स अलॉट हुए हैं। इसकी आपके पास इन्फामेंशन नहीं हैं ? क्या गवर्नमेंट उन ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लेगी, जिन्होंने अपने नाम दो प्लाट जयपुर में अलाट करा रखे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह हाईपोथेटिकल बात हुई। This is based on presumption. १६५१ में जो अलॉटमेंट हुए वे कैंसिल हो गये होंगे। फिर भी I will enquire into the matter.

श्री श्रीभानसिंह : Is the Hon'ble Minister in a position to say. अगर १६५१ में प्लाट अलॉट हुए हैं और अगर उन प्लाट्स को एक्सचेंज कराने की इन्फॉर्मेशन तो मौजूद होती।

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है। वे जांच लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे कह दें कि जानकारी कर लेंगे और अगर उन्होंने दो प्लाट्स लिये हैं तो सरकार उनके खिलाफ क्या एक्शन लेगी ?

श्री अध्यक्ष : वह तो हमेशा है ही।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर रूल्स के खिलाफ है तो देख लेंगे। मैं पूरी जानकारी करके ही अर्ज कर सकता हूं।

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble Minister says that he has been alloted a plot now but I have seen with my own eyes that Bungalow.

श्री अध्यक्ष : It has become clear. Why are you repeating that thing? The Hon' Minister will enquire into the matter. Why labour a dead horse ?

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : दो प्लॉट नहीं, १६ प्लाट्स भी कई के पास हैं, उनके लिए क्या ?

श्री अध्यक्ष : उनकी लिस्ट पेश कर दीजिये, उनकी जांच हो जायगी।

(विराम)

श्री श्रीभानसिंह।

भरतपुर जिले के रतना और रसीलपुर ग्रामों के बीच 'इर्रिगेशन कल्वर्ट' का निर्माण

३२५. **श्री श्रीभानसिंह** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state :—

Is there any Scheme to construct an irrigation culvert on the river between the villages Ratana and Rasilpur of Rupbas Tehsil of Bharatpur Distt ?

उपमंत्री सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई): No, Sir.

जयपुर में खाद्यान्न समस्या

३२६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या खाद्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या २१ व २२ दिसम्बर १६५८ को जयपुर में कोई खाद्यान्न सम्मेलन हुआ ? यदि हां, तो क्या उसने खाद्यान्न समस्या को हल करने के लिये कोई सुझाव सरकार को दिये ? यदि हां, तो उन सुझावों की एक प्रति सदन की मेज़ पर रखें ?

(२) क्या सरकार ने सम्मेलन द्वारा दिये गये सुझावों पर कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या ?

Page No 10

खाद्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां, सुझावों की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत की जा चुकी है ।

(२) सम्मेलन का कोई विशेष सुझाव नहीं था । कुछ सुझाव तो ऐसे हैं जिन पर पहिले ही कार्यवाही की जा चुकी है और कुछ पर कार्यवाही की जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट संख्या १ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : वे कौन से सुझाव थे जिन पर कार्यवाही की जा रही थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जैसे निकासी के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा गया, सलाहकार समिति बन चुकी है, स्टेट ट्रेडिंग पर विचार चल रहा है, सहकारी समितियों की जानकारी कर ली है ।

श्री मुरलीधर व्यास : तो क्या जयपुर शहर में सहकारी समितियों के ज़रिये चीप ग्रेन शॉप्स बनाकर लोगों को खाद्यान्न दिया जाना था, समितियों को इसके लिए प्रोत्साहित किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक सहकारी समिति ऑलरेडी काम कर रही है । जयपुर शहर में उसके जरिये खाद्यान्न के डिस्ट्रिब्यूशन का काम हो रहा है ।

श्री मुरलीधर व्यास : सहकारी समिति के अतिरिक्त दूसरे लोग भी काम करते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वे सभी जगह काम कर रहे है । जहां सहकारी समिति बनाई हैं, उनके द्वारा काम हो रहा है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सुझाव दया गया था कि पर्मिट सिस्टम है, उसका कोई बेसिस होना चाहिए कि किस आधार पर पर्मिट दिया जाय । व्यक्तिगत मुनाफे को प्रोत्साहित करने के लिए पर्मिट दिया जाता है, वह न दिया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसके लिए अर्ज करूं कि को-ऑपरेटिव बेसिस पर काम करते हैं, उनको प्रिफ्रेन्स दिया जाता ।

श्री मुरलीधर व्यास : एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में माल ले जाने के लिए पर्मिट दिया जाता है, उससे व्यक्ति विशेष को मुनाफा होने की गुंजाइश रहती है । इसलिए व्यक्ति को पर्मिट देने की प्रथा की जगह को-ऑपरेटिव सोसाइटी को पर्मिट दिया जाय, इस प्रकार का सुझाव दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मेरी जानकारी में नहीं है । मैं अर्ज करूंगा कि जो कन्ज्यूमर को-ऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उनको प्रिफ्रेन्स दिया जाता है । इस तरह की गवर्नमेंट की हिदायत है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार यह सही समझती है कि व्यक्ति विशेष को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अनाज ले जाने का पर्मिट न दिया जाय और को-ऑपरेटिव सोसाइटी को प्रधानता दी जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि हर क्षेत्र में को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रधानता देने की बात है । को-ऑपरेटिव सोसाइटी होती है तो उसे प्रधानता दी जाती है ।

श्री मुरलीधर व्यास : हर क्षेत्र में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : किस कोऑपरेटिव सोसाइटी

Page No 11

(श्री अध्यक्ष)

ने दर्ख्वास्त दी और किसे पर्मिट नहीं मिला ? जहां तक उसूल का सवाल है, वे कहते हैं कि प्राथमिकता दी जाती है। आपकी शिकायत किसके लिए है, वह बताये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जयपुर के मर्चेन्ट्स ने एसोसियेशन बना रखी है, उसको नहीं देते हैं। उन्होंने एप्रोच किया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : They should make a distinction between the merchants association and a cooperative Society.

श्री अध्यक्ष : आप निश्चित तौर पर पूछें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अजमेर में नहीं दिया है। डिप्रेस्ड क्लास की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनको नहीं दिया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने हिदायत दी है। जोधपुर और बीकानेर में मैं पर्सनली गया हूँ, वहां आर्गनाइज़ कराके आया हूं, यदि आप बतायेंगे तो।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने जो हिदायत दी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को पर्मिट दी जाय। क्या आपने इसके स्टेटिसटिक्स कलेक्टरों से लिये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया है कि अगर दरख्वास्त आती है तो प्रिफ्रेन्स दिया जाता है। अगर आप कोई बतायें तो मैं जांच कर लूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा कि सोसाइटीज़ हैं उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। व्यक्तिगत लोगों को पर्मिट न देकर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनको प्रधानता मिलनी चाहिए, ऐसी कोई सरकार की नीति है क्या ? अगर नीति है तो आप कह दीजिये।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

भांडारेज से उकाली तक कच्ची सड़क

३२७. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) भांडारेज से उकाली तक जाने वाली कच्ची सड़क का निर्माण किस सन् में हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि बरसात में इस सड़क के कट कट कर बह जाने और जगह जगह खड्डे पड़ जाने से सरकार के हजारों रुपये बरबाद हो गये ?

(३) यदि हां तो सरकार कब तक यह सड़क पक्की बनायेगी ?

मन्त्री सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) इस विभाग द्वारा कोई कच्ची सड़क नहीं बनाई गई।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) कार्य चालू है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

डिग्गी ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव

३२८. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल

(डॉ० चन्द्रकला)

बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्र निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) डिग्गी ग्राम पंचायत के सरपंची का चुनाव पहले कब हुआ था ? उसके बाद अब तक सरपंच का चुनाव नहीं होने का क्या कारण है ?

(२) क्या यह सच है कि सरपंच के चुनाव की तारीखें मुकर्रर करने के बाद फिर चुनाव स्थगित कर दिया जाता है। यदि हां, तो क्यों ?

(३) अब सरकार उक्त ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव कब तक करा देगी।

उपमंत्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री दौलत राम सारण) : (१) पंचायत अधिनियम १९५३ के अन्तर्गत अप्रेल १९५४ में इस पंचायत की स्थापना के बाद सरपंच का चुनाव नहीं हुआ। इस पंचायत का निर्वाचन १०.५.५६ को हुआ। परन्तु अशांति हो जाने के कारण निर्वाचन नहीं हो सका। इसके पश्चात भी दिनांक आठ बार निश्चित हुए परन्तु निर्वाचन नहीं हुआ।

(२) जी हां। अशांति आदि कई कारणों से चुनाव स्थगित करना आवश्यक हो जाता है।

(३) इस पंचायत की अवधि २२.६.५९ को समाप्त हो रही है। अतः इस दिनांक तक पूरी पंचायत का निर्वाचन करा दिया जावेगा। अवधि समाप्त होने में छः माह से कम समय रह गया है अतः अब सरपंच के रिक्त स्थान का निर्वाचन नहीं हो सकता।

डॉ० चन्द्रकला : सरपंच जिसको ५६ में बनाया गया वह सरपंच का काम कबसे कर रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री): यह जवाब दिया गया है कि सरपंच का चुनाव हुआ हीनहीं है फिर बनाया कैसे ?

डॉ० चन्द्रकला : ५६ से नहीं होगा लेकिन ४७ से बारबार वह बना हुआ है।

श्री दौलतराम सारण : जो लोग नामजद किये गये है समय समय पर, वे कार्य कर रहे हैं।

डॉ० चन्द्रकला : एक ही सज्जन को बार बार नामजद करने का क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : इनको २५–६–५८ को नामजद किया गया है और २५–१२–५८ को समय समाप्त हो चुका है।

डॉ० चन्द्रकला : मैंने समय नहीं पूछा है। मैं यह जानना चाहती हूं कि एक ही व्यक्ति को क्यों बार बार नामजद किया जा रहा है ?

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास यह जानकारी नहीं है कि एक ही व्यक्ति को क्यों बार बार नामजद किया गया है लेकिन मेरी यह जानकारी है कि २५–६–५८ को इनको नामजद किया गया था और २५–१२–५८ को उनका समय समाप्त हो चुका है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : इससे पहले इस पंचायत के लिये किस को नामजद किया गया था।

Page No 13

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

नगरपालिका मालपुरा

३२६. रावराजा श्री सरदारसिंह (श्री श्रीभानसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) नगरपालिका मालपुरा की सालाना आमदनी कितनी और खर्च कितना है और क्या क्या टैक्स पालिका द्वारा लगा रखे हैं?

(२) क्या यह सही है कि टौंक डिस्ट्रिक्ट के कस्बों को सुन्दर बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

मंत्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री बद्री-प्रसाद गुप्ता) : (१) १६५७-५८ की आमदनी ५६७११ रु० १० आने और खर्च ३८४७२ रु० है। पालिका द्वारा १ टाल टैक्स, २ व्हीकल टैक्स और चूंगी टैक्स लगा रखे है। (२) जी नहीं।

राजस्थान नहर के मुख्य अभियन्ता का कार्यालय

३३०. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) राजस्थान नहर के मुख्य अभियन्ता का कार्यालय इस समय कहां पर स्थित है।

(२) क्या सरकार इस कार्यालय को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बीकानेर में स्थानान्तरित करना उचित समझती है?

(३) क्या यह सही है कि उक्त कार्यालय हेतु बीकानेर महाराजा ने जूनागढ़ देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा है?

उपमंत्री सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई): (१) इस समय राजस्थान नहर के मुख्य अभियन्ता का कार्यालय जयपुर में है।

(२) नहीं। मुख्य अभियन्ता का कार्यालय प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से ही जयपुर में रखा गया है।

(३) बीकानेर महाराजा की ओर से इस कार्यालय हेतु जूनागढ़ देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लालसोट कस्बे में परकोटे की तामीर

३३१. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट): क्या स्वायत्त शासन मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या लालसोट कस्बे में मोटर स्टेन्ड की ओर जाने वाले आम बाजार के कुंए के रास्ते को रोक कर कस्तूरचन्द केसर लाल बैनाडा ने बिना नगरपालिका की आज्ञा के कोई परकोटा तैयार किया है?

(२) क्या उस पर नगरपालिका ने कोई आपत्ति की? यदि हां, तो उसके प्रति कोई जुर्म बनता है? और बनता है तो उस अपराध से वह मुक्त क्यों हैं?

(३) क्या उस कुंए के रास्ते की जमीन पर से परकोटा दूर किया जायगा?

(४) यदि किया जायगा, तो कब तक?

मंत्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री बद्री-प्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां।

(२) जी हां, बोर्ड द्वारा कार्यवाही जारी है।

(३) प्रश्न विचाराधीन है।

(४) प्रश्न विचाराधीन है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बोर्ड के अख्त्यार की बात है विचार कर रहे हैं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): सक्रिय विचार कब होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जल्दी ही।

प्रश्न संख्या ३३२

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष नगरपालिका चाकसू का मासिक भत्ता

३३३. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लाल-सोट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) चाकसू नगरपालिका के भूतपूर्व अध्यक्ष ने नागरपालिका के कोष से कितना मासिक भत्ता कितने माह तक लिया ?

(२) क्या उक्त भत्ता डाइरेक्टर, लोकल बॉडीज़ या सरकार से स्वीकार कराके लिया गया था ?

(३) अगर नहीं, तो इस रकम की वापिस वसूली की क्या कार्यवाही की गई।

मंत्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री बद्री-प्रसाद गुप्ता): (१) ५० रु० माहवार का भत्ता दिनांक ५–२–५८ से ३१–५–५८ तक।

(२) नगरपालिका ने अपने बजट में अध्यक्ष को भत्ता देने हेतु ५० रु० माहवार का प्रावधान किया था और उसी प्रावधान के अनुसार बगैर स्वीकृति के ही प्राप्त कर लिया गया। सरकार ने अपने पत्र क्रमांक ६६७६ एफ. ए. १६४: एल. एस. जी. ५८ दिनांक ११–४–५८ द्वारा अध्यक्ष को भत्ता देने हेतु ३० रु० माहवार की स्वीकृति प्रदान की है।

(३) भूतपूर्व अध्यक्ष ने जो ज्यादा रकम प्राप्त करली है उसकी वसूली की नियमानुसार, प्रशासक द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

टोपीदार बंदूकों के लाइसेन्स

३३४. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि टोपीदार बन्दूकों के लाइसेन्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हैडक्वार्टर पर इश्यु करने के कारण जनता को काफी परेशानी होती है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार यह लाइसेन्स पुलिस स्टेशन पर ही देने का विचार रखती है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) टोपीदार बंदूकों के लाइसेन्स भारतीय

Page No 15

(श्री रामकिशोर व्यास)

शस्त्र अधिनियम के अनुसार दिये जाते है। इस अधिनियम के अनुसार लाइसेन्स देने का अधिकार जिलाधीश को ही है। यह सही है कि जो जिला हैडक्वार्टर से दूर रहते हैं उनको आने में कष्ट अवश्य होता है लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति वहां जावे। लाइसेन्स प्राप्त करने वालों को चाहिये कि आवेदन पत्र लिखकर डाक द्वारा जिलाधीश के पास भेजें। आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात लाइसेन्स उनके पास भेज दिया जायगा और परेशानी कम हो जायगी।

(३) उपरोक्त तरीके से परेशानी का प्रश्न नहीं रहता। थाने से लाइसेन्स देने का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि यह विषय भारत सरकार का है और भारतीय शस्त्र अधिनियम के अनुसार जिलाधीश ही लाइसेन्स दे सकता है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या सरकार के यह ध्यान में है कि दरख्वास्तें डाक से भेजने पर लाइसेन्स नहीं दिये जाते हैं और लोगों को बंदूक लेकर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर बुलाया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो लोग बंदूक दिखाना चाहें वे दिखा सकते हैं वरना थाने में दिखा सकते है।

श्री लक्ष्मीचन्द : उनको डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर ही बंदूक दिखाने के लिये बुलाया जाता है।

श्री रामकिशोर व्यास : दुबारा हिदायत जारी कर देंगे कि थाने पर भी दिखाई जा सकती है।

श्री सम्पतराज (अकलेरा): दरख्वास्त डाक से भेजी जाती है तो पैसा कहां जमा होगा।

श्री रामकिशोर व्यास : मनीआॅर्डर से भेजा जा सकता है।

श्री सम्पतराज : मनीआॅर्डर से भेजते हैं तो लेते नहीं है।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : क्या आपके ध्यान में यह भी है कि जब तक पीछे नहीं घूमते हैं तब तक कोई पूछता नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुनासिब समझें तो भेजें नहीं तो नहीं भेजें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर शहर) : टोपीदार बंदूकों में कौनसी टोपियां लगाते हैं ?

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : चार आने की फीस जमा कराने के लिए हरेक लाइसेन्सदार को कलेक्टर के हैड क्वार्टर पर जाना पड़ेगा, प्रशासनिक दृष्टि से ऐसा किया जाय कि तहसील में या पंचायत में फीस जमा करादी जाय और सारे एरिया के लाइसेन्स सरपंच करवाले।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी कहते हैं कि डाक से भेज सकते हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : डाक से भेजने पर लेते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये मंत्रीजी हिदायत कर देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या ३०३ बंदूक भी टोपीदार में आती है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

Page No 16

घरी बजना (बयाना) में आयुर्वेदिक औषधालय

३३५. **श्री श्रीभानसिंह** :(बयाना) Will the Minister for Medical and Public Health be pleased to state:-

1. Did the District Development Committee, Bharatpur sanction Ayurvedic Dispensary for Ghari Bajna in Bayana Tehsil ?

2. If so, has it been opened and a viadya sent to that place ? If not, why ?

उपमंत्री स्वास्थ्य विभाग (श्री भीखाभाई): (१) जी हां।

(२) चूंकि अभी तक वहां औषधालय चालू नहीं हुआ इसलिये वैद्य भेजने का प्रश्न नहीं उठता ।

डॉ० **बहादुरसिंह** (धौलपुर): विकास समिति रिकमन्ड करती है उसके कितने समय बाद खोलते है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री): तीन साल से रिकेमन्डेशन आई थी लेकिन नम्बरवार खोलते हैं।

३३६. **श्री रामनारायण,वर्मा** (पीपलदा) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम आटोन तहसील बड़ोद, जिला कोटा में गत रबी की फसल के समय बिना पूर्व सूचना के ही नहर की खुदाई आरम्भ करदी थी।

(२) क्या इस खुदाई में किसानों की फसल उजाड़ दी गई थी ?

(३) क्या तत्कालीन तहसीलदार, बड़ोद की आज्ञा से हल्के के पटवारी एवं ग्रामवासियों ने उक्त फसल की पैदावार का अनुमान प्रति बीघा ४ मन अलसी तथा ५ मन गेहूँ लगाया था ?

(४) क्या यह भी सही है कि किसानों को हुई हानि की पूर्ति हेतु चम्बल विभाग उन्हें ३० रूपये फी बीघा दे रहा है ?

(५) क्या यह भी सत्य है कि उक्त रकम लेने से किसानों ने इन्कार कर दिया है ?

(६) यदि हां, तो क्या सरकार आटोन के किसानों को उचित मुआवज़ा देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह रकम कब तक दे दी जायगी।

उपमंत्री सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई): (१) नहीं, पूर्व सूचना रबी की फसल बोने के पहले ही दे दी थी।

(२) बावजूद पूर्व सूचना के बोई हुई फसल का बंटवाना, नहर का कार्य प्रोग्राम के अनुसार खत्म करने के लिए अनिवार्य था।

(३) इस विभाग को ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(४) हां।

(५) इस विभाग को ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(६) जो मुआवजा दिया जा रहा वह उचित ही है।

३३७. **श्री रामेश्वरदयाल** (कोटा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या कोटा नगरपालिका की सीमा में हाल ही में मिलाये गये ग्रामों को म्युनिसिपेलिटी में प्रतिनिधित्व देने के लिये सरकार विचार कर रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) जी हां। आगामी चुनाव होने में चार माह बाकी हैं। उस समय प्रतिनिधित्व दिया जावेगा।

• **श्री रामेश्वरदयाल** : इन गांवों को मिलाये हुए तीन चार महीने हो गये हैं और मैं समझता हूं चुनाव होकर बोर्ड बनने में अभी ५–६ महीने लग जायेंगे। तो उन गांवों वालों को प्रतिनिधित्व के अभाव में म्युनिसिपल मामलों में काफी परेशानी उठानी पड़ती है, तो क्या सरकार ५–६ महीनों तक, जब तक चुनाव नहीं होता, वहां से किसी को मनोनीत करना चाहती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नॉमीनेशन कानून के अनुसार हो नहीं सकता।

श्री रामेश्वरदयाल : सरकार ऐसा कर सकती है कि ग्राम पंचायत में चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनको प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। वहां के पंच और सरपंच चुने हुए हैं उनको प्रतिनिधित्व नॉमिनेशन द्वारा दिया जा सकता है, ऐसा प्रोविज़न भी मौजूद है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा प्रोविज़न मौजूद नहीं होगा। एक बार सदस्यों की जो संख्या मुकर्रर हो जाती है उतनी ही रहती है, घटाना बढ़ाना सम्भव नहीं है।

श्री रामेश्वर दयाल : स्पेशल सरकम्सटान्सेज़ में ऐसा करने की पॉवर है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कानून देखा है उसके अनुसार नहीं हो सकता।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): क्या ये गांव वहां की जनता को पूछ कर मिलाये गये थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑब्जेक्शन्स मांगे थे।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : जो ऑब्जेक्शन्स आये थे उन पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनको देखने के बाद निर्णय लिया गया।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या आपने उनको निर्णय लेने के बाद सूचना दी थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक बार गजेट नोटिफिकेशन होता है, ऑब्जेक्शन इन्वाइट करते हैं, दुबारा फिर फैसला होने पर छपता है।

बांदीकुई-बसवा सड़क पर पुल निर्माण का कार्य

३३८. **श्री बी. एन. जोशी** (बांदीकुई): Will the Minister for Public works be pleased to state :—

(a) What was the initial target date for the completion of the cross drainage works between miles 3 to 8 on the Bandikui-Baswa Road ?

(b) How many of the cross drainage works still remain to be cons-

(श्री बी. एन. जोशी)

tructed on this portion of the road, and why ?

(c) Is it a fact that the construction of a culvert or bridge over nullah Gullana has not been taken up and even the tenders have not so far been invited for this work ?

(d) Can this road be used by traffic without construction the work referred to in part (c) of this question ?

(e) Will the Government give necessary instructions for completing it before the next monsoon sets in ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (a) 6th November, 1958.

(b) 4 due to paucity of funds.

(c) yes.

(d) yes.

(e) Not practicable.

श्री बी. एन. जोशी : Is it a fact that the Government is constructing the present road contrary to the previous decision and contrary to the Verma-Adityendra award ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह सड़क सब पूरी हो चुकी है।

श्री बिश्वम्भरनाथ जोशी : I want one clarification. Whether this construction आपने फर्माया कि पूरी हो चुकी हैं। has been done contrary to the decision of the Govt. and contrary to the Verma-Adityendra Award which was accepted by the Government previously.

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, ऐसा नहीं था, उस रोड के अलाइनमेंट में कई दिनों से झगड़े चल रहे थे, जिनकी वजह से चार पांच बार अलाइनमेंट बदला और वही ओरिजिनल रखो जिसका अर्थ वर्क हो चुका था। उनको अगर छोड़ें तो गवर्नमेंट को २०, २५ हजार रुपये का नुकसान होता था। एक्वीज़िशन के कई झगड़े चल रहे थे। तो उन सब झगड़ों को एक तरफ छोड़ कर जिस पर अर्थ वर्क २० हजार का हुआ था उसी पर सड़क निकाल दी, न वहां किसी प्रकार के एक्विजिशन के झगड़े हुए और न किसी को असंतोष हुआ। वह सड़क चल रही है और सबको उससे संतोष है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : क्या यह सही नहीं है कि उस अर्थ वर्क के हो जाने के बाद राजस्थान सरकार ने डिसिज़न लिया था कि वर्मा आदित्येन्द्र अवार्ड को स्वीकार किया जाय और इस हाउस की फ्लोर पर एक प्रश्न के उत्तर में गवर्नमेंट की ओर से एश्योरेंस दिया गया था कि....The Government has accepted that award and shall implement that award.

श्री नाथूराम मिर्धा : वर्मा-आदित्येन्द्र अवार्ड भी क्यों बना, इसके लिये जैसा कि मैंने अर्ज किया कई झगड़े थे, फिर इसके बाद में उन झगड़ों को सुलझाने के लिये उनकी पंचायत को बीच में डाला था, पर उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। ४०-५० सिंचाई के खेत, चाई जमीन इस सड़क

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में आ रही थी। डेढ़ साल अवार्ड को किये हो गया था, फिर भी एक भी केस फाइनेलाइज़ नहीं हो पाया था। उधर एक्विज़िशन से किसानों को नुकसान हो रहा था और इधर गवर्नमेंट को बीस हजार का नुकसान हो रहा था। इसलिये हमने देखा कि जिस पर गवर्नमेंट का २० हजार का अर्थ वर्क का काम शुरू हुआ है उसी पर सड़क निकालदें और उसी पर सड़क निकाल दी गई, बड़ी आसानी से सड़क निकल गई, किसी प्रकार का झगड़ा सामने नहीं आया और उससे सब को संतोष है।

विश्वम्भरनाथ जोशी : Mr. Speaker, Sir, The Hon'ble Minister is avoiding a plain reply to a plain question.

मेरा निवेश्चन यह था कि उस अर्थ वर्क के हो जाने के बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने वर्मा आदित्येन्द्र अवार्ड को स्वीकार किया था और उसी अवार्ड के माफिक करने के लिये गवर्नमेंट ने अपने आपको बाउन्ड माना था।

श्री अध्यक्ष : इनका उत्तर स्पष्ट है कि अवार्ड देने के बाद दिक्कतें आई थीं, इसके लिये हमने ऐसा किया।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : The question was that whether an assurance was given by the Hon'ble Minister to stick to that alignment as given in the award of Mr Verma Adityendra award and that was the question.

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे तो एश्योरेंस दिये जाने की जानकारी है नहीं, पर मेरे सामने यह मामला आया तो ठीक ढंग से इसको निबटाया कि गवर्नमेंट का २० हजार रुपया अर्थ वर्क पर लगा हुआ है वह बेकार नहीं जाय और एक्विजिशन के टंटे जो दो, तीन साल से चल रहे थे वे भी रास्ते में न आयें। इन सब बातों को ध्यान में रख कर सहूलियत के साथ इसको निबटाया। अगर एश्योरेंस दिया गया है तो गवर्नमेंट ही एश्योरेंस देती है और कोई दिक्कत सामने आने पर कोई रास्ता निकाल कर काम करने का गवर्नमेंट को अधिकार है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती हो ऐसी बात तो नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : I think, Mr. Speaker, this is no reply. The Hon'ble Minister cannot avoid the responsibility.

श्री अध्यक्ष : He says that the Government has changed that even after that assurance was given.

श्री नाथूराम मिर्धा : We have thought, it fit to change according to the circumstances.

श्री पी० के० चौधरी : But he has said.......

श्री अध्यक्ष : He has already said about the change.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : क्या यह सही नहीं है कि आपके प्रेडेसेशर श्री रामचन्द्रसिंह जी चौधरी स्वयं सड़क का मौका देखने के लिये मौके पर गये थे और जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि कई कम्प्लेन्ट्स थीं तो उन कम्प्लेन्ट्स को

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

सुनने और देखने के लिये आन दी स्पोट गये थे और वहां पूरी तरह से एन्क्वायरी करने के बाद मौका देखने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट के डिसिज़न को कन्फर्म किया था कि वर्मा आदित्येन्द्र अवार्ड के माफिक ही किया जायगा ?...

श्री नाथूराम मिर्धा : यह ठीक बात है, रामचन्द्रजी मौके पर गये थे उनका आॅर्डर भी फाइल पर है, फिर भी १५० केसेज़ में से एक भी केस फाइनेलाइज़ नहीं हुआ, डेढ़ साल तक एक्विजिशन के झगड़े चलते रहे, डेढ़ साल में एक फैसला मौके पर दिया और फिर भी उसका एम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ। तो ऐसी सूरत में उससे सरकार और प्रजा दोनों को नुकसान था इस लिये मैंने चेंज किया। अब वहां सड़क बन गई है और लोग चलने लग गये हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करें कि जो डिसिज़न हुआ था उनके प्रेडेसेसर का, जो बाद में चेंज किया, उसके लिये वे अपने आपकी रेस्पोन्सिबिलिटी अवाइड कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने बताया न।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने बताया न ५० जनों की सिंचाई की जमीन में से, चाई जमीन में से सड़क निकल रही थी। पर इस केस में एक भी चाई जमीन सड़क में नहीं आई है। सारी सड़क बारानी लैंड में से निकली है। बसवा टाउन को कनेक्ट करने का सवाल था वह भी हमने लिंक रोड से कनेक्ट कर दिया है। माननीय सदस्य को इससे ज्यादा संतोष होना चाहिये कि ४ साल से उलझा हुआ मामला पड़ा था, वह ठीक हो गया।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : क्या यह सही नहीं है कि जिधर हो कर सड़क अभी बनाई गई है वह पहले से ही सरकार के ध्यान में था और नक्शों में मौजूद था, बारानी जमीन में जाती है यह भी सरकार के ध्यान में था। फिर यह दूसरा प्लान वर्क आउट हो कर मिनिस्टर महोदय की जानकारी में लाने की बात है, इसमें ज्यादा चाई जमीन जायगी पर यह रास्ता म्युनिसिपल टाउन और तहसील हैड क्वार्टर के नजदीक हो कर जाता है, इस पर वर्मा आदित्येन्द्र अवार्ड का तय हुआ था। यह सब हो जाने के बाद में मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन से नये फैक्टर्स पैदा हो गये थे, जो कि बाद में ध्यान में आये हैं जिनके कारण वह डिसिज़न बदलना पड़ा।

श्री अध्यक्ष : बता दिया न इन्होंने।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह तो गवर्नमेंट के पहले ही ध्यान में था, फिर बाद में ऐसी क्या नई चीज़ पैदा हो गई कि वह डिसिज़न चेंज करने की ज़रूरत पड़ी ?

श्री अध्यक्ष : इन फैक्ट्र्स को इन्होंने अपने प्रेडेसेसर से ज्यादा कन्सीडर किया।

श्री बी. एन. जोशी : My second question is that I wanted to know whether the Hon. Minister does not consider it necessary to implement the categorical assurance given on behalf of the Government on the floor of this House.

Page No 21

श्री अध्यक्ष : It does not suit him.

श्री बी. एन. जोशी : It is not a good standard of reply Sir.

श्री अध्यक्ष : It is a question of opinion, how we interpret it.

श्री लक्ष्मी चन्द ।

जसवन्तपुरा तहसील में १६४६-५० में खोली गई चीप ग्रेन शॉप

३३६. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचौर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जिला जालोर की जसवन्तपुरा तहसील में चीप ग्रेन शॉप सन् १६४६-५० में खोली गई थीं और एजेन्ट मुकर्रर किये गये थे ?

(२) क्या यह सत्य है कि उनके कमीशन का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उपमंत्री खाद्य विभाग (श्री खिबचन्द धारीवाल) : (१) जी हां, सर्व श्री संतोषचन्द भंवरलाल १६४६-५० में चीप ग्रेन शॉप के एजेंट मुकर्रर किये गये थे ।

(२) पार्टी के क्लेम की विभागीय जांच कराई गई । जांच से ३३६१॥) के क्लेम में से २५५६॥) की रकम देनी निकलती हैं । इस रकम के भुगतान से पूर्व पार्टी से पुराना क्लेम होने के कारण आवश्यक इन्डेम्निटी बोन्ड मांगा गया है । जिसके प्राप्त होने पर तुरन्त भुगतान करा दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री अनोपसिंह ।

कान्स्टेबल सेवाराम की इन्श्योरेंस पालिसी

३४०. **श्री अनोपसिंह** (बालोतरा) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या रेलवे पुलिस कान्स्टेबिल श्री सेवाराम साकिन मेली, तहसील सिवाना (बाडमेर) की सरकारी सेवा में ४-१०-५७ को मृत्यु हुई ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त कान्स्टेबिल की बीमा पालिसी, जो उसकी पत्नी के नाम पर मनोनीत थी, की रकम अभीं तक नहीं दी गई ? यदि हां, तो अब कब तक दे दी जावेगी ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जब वह अवकाश पर था तब उसकी मृत्यु हुई ।

(२) बीमा की रकम रु० ७०६ मृत की पत्नी को दे दी गई है ।

श्री अनोपसिंह : इस तरह की देर हो जाने का क्या कारण है । आयन्दा इस तरह के किसी केस में देरी नहीं हो इसके लिये गवर्नमेंट अपने प्रोसीज़र में रद्दोबदल करके प्रावधान क्यों नहीं रखती ?

श्री राम किशोर व्यास : इसमें देर लगने का कारण यह है कि कोई मर जाता है तो उसके पीछे हकदार रीयल सक्सेसर का तय करने में देर लगती है ।

श्री अनोपसिंह : यह आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिये कि आपके डिपार्टमेंट के आदमी हैं उनका हरेशमेंट होता है, तो इसके लिये गवर्नमेंट जिम्मेदार है । अपनी जिम्मे-

(श्री अनोपसिंह)

दारी समझ कर गवर्नमेंट को अपने प्रोसीज़र में इस तरह का प्रावधान करना चाहिये कि जल्दी से जल्दी भुगतान हो जाय।

श्री राम किशोर व्यास : गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी समझती है पर यह पुलिस से ताल्लुक नहीं रखता था, इसका इन्श्योरेंस डिपार्टमेंट से ताल्लुक था।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मी चन्द।

गांव चितलवाना में प्राइमरी हैल्थ सेंटर

३४१. श्री लक्ष्मी चन्द (सांचौर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या जिला जालोर की सांचोर तहसील के गांव चितलवाना में प्राइमरी हैल्थ सेंटर खोलने के आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो कब और वहां पर स्टाफ पहुँचा या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उपमंत्री स्वास्थ्य विभाग (श्री भीखा भाई) : जी हां, ये आदेश अगस्त '५८ में जारी कियेगये थे। अभी वहां केवल एक द्वितीय श्रेणी का कम्पाउन्डर ही कार्य कर रहा है व द्वितीय श्रेणी के डाक्टर श्री हरवंशलाल गुलेटीको यहां भेजने का आदेश दिनांक ४।३।५९ को जारी कर दिया गया है, शेष स्टाफ उपलब्ध न होने के कारण नहीं भेजा जा सका है परन्तु डी. एम. एच. ओ. जालोर को जल्दी से जल्दी स्टाफ भेजने के लिये संचालक, स्वास्थ्य विभाग ने लिख दिया है।

किशनगढ़ वाटर वर्क्स

३४२. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(अ) किशनगढ़ वाटर वर्क्स जनता को कब तक पानी सप्लाई करना शुरू कर देगा ?

(ब) क्या किशनगढ़ वाटर वर्क्स को इस काम के लिये बिजली के पावर की जो आवश्यकता होगी, उसके लिए व्यवस्था कर ली गई है ?

(स) यदि हां, तो क्या व्यवस्था की गई है ?

(ड) यदि नहीं तो समय पर फिर पानी किस प्रकार दिया जा सकेगा ?

मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा) : (अ) लगभग एक वर्ष में पानी सप्लाई होने की आशा है।

(ब) की जा रही है।

(स) विद्युत बोर्ड को उचित मात्रा में बिजली व्यवस्था के लिए कहा गया हैं।

(ड) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पुरुषोत्तमलाल : क्या उन्होंने बिजली देना मंजूर कर लिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, इन्तजाम करने को कहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

तहसील टोडारायसिंह में प्रसूति गृह

३४३. श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा सु०) क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का

(श्री रामनारायण वर्मा)

उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(१) तहसील टोडारायसिंह में प्रसूति गृह किस स्थान पर खोला जा रहा है ?

(२) क्या यह ग्राम जहां प्रसूति गृह खोला जा रहा है तहसील के केन्द्र में न होकर मालपुरा तहसील व टोडारायसिंह तहसील की सीमा पर है ?

(३) यदि हां, तो क्या उक्त तहसील की जनता इससे पूरा पूरा लाभ उठा सकेगी ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

उपमंत्री स्वास्थ्य विभाग (श्री भीखा भाई) :(१) कहीं नहीं ।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री रामनारायण वर्मा : क्या सरकार आवश्यक नहीं समझती ?

मन्त्री स्वास्थ्य विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : हमारे प्लान में नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर): क्या इससे सरकारका मतलब यह है कि कहीं भी प्रसूति गृह खोलने की सरकार की योजना नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्राइमरी हैल्थ सेन्टर पर खोलते हैं ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या प्रसूति गृह का सम्बन्ध प्राइमरी हैल्थ सेन्टर से तो नही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

कोटा सिंचाई बांध से सिंचाई की योजना

३४४. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कोटा सिंचाई बांध से कौन से सन् तक सिंचाई शुरू हो जावेगी और कितने एकड़ भूमि सींची जावेगी ?

(२) क्या बारहों मास काश्तकार नहरों से पानी प्राप्त करते रहेंगे ?

(३) इस बांध व नहरों के निर्माण में अब तक कितना खर्च हो गया है और कितना और खर्च होना बाकी है ?

(४) चम्बल बांध तथा नहरों पर कितने कान्ट्रेक्टर्स काम कर रहे हैं ? क्या भारत सेवक समाज के भी कान्ट्रेक्टर है ? यदि हां तो इसमें अब तक कितने हजार रुपयों का ठेका दिया जा चुका है तथा कितना काम किया गया है ?

(५) क्या यह सही है कि बहुत से ठेकेदारों ने मजदूरों का पेमेन्ट नहीं किया है, तथा कुछ समय पर पेमेन्ट नहीं करते ?

उपमंत्री सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : (१) कोटा सिंचाई बांध से सन् १९५९ में सिंचाई शुरू करने की आशा है । संपूर्ण विकास के बाद राजस्थान व मध्य प्रदेश की सात सात लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होगी ।

(२) जी हां ।

(३) इस बांध व नहरों के निर्माण में

(श्री भीखाभाई)

३१.१.५६ तक ८०३.५८ लाख खर्च हो चुके हैं और ८४४.५० लाख और खर्च होना बाकी है।

(४) इस कार्य पर राजस्थान में करीब २०० ठेकेदार काम कर रहे हैं जिसमें भारत सेवक समाज भी शामिल है। भारत सेवक समाज को अब तक करीबन ७,५७,०००) रुपयों का ठेका दिया गया है जिसमें से उन्होंने करीबन ५,५८,०००) रुपयों का कार्य कर लिया है।

(५) ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब आप इस नहर को प्रारम्भ करेंगे तो कितने एरिया में सिंचाई होगी ?

मंत्री सिंचाई विभाग (श्री रामकिशोर व्यास) : बहुत कम ऐरिया में होगी ?

श्री दयाकृष्ण विजय : कितने कम एरिया में ?

श्री रामकिशोर व्यास : दो हजार के करीब।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या इसके आंकड़े तैयार किये गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : आंकड़े हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : लेकिन आपने बताये तो नहीं हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने बताया है। ३१ नवम्बर तक पानी आवेगा उसमें खरीफ की, फसल होगी।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने बताया कि कुछ ही एरिया में होगा। जिन स्थानों पर होगी तो वहां पर नहरें भी खुद चुकी हैं या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेन केनाल बनी है और बनती जावेगी।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (ज़ौहरी बाजार जयपुर) : क्या यह सही है कि इर्री-गेशन डिपार्टमेन्ट्स से काम के ठेके जो एन्रो-ल्ड ठेकेदार्स हैं उन्हीं को दिये जाते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : लिस्ट पर हैं उनको देते है और भी को-ऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनको भी देते हैं।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि भारत सेवक समाज है वह उसमें एन्रोल्ड नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने बताया कि को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती है और भी हो सकती हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यदि कोई को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ ठेका लेना चाहे तो बिना एन्रोलमेन्ट के ही ठेका दे देंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां। को-ऑपरेटिव सोसाइटी को दे सकते हैं।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि भारत सेवक समाज ने कॉन्ट्रोक्ट लेने से पहले अर्नेस्ट मनी नहीं जमा कराई जो कि जमा करानी चाहिये थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से माफ थी

श्री रामेश्वर दयाल (कोटा) : डिस्ट्रिब्युटरी नहरें कब तक बन जावेंगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो हर साल का प्रोग्राम है।

श्री रामेश्वर दयाल : कितने साल में हो जायगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : तीन चार साल में।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर शहर): भारत सेवक समाज जो काम करता है तो वह पैसा किसको मिलता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वे तो नो लास नो प्रॉफिट पर काम करते हैं मजदूरों को पैसा मिलता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भारत सेवक समाज ने चम्बल बांध का काम किया तो क्या चम्बल बांध के ऊपर जो इरीगेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं वे भी उनमें शामिल थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अन्दाज ही है आपका।

श्री दयाकृष्ण विजय : दूसरे ठेकेदार कमाते है तो फिर भारत सेवक समाज को भी लाभ होता है वह कहां जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : लेबर को दे देते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि भारत सेवक समाज कोटा की काफी शिकायतें हैं कि उसने मजदूरों को पेमेन्ट नहीं किया और वे शिकायतें अखबारों में प्रकाशित भी हुई हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसका जबाब उत्तर में आ गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसे काम भारत सेवक समाज को बिना सिक्योरिटी या अर्नेस्ट मनी लिये मुफ्त दे देने के लिए कहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : माफ़ किया है उससे।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार की जानकारी है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : हमारे पास सर्कुलर मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो काम भारत सेवक समाज को दिये गये उनमें कोई टेन्डर इन्वाइट नहीं किये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : एस्टीमेंटेड कोस्ट पर देते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो और भी सीरियस बात है। सात आठ लाख के काम के टेन्डर्स इन्वाइट करने के ऊपर चार लाख के भी आ सकते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : इर्रेगुलरिटी नहीं है। फिक्स्ड है, इतना काम करेंगे तो इतना मिलेगा। भारत सेवक समाज को भी यह दे सकते हैं और कोई दूसरा करे तो दूसरे को भी दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री अनोपसिंह।

समदड़ी ग्राम में पानी के नल लगाने की योजना

३४५. **श्री अनोपसिंह** (बालोटरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगें :*

(क) क्या समदड़ी ग्राम (जिला बाड़मेर) में पानी के नल लगाने की योजना में ग्राम पंचायत समदड़ी ने काफ़ी धन राशि लगाने का विचार किया है और सरकार से योजना की मदद के लिए प्रार्थना की है ?

(ख) सरकार ने इस योजना में कितनी सहायता देने का विचार किया है व कुल योजना में कितना खर्च होगा ?

(ग) क्या सरकारी इन्जीनियर्स ने योज़ना का सर्वे व एस्टीमेट किया है ? यदि हो, तो वह कितना है ?

(घ) कब तक यह योजना शुरू होकर समाप्त कर दी जायगी ?

मंत्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री बद्री-प्रसाद गुप्ता) : (क) बी. डी. ओ ने जान-कारी भेजी थी।

(ख) इस योजना पर कुल खर्चा १,६५ हजार रुपया होगा तथा सरकारी सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ग) इस योजना का सर्वे व एस्टीमेंट सहायक अभियंता कॉम्युनिटी ने किया है और वह १,६५ हजार रुपयो का है।

(घ) यह स्कीम विचाराधीन है।

श्री अनोपसिंह : क्या इस योजना पर खर्च होने वाली धन राशि देने का आश्वा-सन दिया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं। रूरल वाटर सप्लाई स्कीम है उसमें २।३ गवर्नमेंट देती है और १।३ पंचायत या लोकल कॉन्ट्रिब्यूशन होता है। वह एक जनरल स्कीम और सारे हिन्दुस्तान के लिए स्कीम है।

श्री अनोपसिंह : क्या यह बात सुझा दी गई है कि हम इतना दे सकते हैं और उनको इतना देना पड़ेगा? क्या एस्टीमेट लगा कर खर्चा करने के आदेश भी दे दिये गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले १॥ लाख की स्कीम आई थी बी. डी. ओ. से उसको इंजीनियर के पास भेज कर एस्टीमेट बनाया और अब आगे कार्यवाही चल रही है। हमें २।३ हिस्सा देने में कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अनोपसिंह : वहां पाइप लाइन की वजह से ही जितना विकास उस गांव का होना चाहिये वह रुका पड़ा हुआ है और जमीन अच्छी नीलामी बोली में जा सकती है जो रुकी पड़ी हुई। इसके बिना सारा विकास रुका पड़ा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १।३ आप गांव से करवाइये और २।३ गवर्नमेंट से मिल जावेगा।

श्री अनोपसिंह : वे तो देने के लिए तैयार हैं। आप फाइनेलाइज़ करके बता दीजिये कि आप कितना देंगें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १,६५ हजार की फाइनल स्कीम है।

ग्राम कैथुन तहसील लाडपुर के निवासियों को जंगल से लकड़ी देने की मनाही

३४६, **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा सु.) क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न की उत्तर देने की कृपा करेंगें :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा के निवासियों को निकस्थ डाढ़देवी के जंगल से हलकुली व जलाने की लकड़ी नहीं दी जाती है ?

(२) क्या यह भी सही है कि यहां के चमारों को चमड़ा रंगने के लिये धोकड़े की छाल उपलब्ध नहीं होती ?

(३) यदि हां, तो ग्राम कैथून की उक्त आवश्यकतायें कौन से जंगल से पूरी की जाती हैं ? वह जंगल कितनी दूर है ?

(४) क्या यह भी सही हैं कि कैथून निवासी दूर के जंगल से बहुत कम लकड़ी लाते हैं और फलस्वरूप निकट के जंगल में चोरियां होती हैं जिससे डाढ़देवी का जंगल उजड़ रहा है ?

(५) यदि हां तो क्या सरकार डाढ़देवी के जंगल की उचित ढ़ंग से कटाई एवं कैथून की जनता के उक्त कष्ट निवारणार्थ सक्रिय कदम उठायेगी ?

मंत्री वन विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) हलकुली की लकड़ी डाढ़देवी जंगल से नहीं दी जाती। सर बोझा सूखी जलाऊ लकड़ी दी जाती है।

(२) जी हां।

(३) हलकुली की लकड़ी दूसरे निकटस्थ जंगल से दी जाती है जो कैथून से लगभग ६.७ मील दूर है। चमड़ा रंगने के लिये धोकड़े की छाल के स्थान पर धोकड़े के पत्ते निकटस्थ जंगल से दिये जाते हैं।

(४) कैथून निवासी दूर के जंगलों से बहुत कम लकड़ी लाते हैं या नहीं उसकी सूचना नहीं है। निकटस्थ जंगल में चोरियां अवश्य होती हैं किन्तु कैथून निवासियों द्वारा ही होती है या दूसरों द्वारा इसकी जानकारी नहीं है। चोरियां अक्सर सर बोझ से लकड़ी लाने वालों द्वारा होती हैं। यह सही है कि ऐसी चोरियों से डाढ़देवी का जंगल काफी बरबाद हो गया है।

(५) जी हाँ।

श्री रामनारायण वर्मा : जब डाढदेवी के जंगल में ही वह लकड़ी मिल जाती है तो वह क्यों नहीं दी जाती।

श्री नाथुराम मिर्धा : दरख्तों की छाल काट काट कर सारे दरख्त खराब कर दिये हैं। जब छाल उतार ली जाती है तो दरख्त सूख जाते हैं इसलिये उनको कहा गया है कि रंगाई के काम के लिये पत्ते भी आते हैं वह ले लिये जायं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): जब कि पास ही में हलकुली की लकड़ी मौजूद है वैसी हालत में ५,७ मील दूरी पर जाने के लिये क्यों मजबूर किया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पास के जंगल में यह लकड़ी है नहीं इसलिये पांच सात मील पर जो जंगल है वह बताया गया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : डाढ़देवी के जंगल में इस प्रकार की लकड़ी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप कहते हैं, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : वह जंगल तो लाडपुरा तहसील में पड़ता है जब कि उसी तहसील में जंगल मौजूद है तो वहां क्यों नहीं लेने दिया जाता ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हलकुली की लकड़ी उस जंगल में है नहीं उसके लिये ६, ७ मील की दूरी पर जाना पड़ता है।

श्री रामचन्द्र (डग) : चमड़ा रंगने में जो पत्तियां काम में ली जाती हैं उन पर क्या टैक्स देना पड़ता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस समय तो मुफ्त में दे रहे हैं आगे की आगे देखी जायगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामचन्द्र : मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं दो रुपया फी गाड़ी टैक्स लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये।

डॉ० **बहादुरसिंह** (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, दो महत्वपूर्ण प्रश्न रह गये हैं जो खाद्य के सम्बन्ध में है उनके उत्तर दिलवाये जायं।

श्री अध्यक्ष : समय नहीं है, बजट पर वाद-विवाद होगा। श्री मूलचन्द डागा।

(प्रश्न काल में न लिये जाने वाले प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट नं० २ देखिये)

(स्थगित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट नं० ३ देखिये)

प्रश्न संख्या ३२४ के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : ऑन एपोइन्ट ऑफ प्रिविलेज़ सर, अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न संख्या ३२४ पूछा था, जिसके बारे में माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर देते हुए कहा था कि जिन जिन व्यक्तियों की अर्जियां १६५१ की थी उनको प्लाट्स अलाट किये गये। इसके पहले भी अर्बन इम्प्रूवमेंट के बारे में मैंने सवाल पूछा था और ५६–५७ तक के अलॉटमेंट की पूरी लिस्ट मांगी थी। उस लिस्ट के अन्दर अध्यक्ष महोदय, ७५,७६ ७७ पर जिनके नाम हैं श्री सुमेरनाथ गुर्ट, श्री समरथराज और श्री के. सी. सतसंगी। इनको जालूपुरा स्कीम में जमीन अलोट की गई है। उनकी अरजी १३।१।५६ की थी। इस प्रकार अधिकारियों द्वारा गलत सूचना मंत्री जी को दिया जाना और मंत्री जी द्वारा गलत सूचना सदन के समक्ष रखना यह प्रीविलेज़ का ब्रीच है। इस प्रकार पहले कई दफा हुआ है लेकिन इस समय तो मेरे पास लिस्ट मौजूद थी इसलिये यह ध्यान में आ गयी। अगर यह लिस्ट नहीं होती तो मैं भी सन्तोष खाकर बैठ जाता। ऐसी जो गलत सूचना दी गई है उसके लिये अध्यक्ष महोदय सीरियस व्यू लिया जाना चाहिये अतः माननीय मंत्री महोदय को यह आदेश दिये जायं कि वे इस सम्बन्ध में जानकारी करें और जिन सम्बन्धित अधिकारियों ने गलत

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सूचना दी है उनके खिलाफ़ कदम उठायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : I hope the Hon'ble Minister agrees to that.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : कुछ न कुछ तो कहिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (मंत्री स्वायत्त शासन विभाग) : मैं प्रश्न के उत्तर में कह चुका था यह कोई बड़ी गलती नहीं है, फिर भी यदि किसी प्रकार की गलती हुई है तो दुबारा देखूंगा ।

श्री अध्यक्ष : देखने का मतलब यही है कि इस पर उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री पी० के० चौधरी : He never says that he will take action.

श्री अध्यक्ष : It is always presumed even if he does not say.

श्री मूलचन्द डागा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बीस मिनिट पहले ही बोल चुके हैं ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य जिन्होंने प्रिविलेज़ का क्वेश्चन उठाया है वह इस तरह से लाइटली डिसकस नहीं किया जा सकता । अगर वास्तव में माननीय सदस्य पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज़ का सवाल उठाते हैं तो उसका जो प्रोसीज़र है उसके अनुसार कार्यवाही करनी होगी ।

श्री अध्यक्ष: The Hon'ble Member has himself suggested a course of action which the Government has accepted and the Hon'ble Member is satisfied.

१२.५ म० प०

आय-व्ययक भाषण पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा अपना भाषण पांच मिनिट में समाप्त करें ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष, आपका आदेश मुझे हुआ है कि मैं अपना भाषण पांच ही मिनिट में समाप्त कर दूँ । मैं कल बात यह कह रहा था कि हमारी लोकप्रिय सरकार छोटी छोटी गलतियों की शिकार हो चुकी है । मैंने बताया था कि प्रशासनिक मामलों में छोटी छोटी गलतियों का क्या असर होता है । इस बारे में बोलते हुए मैंने बताया था कि यदि एक जहाज में छोटा सा छेद हो जाता है तो वह सारी जहाज को डुबा देता है । बड़े बड़े काम छोटी छोटी गलतियों के हो जाने से हमें कितना नुकसान उठाना पड़ता है । इस बारे में, मैं आपका ध्यान, जो भाषण मिला है, उसके पेज ३० पर दिलाना चाहता हूं । इसका मतलब कोई भी समझ नहीं पाया । पेज तीस पर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है उस पर अध्यक्ष महोदय, आप प्रकाश डालेंगे ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Hon'ble the Finance Minister is not present, Sir.

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, पेज ३० पर जो भाषा है उसको आप जरा मुलाहिजा फरमाइये । रिहेब्लीटेशन और डिसप्लेसड पर्सन्स हैं वहां यह सेन्टेन्स है "Rehabilitation of Displaced Persons."

इसके आगे है "The displaced persons from West Pakistan have almost been settled by now. There are 3 Widows' Homes and two Infirmaries with the sanctioned strength of 900 and 925 respectively. Deserving students are given stipend and the expenditure chargeable to Revenue came financial assistance is given to the children and destitute widows..." अब आप इस सेन्टेन्स को देखेंगे इसकी ज्यादा व्याख्या श्री श्रीभानसिंह या श्री पी० के० चौधरी कर सकते हैं । मैं देखता हूं कि उनको मौका नहीं मिलेगा इसलिये अध्यक्ष महोदय आप ही बता दीजिये यह भाषा क्या है : "Deserving students are given stipend and the expenditure chargeable to Revenue came financial assistance is given to children and destitute widows from West Pakistan."

श्री अध्यक्ष : आप हिन्दी भाषण पढ़ लीजिये ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं क्षमा चाहता हूं मैंने हिन्दी नहीं की । मैं हिन्दी भाषण भी पढ़ लूंगा । लेकिन यह मैंने बतलाने की कोशिश की कि छोटी छोटी गलतियों के कारण, हमारी प्रशासनिक कमज़ोरियों के कारण, हमारी नैतिकता की कमी के कारण कितना नुकसान उठाना पड़ता है । राजस्थान के अन्दर जो कल्याणकारी राज्य की घोषणा करते हैं लेकिन इन घोषणाओं का प्रशासनिक कमजोरियों के कारण असर नहीं होता । इस सम्बन्ध में राजस्थान फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है जिसने अपने सजेशन दिये थे उसके पेज २३३ पर कहा है "The savings likely to result from a further reduction of class IV servants will not, however, be very significant, comparing to savings likely to accrue from reductions in the clerical and higher cadres which have of late years grown to very large proportions owing to the multiplication of the departments, top heavy organisation and the quality and insufficient training of personel." Then there is:—"Frequent transfers of the officers from one station to another and from one department to another involve a loss of effectiveness which is obvious though it cannot be measured in terms of money. All these things add to invisible cost of public services."

उसके बाद यहां के सब मेम्बर्स राजस्थान प्रशासन के बड़े बड़े उच्च अधिकारियों ने निर्णय दिया था:—

"The Committee therefore suggested during their discussions that reduction in the number of their present administrative units was a necessity which could not be delayed much

(श्री मूलचन्द डागा)

longer and that there should be a time limit of, say, six months for effecting this essential administrative reorganisation. The State Government was generally responsive to this suggestion and agreed to lay down a target to which they should work."

आज तक उसके लिये कोई तारीख मुकर्रर नहीं हुई। हमें यह भी मालूम नहीं हुआ कि इस कमेटी पर इतना खर्च करने के बाद इस कमेटी की रिपोर्ट पर क्या असर हुआ, यह पता नहीं है। और उस कमेटी में हमारे यहां के उच्चाधिकारी बैठते हैं और सलाह देते हैं कि हमें किस रूप में खर्चे को कम करना है और डाटा फिक्स करना है। वह डाटा फिक्स करने का सवाल अभी तक देखा है हमारे यहां के मुख्य मन्त्री प्रशासनिक कर्मचारियों की प्रशंसा करते नहीं अघाते। बोलते हैं कि हमारे प्रशासनिक कर्मचारियों ने यह किया है, वह किया है। मैं तो मानता हूँ कि इन प्रशासनिक कर्मचारियों की नैतिकता की कसौटी मुख्य मन्त्री नहीं हैं, जनता है। जनता जनार्दन है। वही ठीक राय दे सकती है कि इनका नैतिक स्तर कैसा है। पर दुःख की बात यह है कि जो प्रशासन करने वाले हैं वे खुद ही अपनी तारीफ करने लग जाते हैं कि हमारा प्रशासन और प्रशासन कर्मचारी बड़े अच्छे हैं। ऐसे हैं, वैसे हैं। इस कारण उन लोगों में और बुराइयां आती हैं। वे समझते हैं कि जो हमारे रक्षक हैं जो हमारे कन्ट्रोल करने वाले हैं वे हमारी तारीफ करते हैं हम सारे देश के कौने कौने की बात सुनते हैं। हम देखते हैं राजस्थान के इन कर्मचारियों के आराम के लिये खस के टट्टे लगे हैं। इसमें पचास हजार खर्चा है। दस बारह हजार उनकी मरम्मत के लिये हैं। पहले टट्टे में बैठकर ठण्डे होते हैं पर ठंडी हवा खाने के बाद काम की तत्परता उनमें आई हो, ऐसा नहीं दिखाई देता। यह चीज़ नहीं रही, आराम तलबी में वे सब भूल जाते हैं। अगर यही हाल इनका रहा तो लोकराज की कल्याणकारी, राज्य की जो उडान हम लेना चाहते हैं वह उडान नहीं भर सकेंगे। जनता की भावनाओं की कदर नहीं करेंगे, पिछड़े वर्ग को ऊपर नहीं लावेंगे और इस प्रशासन की मशीनरी को ठीक नहीं करेंगे तो समय बतलावेगा हम कहां होंगे, आने वाले समय में।

मैं मजदूरों की हालत बताना चाहता हूँ। किशनगढ़ की मिल बन्द हुई। हजारों मजदूर बेकार हुए। विजयनगर की मिल बन्द हुई। पाली मिल ने एक महीने का नोटिस दिया है। हर जगह वे कहते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। जो मजदूरों में काम करने वाले लोग हैं उनके नेताओं के खिलाफ़ बडे बडे मुकद्दमे चलाये जाते हैं और यह होता है कि उनको भी नौकरी से हटा दिया जाता है।

तो उनमें लेबर वेलफेयर ऑफीसरस होते हैं उनको मिल नियत करती है। मैं चाहता हूं सरकार खुद करे, होना यही चाहिये। वास्तव में क्या होता है इनमें। स्टोर में जो सामान आता है बाजार में खरीद करते हैं. सस्ते भावों पर और महंगे भाव का इन्द्रराज करते हैं और इन इन्दराजों के आधार पर गलत आंकड़े पेश करते हैं। और ये लेबर वेलफेयर आफिसर्स आराम करते हैं। मनमाने रीजन्स बता कर मिल

(श्री मूलचन्द डागा)

बन्द कर लेते हैं। इसका एक मात्र कारण (समय समाप्ति सूचक घंटी) यही है कि हम पूरी तरह इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, यह प्रशासन करने वाले खस के टट्टों में पडे रहते हैं, उन्हें फुरसत नहीं इधर ध्यान देने की। सरकार को इस बारे में सक्रिय होना चाहिये। मिल को अगर जरुरत पडे तो अपने कब्जे में लेकर चलाना चाहिये नहीं तो यह बेकारों की समस्या बनी रहेगी। इसको हल करना जरुरी है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर, नगर पूर्व) : श्रीमान्, बजट के अन्दर साधारण तौर पर अच्छाई और बुराई सब होती है। कोई भी हुकूमत थोड़ा भी अच्छा काम न करे ऐसा असम्भव है। इसमें भी कई बजट की मदें सराहनीय हैं। मगर उनको गिनाना, करना, मैं समझता हूँ कि बजट के सामान्य चर्चा के ध्येय को पूरा नहीं करेगा। तो उन अच्छी बातों का जिक्र न करुं तो यह न समझा जावे कि मैं उन अच्छी बातों की सराहना नहीं करता। जो भी अच्छा काम हो रहा है वे बहुत ठीक हैं। मगर हमारी सरकार की प्रतिक्रिया किस ढ़ंग से चलती है उस बारे में क्या क्या इशारे मिलते हैं इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं।

मुझे लगता है श्रीमान् कि जिन बुनियादी समस्याओं को सुलझाने की जिम्मेदारी जनतान्त्रित सरकारों पर होती है उन पर गहराई से और जिम्मेदारी के साथ न सोच कर कभी कभी हम एक टालमटोल के ढ़ंग से और दिल बहलाव के ढ़ंग से समस्याओं पर सोच लेते हैं। मुझे अपने जीवन के बचपन का एक प्रसंग याद आता है। एक बार पुष्कर के मेले में पिताजी से मैंने जिद्द कर ली कि मैं तो इस मेले में से हाथी खरीदना चाहता हूँ। मेरी जिद्द को पूरा करते हुए और न करते हुए बहलाने के ढ़ंग से उन्होंने मेरे अज्ञान का फायदा उठाया। मुझे पशुओं का ज्ञान नहीं था। एक मुर्गी की अंडा खरीद दिया और मुझे बहला दिया कि यह हाथी का अंडा खरीद दिया है इसमें से हाथी का बच्चा तुम्हें मिल जावेगा। मैं बहल गया। मैं समझता हूँ हमारी यह सरकार भी बुनियादी चीजों को पूरा करने के बारे में हाथी के अण्डे के समान तरीका अख्तियार करती है। माननीय वित्त मन्त्रीजी के भाषण में एक ऐसी बात देखी। स्कॉलरशिप का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रथम श्रेणी में इम्तिहान पास करने वाले विद्यार्थियों को यदि उसके माता पिता की २५०) से कम आमदनी है तो उन सबको सरकार स्कॉलरशिप देगी। उनका इन्टरप्रिटेशन इसका यह है कि यह एक बडा जबर्दस्त कदम है, समाजवादी समाज व्यवस्था देश में कायम करने का।

मुझे इस पर हंसी आई। अगर इतनी आसानी से समाजवाद कायम हो सकता है तो इस नीति का प्रचार विदेशों में करना चाहिये और सारे संसार में समाजवाद कायम करना इस तरह से दो दिन का काम है। इतनी आसानी से चीज को समझा देते हैं। मेरा मतलब कहने का यह है कि वे इन समस्याओं पर जिम्मेदारी और गहराई से सोचने का चेष्टा नहीं करते। दिल बहलाव की दृष्टि से विचार करके टाल देते हैं। वह चीज फिर चाहे मिले या न मिले।

प्लानिंग के कुछ आंकड़े देखने को मिले। आज हमारे देश में सबसे बड़ा काम

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

प्लानिंग का हो रहा है । हमारे देश के राजनैतिक और आर्थिक ढांचे में मौलिक परिवर्तन कर रहे हैं प्लानिंग के आधार पर। अकसर चर्चा आती है भिन्न भिन्न आयोजनों के सिलसिले में कि खर्चा बहुत होता है पर सही ढंग से नहीं होता । यह दृष्टि है । ठीक ढंग से काम न करे, और रुपया रख दे । तो वह जितना बडा खर्चा है उतना ही बडा अपव्यय होगा । यह सही दृष्टि है, सोचने की । मान लीजिये बड़े खर्चे का आंकडा दिखाना भी तरक्की की निशानी है हांलांकि यह अनुचित मापदण्ड है, पर मान लीजिये थोड़ी देर के लिये, यह तरीका भी ठीक हो। तो आज सबसे बड़ा आंकड़ा प्लानिंग के सम्बन्ध में है। उस पर जरा गौर करें तो मैं कह दूँ कि ये आंकड़ा मैंने बजट भाषण में से निकाले हैं। वित्त मन्त्रीजी ने मन्जूर किया है कि दूसरी योजना के प्रथम दो वर्षों में जितना खर्च का इरादा किया गया था वह पूरी रकम खर्च नहीं हुई। कम हुई और उसके आंकड़े इस प्रकार आते हैं पहले दो सालों में जितनी रकम रखी गई थी उसमें से १३ करोड़ ६ लाख बिना खर्चे रह गये। असल खर्वे की रकम का ३१.६ प्रतिशत काम में नहीं आई।

इसी प्रकार पहले तीन साल के आंकड़े लें। १५.११ करोड़ बिना उपयोग के पड़ा रह गया। इसका औसत आता है २४ पर्सेन्ट। पहली चार साल के आंकड़े उम्मीद करता हूं साफ साफ तौर से मन्जूर किया है कि नहीं पूरे खर्च कर सके। ७० पर्सेन्ट वह होगा। कायदे से पहले चार सालों में ८० पर्सेन्ट खर्च हो जाना चाहिये। अगर पांच साल में सारा खर्च करना है तो अब दस करोड की रकम बेकार रहेगी। विचित्र चीज़ और भी देखने को मिली। मौजूदा, करन्ट ईयर के आंकड़े देखे तो माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि करन्ट ईयर के रिवाइज्ड फिगर पहले ९ महीने के अन्दर फिर बनाये हैं। और ९ महीने में बतलाते हैं कि प्लानिंग पर ४ करोड़ रुपयों की रकम खत्म हो गई है। ९ महीने साल का ३।४ हिस्सा होता है। जितना बजट में प्रोवाइड था वह ९ महीने में खत्म हो जाना चाहिए था तो इसका हिसाब लगायें तो ८ करोड़ खर्च हो तो ७ करोड़ बिना उपयोग की हुई रकम पड़ी रही और इसका प्रतिशत पड़ता है ८७.५। याने जितनी रकम काम में लायें उससे करीब करीब दुगनी काम में लानी चाहिए थी और उसके लिए तीन महीने में उम्मीद करते हैं कि जो रिवाइज्ड बजट है वह काम में आ जायेगा। अजमेर में भी हमें यही मुसीबत रहती थी। मैं नहीं समझता कि यह बीमारी हमारे अजमेर से आई है या यहां पहले से ही मौजूद है। मैं कहता हूं कि ११ महीने तो हुकूमत सोती रहती है और वित्तीय महीने के आखिरी महीने में याने मार्च के महीने में सारी रकम खर्च करने की सरकार सोचती है। जैसे खरगोश को पागलपन आता है मार्च के महीने में वैसे ही इनको खर्च करने का पागलपन आता है मार्च के महीने में। साल भर का काम एक महीने में करते हैं। मगर यह प्लानिंग का महकमा जिसका काम योजना के अनुसार काम करना है इसके अन्दर बिना योजना के काम किया है। तो इसको हम सही माने में योजना नहीं कह सकते। यह काम तो सारा हैपहैज़र्ड वे से होता है, वह बेढंगा है। जब तक आप उसका सिलसिलेवार शिड्यूल के मुताबिक उपयोग नहीं करेंगे तो वह रकम का सही उपयोग हो सकता है। मेरी समझ

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

में नहीं आता कि जो मशीन ९ महीने में अपनी रकम को खर्च नहीं कर सकती तो वह तीन महीने में उस रकम को कैसे खर्च करेगी। इसका मतलब यह है कि आपकी मशीनरी ही खराब है। आपके प्लानिंग का महकमा इतना निकम्मा है कि सारा काम उसका अनप्लैन्ड होता है। अगर आंकड़ों को देखें तो मालूम होता है कि सही ढंग से काम ही नहीं होता है। और प्लानिंग के इतने बड़े आंकड़ों में ८७.५ रकम बिना काम में आई हुई पड़ी रहती है और आखिरी ३ महीनों में काम में लायेंगे तो यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि आप बिलकुल हैपहैज़र्ड वे में काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष, मैं इस बात पर जोर दिया चाहता हूँ कि जनतांत्रिक हुकूमत का काम क्या होता है। जनतांत्रिक हुकूमत का काम वह नहीं है जो आम तौर से हम अपने देश में सर्विसेज़ से उम्मीद करते हैं। राज्य का सारा काम मैं आपको बताऊं कि हमारी सर्विसेज़ चलाती हैं। दिन प्रति दिन का काम हमारा कर्मचारी वर्ग करता है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर समूचे मंत्री मण्डल को छुट्टी दे दें पांच वर्ष की और उसको यह कह दें कि आप जाइये और कश्मीर में घूमिये तो जैसा काम आज हो रहा है राज्य का और जो सरकारी कर्मचारी चला रहे हैं तो बराबर उसी तरह चलता रहेगा क्योंकि मंत्रीमण्डल में कोई नवीनता नहीं है। जनता के नुमाइन्दों को बैठकर जो काम करना चाहिए वह कर्मचारी वर्ग नहीं कर सकता। यही कारण है कि महकमाशाही से काम होता है। मालूम करने की तो बात यह है कि डिफिकल्टी कहां पर है कि ९ महोने में उपयुक्त रकम क्यों नहीं खर्च हो पाती है। मैं तो समझता था कि वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट में आंकड़े दिये उन आंकड़ों के साथ ही साथ वह नीति रखते कि हम इस बात के प्रति जागरूक हैं कि योजना के अनुसार काम होना चाहिए। तो यह योजना के अनुसार क्यों नहीं काम हो रहे हैं। आप कौनसी नीति अपनाना चाहते हैं कि इस प्रकार के दोष शासन में से निकल जायें, इसकी ओर वित्त मंत्री महोदय का कोई संकेत नहीं है। हमारी योजना के जितने भी काम हैं उनमें सही ढंग से पैसा खर्च हो तो इस तरफ वित्त मंत्री महोदय की ओर से कोई प्रकाश नहीं पड़ा। मैं चाहूँगा कि आइन्दा से कम से कम हमारी सरकार इस ओर ध्यान रखे कि यह स्लैकनैस हमारी हुकूमत में से चली जाये। स्लैकनैस के लिए देखना चाहिए कि इसका दोष कहां है। हमारी रिआर्गेनाइज़ेशन में कोई दोष है या फिर एक विभाग से दूसरे विभाग का सामंजस्य नहीं बैठता या फाइनेन्स डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट के बीच में कहीं अड़चन आती है, या कोई और बात है। जितना पैसा मद में रखा जाता है वह पूरा खर्च क्यों नहीं हो पाता है और जरूरी कामों में खर्च हुए बिना पड़ा रहता है तो इस चीज की खोजबीन होनी चाहिए और इसकी खोजबीन तभी होगी जब कि इसके प्रति हमारा मंत्री मंडल जागरूक रहे मुझे एक मिसाल याद आती है इंगलैंड के एक प्राइम मिनिस्टर की जिनका नाम ग्लेडस्टन था। उनकी जीवनी आप पढ़ डालें। उन्होंने कोई भाषण नहीं किये, उन्होंने कोई उद्घाटन नहीं किये उन्होंने बैठकर ट्रेजरी रेकार्ड किया। आपकी जो प्रचलित बजट प्रणाली थी या जो मामले आते हैं उसमें ट्रेजरी सिस्टम में मजदूरों की तरह बैठकर पांच साल उन्होंने मेहनत की। पहले इंगलैंड की पार्लियामेन्ट

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

में भी इसी तरह हैपहैजर्ड वे में काम होता था। हमारे महकमों का सामंजस्य कैसा है, कहां दोष है, कहां नहीं है इस और आप ध्यान रखिये यह है जनता के नुमाइन्दों का काम। वरना राज्य का काम तो कर्मचारी वर्ग चलाता रहता है। उसके ऊपर हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट की तरह मंत्री लोग काम करेंगे तो जैसे हम हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट किसी डाइरेक्टर को अपाइन्ट करते हैं तो मंत्री लोग डाइरेक्टर ही हैं। अगर इस तरह हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट के बतौर काम करेंगे तो उससे जनतांत्रिक तरीके की प्रणाली में नयापन नहीं आता है। आपको तो नीतियों की खोज करनी चाहिए। आपकी जिस ढंग से शासन व्यवस्था चल रही है उसमें क्या दोष है कहां सामंजस्य नहीं हैं, क्यां देर लगती है इन सब चीजों को सोचिये लेकिन आप पूरी मेहनत से काम नहीं करते। नैपोलियन कहता था कि असम्भव शब्द हमारे शब्दकोष में ही नहीं है। साधारण बुद्धि वाले आदमी जो काम कर सकते हैं वह काम तो हम कर ही सकते हैं। हमारी दृष्टि उधर क्यों नहीं जाती है, हम क्यों दिल बहलाव की तरह काम करते हैं, शतुरमुर्ग की तरह से। शतुरमुर्ग के सामने जब कोई खतरा आता है तो वह अपना मुंह बालू रेत में छिपा लेता है। तो आप ऐसी नीति से क्यों चलते हैं? अगर इस तरफ देखें तो काफी उन्नति हो सकती है।

आप देखते हैं कि हमारे शासन में कई तरह के डुप्लीकेशन होते हैं। डुप्लीकेशन से दो दोष पैदा होते हैं, दोहरादोष पैदा होता है। न केवल यह दोष कि डुप्लीकेशन से आपके शासन में एक आदमी की जगह दो आदमियों को तनख्वाह मिलती है। इसको भी नजर अन्दाज कीजिए उसमें सबसे पहला दोष तो यह आता है कि जहां डुप्लीकेशन होगा वहां अथॉरिटीज़ में झगड़ा पैदा हो जाता है। एक महकमा कहता है कि यह काम उसका है और दूसरा कहता है कि उसका है। इससे टेबल वर्क बढ़ जाता है। यह हुकूमत में शिथिलता पैदा करते हैं। तो इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं बहुत बारीकी से इस पर बात नहीं करूंगा, मेरे दूसरे साथियों को भी बोलना है और न इसके लिए मैं कोई ज्यादा मिसाल देना चाहता हूं। मेरे दूसरे साथी कटमोशन के समय इसको बतायेंगे। मगर मैं एक मिसाल देना चाहता हूं हाल ही इसी सदन के सत्र में सुना कि संस्कृत शिक्षण का एक अलग डाइरेक्टोरेट कायम करना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों? यह डुप्लीकेशन का ही एक उदाहरण है। संस्कृत की शिक्षा अपने अन्दर एक अलग से कायम होगी या जो नार्मल शिक्षा चलती है स्कूलों में कॉलेजों में उसके साथ ही संस्कृत पढ़ानी है या किस रूप में करना है या फिर संस्कृत की अलग व्यवस्था करनी है जिससे नहीं पढ़ने वाले लोग भी संस्कृत पढ़ेंगे, तो किस रूप में आप इसको सोचते हैं और क्या जस्टीफिकेशन है संस्कृत के अलग डाइरेक्टोरेट का। आपका एज्यूकेशन डाइरेक्टोरेट इस संस्कृत डाइरेक्टोरेट से नान कोआपरेट करेगा। इससे मेरे ख्याल से डुप्लीकेशन की जैसी गलती पैदा होती है। जनतंत्रिक शासन व्यवस्था में उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। एक नया डाइरेक्टोरेट स्थापित करके नया सेट अप ऑर्गेनाइज करेंगे और पैसा जनता का व्यर्थ जायगा। एक नया महकमा खोलते है तो उसमें सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी, सुपरिन्टेन्डेन्ट, दूसरे लोग और फील्ड स्टाफ भी

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

होगा मुमकिन है अलग कालेजेज़ भी खुलेंगी तो कितना लंबा चौड़ा खर्च का पिक्चर सामने आता है उससे क्या फायदा ? कितना फायदा होगा इसको जस्टिफाई करना चाहिये और यह बताना चाहिये कि इनमें यह मोटा मोटा भेद है ।

एक बात और सामने आई है । मिसाल के तौर पर मैं एग्रीकल्चर महकमे के बारे में कहूंगा । इस महकमे के फार्म्स बने हुए है एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेन्टल फार्म्स और साथ ही साथ एक अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड भी चलता है । इन दोनों के पास मशीनें होती हैं, पंपिंग सेट, ड्रिलिंग मशीनें, मोटर गाड़ियां आदि होती है । इनके मेकेनिक भी होते, हैं, इंजीनियर्स भी होते है मरम्मत आदि के लिये उनके पास साधन होता है, मोटर गाड़ियां होती हैं । अगर आप अच्छी तरह से इन दोनों का निरीक्षण करेंगे तो यह जाहिर होगा कि यह अनूनेसेसरी डुपलीकेसी है । आप इसमें बहुत कुछ कटाई छंटाई कर सकते हैं । ये मैंने आपके सामने मिसालें दीं । इससे बुनियादी नुक्सान क्या होता है इस ओर ध्यान आकर्षित किया ।

तीसरी चीज साथ २ मैं यह कहूं, जैसी एक मिसाल है, मैंने कहीं सुना था बचपन में, मिसाल कोई एनोलोगस आर्गूमेन्ट नहीं होती, समझाने के लिये होती है, इससे भाव प्रकट कर देते है । एक साधुजी थे जिन्होंने बड़ा त्याग किया सिर्फ एक लंगोट अपने पहनने के लिये रखी । थोड़े दिन बाद में उनका ध्यान उस लंगोट की ओर गया तो उन्होंने देखा कि उसको चूहा काट रहा है । उनको बड़ा गुस्सा आया कि मैंने सब कुछ त्याग दिया एक लंगोट रखी उसको भी यह चूहा काट रहा है इसलिये उन्होंने एक बिल्ली पाली, थोड़े दिन बाद में एक भैंस ले आये....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या आपका मतलब विनोबाभावे से है ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : वह तो साधारण बात है । विनोबा भावे में भी थोड़ी मात्रा में हो तो ताजुब नहीं । श्रीमान् मैं यह निवेदन कर रहा था कि अपने ढांचे को लगातार बढ़ाना एक स्वाभाविक मनोवृत्ति है जो मनुष्य मात्र में होती है । महकमे भी इसी प्रकार के होते हैं । कोई ऐसा महकमा नहीं है जो अपने कलेवर को बढाने के बजाय छोटा करता जाय किसी न किसी तरह से वह बढ़ता रहता है । जनतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि जो जनता के नुमायन्दे हैं वे इस चीज को तेज आंखें देखें कि. आवश्यक बढ़ोत्तरी कैसे हो रही है । कहीं इसका कलेवर गणेशजी की तरह तो नहीं बढ़ रहा है । यदि आवश्यक हो तो बड़े गौर से उसे देखें और अनावश्यक बढ़ोतरी नजर आती हो तो उस पर छटनी की नजर रखें, उसका अन्वेषण करें यह मंत्री मंडल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ।

इस बजट को यदि आप देखें तो एक जगह ही नहीं बल्कि पचीसों जगह वित्त मंत्रीजी ने मंजूर किया है कि हमने इकोनोमिक योजना बनाई थी वह पूरी नहीं हो सकी । जिन जिन महकमों मैं हम कम खर्चा करना चाहते थे उनमें कई मदों में अधिक खर्चा हुआ । इसका जो एनेलेसिस दिया है वह कितना शर्म का है । इकोनोमिक योजना बनाई, कमेटी बनाई, उसने सजेशन्स दिये परन्तु उनको इम्पलीमेन्ट नहीं कर सके ।

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

आपका जो मुख्य काम है वही नहीं हुआ तो आपसे हुआ क्या ? बाकी काम तो महकमों के डाइरेक्टर्स और सेक्रेटरीज़ भी कर सकते हैं उनके लिये जनता के नुमायन्दों की आवश्यकता नहीं थी। कभी कभी में महसूस करता हूं कि आज जो डींग मारते है तरक्की की वह आज से २५ वर्ष पहले, जब अंग्रेजो की हकूमत थी और मैं कॉलेज का स्टूडेन्ट था, उन चीजों की बुनियाद उस समय अंग्रेजों ने डाली थी। अध्यक्ष महोदय, अगर गहराई से देखें तो भाखरा वगैरा बड़े बड़े काम है पोस्टवार रिकंस्ट्रक्शन के रूप में उनकी बुनियाद पड़ चुकी थी अंग्रेजों के समय में ही....

(सयय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े में ही खतम करना चाहता हूं।

श्रीमान् एक बुनियादी चीज़ की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जो सरकार की नीति में नहीं है तो मैं चाहूंगा कि सरकार सच्ची नीति को अमल मैं लावे। में उस चीज का आधार विधान को बनाऊंगा। अक्सर शिकायत आती है कि पंचायतों में न्याय नही अन्याय होता है। यहीं पर पिछले सत्र में यह बात आई थी कि पंचायत ने ५०० रूपये तक का जुर्माना किया। मैं भी वकील हूं। बहुत से पंचायतों के मामले मुझे भी करने पडते है। मैं उनमें बहुत सी अजीब बातें देखता हूं लेकिन इसका सही इलाज क्या है। हमारे विधान में लिखा है कि विकेन्द्रीयकरण शासन सत्ता का हो, यह बुनियादी चीज़ है और इसी रूप में आप पंचायतों को अधिकार देते हैं। मैं कहता हूं कि म्युनिसिपेलाइज़ेशन ऑफ पुलिस भी होना चाहिये। शक्ति का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। यह ठीक है लेकिन आप उनको न्याय का काम क्यों सौंपते है। वे प्रशासनिक और एग्ज़ीक्युटिव इकाई के रूप में काम कर सकती है। हमारा विधान कहता है कि एग्ज़ीक्यूटिव और ज़्युडिशियरी को सेपरेट करना चाहिये। लेकिन हम ठीक इसके विपरीत करते है तो फिर गड़बड़ी होती है। अमेरिका में पहले यह हुआ था कि वहां पर जजेज़ चुने हुए होते थे, जजों का चुनाव होता था उसमें पार्टी के आदमी आते थे। चुनाव में निष्पक्ष आदमी आ नहीं सकते। अमेरिका ने ५० वर्ष के बाद इस चीज़ को बड़ी कठिनाई से छोडा और तय किया कि जजेज़ कभी चुने हुए नहीं होने चाहिये, निष्पक्षरूप से उनका सिलेक्शन होना चाहिये। मैं चाहता हूँ कि लोगों को उनके घरों के नजदीक ही इन्साफ मिले। लेकिन चुने हुए जजों की प्रथा हमारे विधान के डाइरेक्टिव के भी खिलाफ है। हमें जुडिशियरी और एग्ज़ीक्युटिव को सेपरेट करना है, शामिल नहीं करना है, इस दृष्टि से सोचा जाय तो अच्छी चीज़ होगी।

कुछ बातें मैं पुलिस के बारे में भी कहना चाहता हूं। इस महकमे पर भी लम्बा चौड़ा खर्चा बढ़ रहा है। हर महकमे की अपना कलेवर बढ़ाने की टेन्डेन्सी होती है वह यहां भी चल रही है। जो नोन डवेलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट्स हैं उनका खर्चा काफी परसेन्ट बढ़ा है और यह अनावश्यक बढ़ा है। हमें नोन डवेलपमेंट विभागों का खर्चा कम करना है। शासन चुस्त रहे, उसमें एफिशियेन्सी रहे, योग्यता बढ़े यह सब कुछ करना है लेकिन

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

दूसरे महकमों में जिस टेन्डेन्सी से खर्चा बढ़ा है उसी टेन्डेन्सी से पुलिस में भी बढ़ा है। डकैतों के बड़े जबर्दस्त झुंड अब भी बताये जाते हैं। शासन को सुधारने के लिये कल्पना की आवश्यकता कम से कम उतनी तो होनी चाहिये जितनी अंग्रेजों में थी, हालां कि जनतन्त्र में उससे अधिक की उम्मेद करते हैं। डकैत बड़े ओर्गेनाइज्ड ढंग से काम करते हैं लेकिन आप उनको कोएरशन से काबू में लाना चाहते हैं लेकिन यह गलत तरीका है, आपको इसके लिये योग्यता से काम करने की जरूरत है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट अंग्रेजो ने कायम किया था और ऐसे ही अंगों को काबू में करने के लिये किया था। आज तो हमने पोलिटिकल पुलिस बनादी है। राजनैतिक काम में हम सी. आई. डी. को लेते हैं। डाकुओं के ऑर्गेनाइज्ड गैंग होते हैं वे कहां जाते हैं, कहां बैठते हैं, कहां खाते हैं, कहां पीते हैं और कहां सोते हैं इसका आपको पता लगाना चाहिये, आखिर उनका भी तो एक सिस्टम है। आप इन्टेलिजेन्स डिपार्टमेंट को पोलिटिकल पुलिस नहीं बना कर उनको इधर लगावें तो आप तीन दिन में सभी डाकुओं को पकड़ सकते हैं। इसके लिये न आपको तलवार की आवश्यकता पड़ेगी और न बन्दूक की, जहां वे सोते हैं वहां जाकर उनको पकड़ लीजिये। परन्तु आपकी कल्पना कोअर्शन की चलती है। आप यदि कल्पना से काम लें तो काम हो सकता है।

तो मैं चाहता हूं कि हमारी शासन व्यवस्था में कल्पनाएं इन्ट्रोड्यूस करें। इस तरह से बजट को देखें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम ऐसा नया काम कर सकते हैं जो हिन्दुस्थान में मिसाल हो, मैं चाहता हूँ कि राजस्थान मिसाल पेश करे। इसीलिये मैं वित्त मंत्री से जोर से कहता हूँ कि उन्होंने हमें कहा था कि फेअर एन्ड ओपन माइन्ड से बजट पर बहस करें तो वे भी फेअर एन्ड माइन्ड से, इसको देखेंगे, ऐसी मैं उनसे आशा करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्वेदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराट) : साहब पहले भी नहीं बोलने दिया।

(हंसी)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष राजस्थान राज्य का ५९–६० का आय व्ययक पेश है। किसी भी राज्य का आय व्ययक केवल उस राज्य के आय और व्यय के आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं होता, अपितु वह आय व्ययक अर्थ नीति के सिद्धान्तों पर आधारित होता है, खास तौर से यह कि जो उस राज्य की आय है, वह किन साधनों से आती है और व्यय किन मदों पर किया जाता है।

आय के साधनों में भी यह देखना पड़ता है, कि आय केवल उन्हीं मदों से की जाय, जो आय देने के योग्य हैं। हमारी केन्द्रीय सरकार जैसा हम देखते हैं कि उनकी आय खास तौर से सारे देश पर लागू होती है, वह आय–कर है, सम्पत्ति–कर है, मृत्यु–कर है और इस प्रकार के कर हैं, जो वे ही लोग देते हैं जो कि देने की क्षमता रखते हैं। तो जिस तरह बजट के आंकड़ों में यह देखना पड़ता है कि आय किन लोगों से की जानी चाहिये, उसी तरह व्यय करने में और भी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

अधिक विवेक की आवश्यकता होती है कि जो व्यय किया जाय उससे अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। यह खास चीज देखने की होती है।

जब हम अपने आय व्ययक को देखते हैं तो मुझे दुख होता है कि वह हमारे अर्थ शास्त्र की जो मूल नीति है, उस पर भी आधारित नहीं है। हमारी आय के साधनों में मैं यह देख कर खुश होता हूं कि इसमें कर ऐसे लोगों पर लगाये गये हैं जो कर देने की क्षमता रखते हैं, जिनकी शक्ति साधारण लोगों के मुकाबले में ज्यादा देने योग्य है, तो मैं उनका स्वागत करता हूं और सारा सदन स्वागत करेगा। पर आय में अतिरिक्त कर रखे हैं मुझे यह देख कर दुःख है कि यह उन लोगों पर रखे गये हैं जिन लोगों में देने की क्षमता कम है।

भाषण के आरम्भ में हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने बड़े ही सुन्दर और सुहावने शब्दों में बताया है :

"हमारे देश की अधिकांश आबादी गांवों में बसती है, और परम्पराबद्ध मनोवृत्ति, आदिकालीन अवस्थाओं व सीमित साधनों वाले हमारे इन देशवासियों को केवल इस बात की अपेक्षा है कि उनके अन्तःकरण की ज्योति जगा दी जाय।"

इससे आगे जो भी कुछ है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे आय व्ययक में यदि अधिक से अधिक लाभ किसी को पहुंचाया जाय तो वह गांव वालों को पहुंचाया जाय और जो कुछ लिया जाय तो उसका कम से कम बोझा, उन गांव वालों पर पड़े। पर जहां हम इन अतिरिक्त करों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो कर लगाये गये हैं उनका अधिकांश बोझा गांव वालों पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर भूमि सुधार कर और जो सिंचाई की दरों में वृद्धि की गई है वे दोनों पूरे तौर से गांव वालों पर ही बोझा डालते हैं। यह बात भी सही है कि उनसे लाभ गांव वालों को पहुंचता है पर ये सारे कर गांव वालों पर लगाये गये हैं। जो मनोरंजन कर लगाया है वह तो मुमकिन है शहरी लोगों पर ही हो।

एक कर आबकारी कर है, मैं समझ नहीं सकता कि इस कर के लगाने की क्या मंशा है। आया यह इसलिये लगाया गया है कि शराब की खपत ज्यादा है, इसको रोकने के लिये लगाया जाय, या आय बढ़ाने के लिये लगाया है। होना तो यह चाहिये था जिस चीज़ का निषेध हम बहुत दिनों से करते आये हैं, देश के आजाद होने से पहले कांग्रेस के नेता इस बात पर सबसे अधिक बल देते थे कि हमारे देश से शराबखोरी बिलकुल बन्द होनी चाहिये। मुझे तो स्मरण हो रहा है कि स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सबसे ज्यादा ज़ोर इस बात पर दिया था कि शराब को बिलकुल बन्द कर देना चाहिये और इसको आमदनी का साधन नहीं बनाना चाहिये क्योंकि इससे की हुई आय शिक्षा पर खर्च की जाती थी, इसलिये वे बिलकुल नहीं चाहते थे कि शिक्षा प्रसार में इससे हुई आय को व्यय करें, इसलिये वे सबसे अधिक जोर इस बात पर देते थे कि शराबखोरी को खत्म किया जाय, इस पर टैक्स लगाकर इसको आय का साधन नहीं बनाया जाय। पर यहां इसको आय का साधन बनाया है तो हम कह

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

सकते हैं कि यह आय का साधन कांग्रेस की नीति के अनुकूल नहीं पड़ता। आवश्यकता तो इस बात की थी कि शराबखोरी को हर स्थान से मिटाया जाये जब कि दूसरे राज्य इस ओर कदम बढ़ा चुके हैं पर मुझे यह देख कर दुख हो रहा है कि शराबखोरी दिन प्रतिदिन हमारे राज्य में बढ़ रही है। कभी हम अखबारों में पढ़ते हैं कि पुलिस का अधिकारी शराब पीकर राजकीय प्रवास भवन में आता है और शोर गुल करता है, यह शराबखोरी का इस तरह का प्रदर्शन किया जाना और खास तौर से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाना जिनको प्रजा अन्नदाता, शासक और मालिक के तौर पर मानती है, तो उन पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है।

मैं चाहता तो यह था कि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करती कि शराबखोरी इस प्रान्त से मिटाती और खास तौर से उस अधिकारी वर्ग में से तो एक दम मिट जानी चाहिये थी जिसको जनता परम्परागत संस्कारों के कारण मालिक की तरह देखती आई है। फाइनेन्स कमेटी ने भी इसी तरह का सुझाव दिया है। कुछ खास दिन ऐसे रखे हैं, ८ या १० दिन मुकर्रर किये हैं जिन दिनों में राज्य में कोई शराब नहीं पिये, पर इसका कहां तक पालन होता होगा यह तो मैं नहीं कह सकता।

तो मैंने बताया कि जो आय के साधन हैं उनका अधिक भार गांव वालों पर ही पड़ता है और व्यय से हमारे ग्रामवासी भाइयों को कम से कम लाभ पहुँचता है। इसी प्रकार हमें व्यय को भी देखना पड़ेगा कि किन मदों पर ज्यादा व्यय होता है। देश के आजाद होने से पहले सबसे ज्यादा जोर इस बात पर देते थे कि प्रशासनिक कार्यों पर कम खर्चा होना चाहिये, जनता की भलाई के कामों पर, जन हितकारी कामों पर, उपयोगी कार्यों पर हमारी आय का अधिकांश भाग ज्यादा खर्च होना चाहिये। पर आज हम देखते हैं कि राजाओं महाराजाओं का ज़माना था, अंग्रेजों का जमाना था, उस समय जिस कदर प्रशासनिक व्यय हमारे देश में होता था, उससे भी ज्यादा खर्चा प्रशासन पर बढ़ रहा है।

फाइनेन्शियल एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि राजस्थान सरकार अपने प्रशासन पर अधिक से अधिक खर्चा बढ़ा रहा है। यहां तक लिखा था:—

"It is estimated that the total expenditure on salaries and allowances to Government servants in Rajasthan is about 2.15 crores, while taxes and charges amount to 53 lakhs."

और फिर आगे लिखा है,

"The two items alone account for nearly half of the present revenue budget. They exceed the whole State revenue as it stood in 1951-52."

राजस्थान राज्य के अस्तित्व में आने से पहले जितना राजस्व था, उससे कहीं अधिक खर्चा प्रशासनिक अधिकारियों की तनख्वाह पर और उनके पेन्शन पर किया जाता था। किसी राज्य की आमदनी का खर्चा इस प्रकार से करना उचित नहीं है। कहां कहां काम किये जांय और कैसे २ किये जांय यह तो राज्य सरकार का काम है, लेकिन यह व्यय हो रहा

Page No 41

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

है, उस जनता पर, किसकी भलाई के लिए यह राज्य बना है, उसके लिए नहीं है। जनता चाहती थी कि लोक हित के कार्य हैं, जैसे शिक्षण संस्थायें, औषधालय, बिजली, सिंचाई आदि इन पर अधिक खर्चा किया जाता लेकिन खर्चा ज्यादा हो रहा है इन विभागों पर यह भी मुझे देख कर आश्चर्य हुआ कि इसमें शायद शिक्षा को छोड़ कर सबसे अधिक खर्चा यदि किसी विभाग पर होता है तो वह पुलिस विभाग पर होता है। यह तो हो सकता है कि देश में शान्ति और व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस बढ़ाई जाय, उसे रखी जाये, लेकिन एक तरफ तो हम राज्यपाल महोदय के भाषण में पढ़ते हैं कि देश की शान्ति और व्यवस्था सन्तोष प्रद होती जा रही है, इतने डाकू अमुक स्थानों पर मारे गये, इतनी कम चोरियां हो गई। यह तो मैं आपको कटौती प्रस्तावों पर बोलते समय बताऊंगा कि डकैतियां, चोरियां कितनी कम हुई है, लेकिन एक तरफ तो सरकार की यह घोषणा होती है कि डाके और चोरियां कम होती जा रही हैं लेकिन जब आय व्यय के बजट को देखते हैं तो पुलिस विभाग पर अधिक से अधिक खर्चा बढ़ता ही चला जा रहा है। पुराने समय में जब कि हमारे यहां विदेशी हुकुमत थी तो यह आवाज बुलन्द की गई थी कि विदेशी हुकुमत सारा खर्चा, व्यय फौज और पुलिस पर करती है जिससे जनता के विकास के ऊपर खर्चा नहीं होता, और इसीलिए भी हम यह चाहते थे कि विदेशी हुकुमत जल्दी से जल्दी हमारे देश से चली जाय जिससे कि जो आय है वह जनता की भलाई के लिए खर्च की जाय और उन आयों को और भी बढ़ाया जाय। आज सेना का जो खर्चा है वह तो केन्द्रीय सरकार के ऊपर है लेकिन पुलिस का जितना खर्चा है वह राज्य सरकार पर है और मैं समझता हूं कि अन्य राज्यों के मुकाबले में भी हमारे इस राज्य में पुलिस पर अधिक व्यय होता होगा।

इससे उस जनता को कोई लाभ नहीं जिस जनता के लिए वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण के प्रारम्भ में बताया था कि उनके लाभ के लिए किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बड़ी खुशी तो यह होती, कि यदि मंत्री महोदय इस बजट में यह दिखाते कि ग्रामीण लोगों की शिक्षा पर इतना खर्च कर रहे हैं, ग्रामीण जनता के आवागमन के साधनों के लिए इतना खर्च कर रहे हैं, ग्रामीणों की चिकित्सा के लिए इतना खर्च कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था के लिए इतना खर्च कर रहे हैं। हमारा शिक्षा मंत्रीलय कहता है कि हमने अब के इतने प्राइमरी स्कूल खोल दिये, किस उद्देश्य से खोले? जो बेरोजगार लोग हैं, जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं उनको धन्धा देने के लिए उनको प्राइमरी स्कूलों में लगा दिया, या लगादिया जायगा। मैं समझता हूं कि जहां उद्देश्य यह है कि शिक्षण संस्थाओं में उन लोगों को भेजा जाय जिनको दूसरी जगह कहीं धन्धा नहीं मिलता जो मेट्रिकुलेट्स हैं, फर्स्टडिविज़न में या हायर डिविज़न में पास होते हैं तो वे कम्पीटिटिव एक्ज़ामिनेशन में आगे जा सकते हैं, लेकिन जिनकी योग्यता इतनी नहीं है, जो तृतीय श्रेणी में पास हुए लोग हैं उनको प्राइमरी स्कूलों में रखा जावेगा और आज उनकी जो हालत है वह भी समय पर हमारे सामने आती ही रहती है, इससे शिक्षा का उत्थान नहीं होने वाला है। यह ग्रमीण शिक्षण भी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

नहीं कहा जा सकता । ज्यादा गावों में साक्षरता का प्रचार हो रहा है, यही सहा जा सकता है । किस तरह से इसको बनाये, कैसे बनाये, यह तो विस्तार की चीज़ है । प्राइमरी स्कूल सुन्दर बन सकते हैं यदि शिक्षक योग्य हो । तो हम ग्रामीण शिक्षा पर कितना खर्च करते हैं, यह इससे स्पष्ट प्रकट हो जाता है ।

इसके साथ साथ गांवों में कुटीर उद्योग धन्धे क्या क्या होने चाहिये, कहां कहां क्या विकास की उनके लिए आवश्यकता है जिससे कि ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है उसकी ओर कोई संकेत नहीं मिलता । मैं समझता हूं कि ब्लाक्स, विकास खंड नहीं होते तो १२ वर्ष हमें स्वतन्त्र हुए होगये, गांवों में किसी प्रकार भी उन्नति का काम हुआ, यह नहीं प्रकट होता । लेकिन ब्लाक्स भी तो सब जगह नहीं है । ब्लाक्स में भी सोभाग्य से ब्लाक्स अधिकारी सुयोग्य और अच्छे मिले बी. डी. ओज़ ब्लाक्स अधिकारी, ग्राम सेवक आदि अच्छे हैं वहां तो कुछ काम हो भी रहा है और हुआ है लेकिन यह भी शिकायत है उन ब्लोक्स से भी, जहां ग्रामीणों का जैसा लाभ और विकास होना चाहिये, वह नहीं हो रहा है । ग्रामों में बड़े २ मिल खोलना वांछनीय नहीं हो सकता, वहां तो कुटीर उद्योग ही हो सकते हैं । जितना खर्चा आज बड़े २ उद्योगों के लिए किया जाता है, जितना धन उनको कर्ज के रूप में आज दिया जाता है, उतना कुटीर उद्योगों के लिए व्यय नहीं कर रहे हैं । आज ग्रामों की उन्नति का उदाहरण यह है कि जहां देश को स्वतन्त्र हुए १२ वर्ष हो गये हम देखते हैं कि ग्राम दिन व दिन उजड़ते जा रहे हैं और लोग रोजगार पाने के लिये शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं और जहां एक तरफ गांव में खण्डहर होते जा रहे हैं वहां दूसरी ओर शहरों में स्लम्स बढ़ते जा रहे हैं । यदि गांवों में आवागमन के साधन बढ़ाते, यदि गांवों में कुटीर उद्योग धन्धों को अधिक प्रोत्साहन देते, उनके लिए बिजली के साधन जुटाते, उनके लिये पानी की व्यवस्था करते और यह सारी व्यवस्था यदि हम गांवों में करते तो हम समझ सकते थे कि ग्रामों का विकास हो रहा है । इसके बावजूद भी ग्रामवासियों का हमारे साथ जो सहयोग है वह उनकी उदारता का परिचायक है । लेकिन उनके विकास के लिये जब व्यवस्था हम आय व्ययक बजट में देखते हैं तो हमें दुःख होता है और यह कहना पड़ेगा कि गांव वालों के लिए इसमें कोई सुविधा नहीं रखी गई है ।

इससे आगे हम यह भी देखते हैं कि राज्य सरकार ने शिक्षा पर व्यय करने के लिए प्रावधान रखा है । यह बड़ी खुशी की बात है । लेकिन जिस बुनियादी शिक्षा को हम समझते हैं कि देश की बेरोजगारी, बेकारी को मिटाने के लिये है और जिसको वास्तविक शिक्षा कह सकते हैं वह बुनियादी शिक्षा के द्वारा हो तो उस बुनियादी शिक्षण में भी हम त्रुटि पाते हैं । मेरा विश्वास है कि बुनियादी तालीम जिन शिक्षकों से दिलाते हैं वे बेसिक शिक्षा के लिये ट्रेन्ड होते हैं लेकिन उनके ऊपर जो अधिकारी गण होते हैं, मुझे पता नहीं कि वे कहां तक बेसिक शिक्षा में ट्रेन्ड होते हैं और उसमें रुचि लेते हैं । कुछ दिनों की बात है कि श्रीमती आशा आर्यनायकम, जो बुनियादी शिक्षा की विशेषज्ञ है, उन्होंने कहा कि यदि बुनि-

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

यादी शिक्षा का प्रचार करना है तो यह केवल प्रारम्भिक पाठशालाओं में जो टीचर्स हैं, उनकी बुनियादी शिक्षा की ट्रेनिंग से ही काम नहीं चलेगा किन्तु यह राज्य सरकार के शिक्षा के डाइरेक्टर्स हैं, इन्सपेक्टर्स आदि हैं उन शिक्षितों में भी बुनियादी शिक्षा का प्रचार होने से ही होगा। मैं समझता हूं कि यदि देश में बुनियादी शिक्षा को प्रभावशाली बनाना है, यदि जनता में बुनियादी शिक्षा के लिये रुचि पैदा करना है तो इसके लिए उच्चाधिकारियों को ट्रेन्ड करना पड़ेगा और जब तक ट्रेन्ड नहीं किया जायगा तो कोई विशेष फायदा नहीं होगा। यह कहा जाता रहा है कि बच्चों की जो बनी हुई चीजें हैं उनमें सहायता देंगे, मैं समझता हूं कि केवल सहायता देने से ही लाभ नहीं होगा। जब तक राज्य सरकार बच्चों के द्वारा बनाई हुई चीजों को, वे वस्तुएं जो कि बच्चे बुनियादी तालीम के समय बनायेंगे, सरकार स्वयम् नहीं खरीदेगी और स्वयम् ही नहीं बेचेगी एम्पोरियम आदि में रख कर तब तक लाभ नहीं होगा। इसलिये यहां हम अपनी शिक्षा में बुनियादी शिक्षा को स्थान दें और उस बुनियादी शिक्षा को प्रभावशाली बना सकें और जनता को आकृष्ट कर सके, इस तरह का बनाना होगा। जनता क्या बहुत से शिक्षक लोग भी अभी पूरी तौर से ध्यान नहीं दे पाये हैं कि बुनियादी शिक्षा से देश को लाभ होगा या नहीं। शिक्षा की मद के अन्दर एक अवश्य स्वागत योग्य प्रावधान किया गया है। जो लड़के या लड़की, चाहे मैट्रिक, इन्टर, बी. ए., बी. कॉम कैसे छोड़ दिया? यह भी डिग्री है, यह भी फेकल्टी में आती हैं उनको नहीं दिया है, शायद उसको बाद में सुधार देंगे इन कक्षाओं में जो छात्र या छात्रा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होंगी और जिनकी आमदनी २५० रुपये माहवार से कम होंगी उन छात्र छात्राओं को सरकार विशेष रूप से छात्रवृत्ति देगी। मैं समझता हूं यह प्रावधान इतनी आय से ऊपर वालों तक भी रहे तो भी कोई बात नहीं होनी चाहिये। इससे काफी छात्र लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ साथ मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि शिक्षा के अतिरिक्त सरकार जिन मुद्दों पर खर्च कर रही है, उसको जनहितकारी मान सकते हैं, वे सड़कें हो सकती हैं, वे हमारे भवन हो सकते हैं और इससे भी ज्यादा पशु धन की तरफ ज्यादा ध्यान दिलाया है। पशुधन के अन्दर भैंसे और कुक्कट और मुर्गा का बहुत जिक्र हुआ लेकिन मैंने इसके अन्दर नहीं देखा कि हमने गोसंवर्धन के लिये गोसदन या गोसंवर्धन के लिये किसी प्रकार का प्रावधान रखा हो। कितनी डेरियां आपने चालू की कितना शुद्ध दूध और घी की व्यवस्था की इसका उल्लेख कहीं नहीं है। यह ठीक है जो कुक्कुटों का उपयोग करते हैं उनके लिये यह उपयोग हो सकता है वे उनके अंडों का उपयोग कर सकते हैं। किन्तु दूध पीने वाले शुद्ध घी खाने वालों के लिये आपने क्या किया। केवल मुर्गियों के पालन से पशु धन की रक्षा नहीं हो सकती। पशुधन में सब से बड़ा धन गोधन है। हमें गोवंश की तरक्की करनी होगी केवल कुक्कुटों से काम नहीं चलेगा। गोसदन और गोसंवर्धन के लिये अधिक से अधिक व्यवस्था की जानी चाहिये। एक तरफ आप पशु धन को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आपने गांवों में जाकर देखा है वहां पशुओं को चराने के लिये गोचर भूमि नहीं। गांव के गांव ऐसे मिलेंगे। जिस

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

ज़िले से मैं आया हूँ वहां के लिये मैं कह सकता हूं वहां के गावों में गोचरभूमि नहीं है और जब पशुओं में बीमारी फैलती है उन बीमारियों के लिये दवाइय पैदा नहीं होती डाक्टर पैदा नहीं होते। हम चाहते हैं कि पशुधन की उन्नति हो पशुधन की रक्षा के लिये साधनों की आवश्यकता है लेकिन उन साधनों का सरकार के पास अभाव है। इसलिये मैं चाहता हूं कि पशुधन में वास्तव में तरक्की करनी है। तो जो कुछ सुझाव दिये गये हैं उन पर अमल किया जाय।

सड़कों के संबन्ध में एक बात जरूर बतलाना चाहूंगा। यह बहुत अच्छी चीज़ है कि सड़के अधिक से अधिक बनती जा रही है। लेकिन जितनी सड़कें आज पुरानी हैं उनकी दशा जितनी दुर्दशाग्रस्त है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि कुछ अर्से के लिये जो नई सड़कें बन रही हैं उनको कतई बन्द कर दिया जाय और जो पुरानी सड़कें जो जीर्ण शीर्ण अवस्था पड़ी है, उनकी पहले मरम्मत की जाय। इसके अलावा कई ऐसी सड़कें हैं जो दो-दो चार-चार मील बन कर रह गई हैं किसी सड़क पर पुलियां नहीं है तो कहीं कलवर्टस नहीं ऐसी हालत सड़कों की है उससे जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचता। जब तक उन सड़कों की दुरूस्ती नहीं होती, वे सड़कें किसी काम की नहीं हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

१. ३. म० प०

श्री अध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलालमोदी (बैरठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस असेम्बली में राजस्थान का जो बजट.......

श्री श्रीभानसिंह : But Sir, even the Deputy Finance Minister is not present in the House now.

श्री अध्यक्ष : One Minister can look after the work of another Minister.......

श्री श्रीभानसिंह : There must be some curtsey. Sir. Either the Finance Minister or his Deputy must be here.

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : भोजन करने गये हैं। He has gone to take his lunch only.

श्री श्री भानसिंह : But this is no excuse.

श्री रामकिशोर व्यास : But I am ready to take your notes.

श्री श्रीभानसिंह : There is a joint responsibility, undoubtedly, but he can take notes about his own department, and not about taxation and other matters pertaining to the Finance Department.

श्री अध्यक्ष : Are you missing this so badly ?

श्री श्रीभानसिंह : I do miss the Finance Minister very badly.

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बज़ट पेश हुआ है उसको जो बचत का बजट बताया गया है उसके लिये

Page No 45

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

मैं राजस्थान सरकार को बहुत धन्यवाद का पात्र मानता हूं। लेकिन इस बचत के अन्दर भी राजस्थान सरकार ने टैक्स लगाये उन टैक्सों का असर हर गांव के अन्दर हर कस्बे के अन्दर होने वाला है। वहां के लोग यह सोचने लगे हैं कि दिन प्रतिदिन सरकार यह क्या नये नये टैक्स लगाती जा रही है। पहले बहुत आराम था, अब तो बड़ी परेशानी में है। इस तरह की लोगों की धारणा बनती जा रही है। माननीय अध्यक्ष, दिन प्रति—दिन टैक्स लगाने से जो हम गांवों में या कस्बों में विकास का काम करना चाहते हैं और पंचायतों द्वारा काम कराना चाहते हैं उसमें बहुत बाधा पैदा होती है। मैं अपनी जानकारी के आधार पर बताना चाहता हूं कि दूसरी कन्ट्रीज़ में इतने टैक्स नहीं हैं। उन कन्ट्रीज में टैक्स अवश्य हैं, लेकिन वहां एक ही तरह का टैक्स हो सकता है। वहां तो कई तरह के टैक्स हर साल सरकार लगाती जा रही है उससे जनता परेशान रहती है। आज सरकार को पता नहीं जिस फेमीली के अन्दर पांच छ मेम्बर्स हैं उसकी आमदनी जब तक तीन सौ रुपया माहवार नहीं होती तब तक उसका गुजारा नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष, आज हम समाजवाद का नारा बुलुन्द करना चाहते हैं। लेकिन जिस समाजवाद का नारा आप लगा रहे हैं वह समाज—वाद के रूप में डिक्टेटरशाही को आप ला रहे हैं।

१. ६. म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जैसा चाहे उस तरह से टैक्स लगाकर जनता को परेशान किया जाता है, और बजट बचत का बताया जाता है, यह उचित नहीं है। जब आप फायदे का बजट बताते हैं तो जनता जरूर यह समझ जाती है कि अब हमारे पर टैक्स आयेंगे।

जो नये टैक्स लगाये हैं वे भी नये नहीं लगाते तो भी ज्यादा अच्छा होता।

आज जो रुपया खर्च किया जाता है वह पूरी तरह से खर्च नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर तो कई माननीय सदस्य बोल चुके है। कोई नया सुझाव हो तो अच्छा होगा।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : बता दिया होगा पर मेरी तरह जगह जगह पर जाकर देखा नहीं होगा। मैं तो पूरे अनुभव की बात कहता हूं। तो उपाध्यक्ष महोदय, इन ब्लाकों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा पचास हज़ार विकास के काम के लिये होता है, और सत्तर हज़ार मशीनरी के लिये होता हैं।

श्री उपाध्यक्ष : किन रुपयों की और संकेत है आपका ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : राजस्थान की बात कह रहा हूं।

(हंसी)

और बाकी रुपया तकावी का होता हैं तो वह कर्ज़ा है। हाथ दिया और हाथ लिया और एक लाख मकान बनाने का। वे सारे दिन जीप लिये लिये डोलते हैं, कोई ग्राम सेवक

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

बना दिया, कोई ग्राम काकी बना दी, काका बना दिया और काम कुछ नहीं। मैं तो सही अर्ज कर रहा हूं। वह पैसा सारा फिजूल जाता हैं। कुछ काम ये नहीं करते।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राम काकी का पैसा? यह क्या है?

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो यह सारा पैसा जो ब्लाक की मशीनरी में खर्च किया जाता है उसका कोई उपयोग नहीं होता। मैं इसके खिलाफ हूं। जब आप पंचायतों को सब अधिकार देते हैं तो इनकी कोई जरूरत नहीं। यह पैसा फिजूल जाता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

पांच मिनिट तो हुए हैं। घंटी क्यों बजा दी।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : मैं संकेत कर रहा था। मुद्दे पर बोलें तो अच्छा हो ताकि माननीय सदस्यों को उसका लाभ मिले।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो ऐसी हालत में डवेलपमेन्ट एरिया में ६० हजार दिया तो उसमें पंचायत ने काम किया, मैंने भी उसमें योग दिया। उस ६०हजार से हमने ३ लाख का जनता से काम करवाया। परन्तु अब टैक्स दिन पर दिन लगाया जाता है और काम नहीं होता हे इसलिये मेरे को दुःख बहुत होता है। सरकार का एक रुपया भी फालतू खर्च होता है तो मेरे को दुःख होता है। सरकार ने जितने कामों में रुपया सैंक्शन किया, पी. डब्लू डी. में या इर्रिगेशन में तो काफी रुपये की गड़बड़ियां होती हैं पर अगर ये कानून बनाने वाले सभी यह सोच लें कि प्रेक्टिकली उनको भी काम करना है तो काफी काम हो सकता है। और सारी दुनिया में राजस्थान का नाम हो सकता है। अगर प्रैक्टिकल काम करके सब काम के पीछे पड जावें तो सब काम अच्छा हो सकता है। पर आज इसके बिना कोई फल नहीं है इसलिये मुझे बडा अफ़सोस है। अगर ये कर लें तो यहां सारी चीजें कहने की जरूरत नहीं पड़े।

माननीय उपाध्यक्षजी, दूसरी चीज़ यह है कि सरकार ठेकेदारों से काम कराती है।

श्री उपाध्यक्ष ; इस पर तो आपने पहले वक्तव्य में बहुत कहा है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : कहां कहा महाराज ? कहा ही नहीं महाराज।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : हर भाषण में ठेकेदार की बात आती है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : वह तो क्वेश्चन पूछा था मैंने। तो माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान सरकार को चाहिये कि डिपार्टमेंटली काम करावे। इससे काम मजबूत होगा, रिश्वतखोरी बन्द होगी, देश की उन्नति होगी और जनता में राजस्थान गवर्नमेंट की उन्नति होगी। पी. डब्ल्यू. डी. की तरफ से बैराठ तहसील में १२ लाख का काम करवाया, जो जाता है उसकी तारीफ

Page No 47

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

करता है। काम तो अच्छा हुआ, कम से कम यह तो हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका ख्याल है, कानून भी डिपार्टमेन्टली बनावें।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह तो नहीं, पर काम डिपार्टमेंटली करावें। मैंने पहले भी कहा था जितना सामान खरीदा जाता है, टेन्डरों के द्वारा खरीदा जाता है। वैसे नहीं खरीद कर इन्डियन स्टोर, न्यू दिल्ली से खरीदा जावे।

श्री उपाध्यक्ष : आप उसके मैनेजर से मिले हैं क्या ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : अजी, वह तो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का है। मेरे घर का थोड़े ही है।

(हंसी)

और लोग करते होंगे, मैं थोड़े ही करता हूं ये बातें।

(हंसी)

वह तो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का है, इण्डियन स्टोर नई दिल्ली में है। उसमें भारत सरकार का रुपया लगा है न कि किसी पार्टी का। पी० डब्ल्यू० डी० तो काफी सामान मंगाती है पर दूसरे डिपार्टमेंट वाले नहीं मंगाते हैं। मेरा यह कहना है कि जितना सामान सरकार को चाहिये उससे मंगाना चाहिये। इससे आज जो गड़बड़ियां होती हैं, झगड़े पड़ते हैं लाखों रुपये लैप्स होते हैं। तो, इस तरह से सरकार करेगी तो इससे सरकार को ज्यादा फायदा होगा।

आपने मास्टरों का रुपया बढ़ाया। पर पटवारी को भूल गये। मुख्य काम काश्तकार के सम्बन्ध का गिरदावरी का जिसके झगड़े हाई कोर्ट तक चलते हैं वह यह पटवारी करता है और कम पैसा मिलने से गड़बड़ी करते हैं और इस वजह से वह मामला हाई कोर्ट तक जाता है, सरकार भी हैरान होती है और किसान भी बड़ी तकलीफ पाते हैं। तो उनको भी इतनी तनख्वाह तो मिलनी ही चाहिये। जब भरपेट खाना नहीं मिलेगा तो चोरी तो करेगा ही। तो इसके लिये सरकार को सोचना चाहिये।

(समय सूचक घंटी)

श्री मुक्तीलाल मोदी : पांच मिनिट और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : सिर्फ एक मिनिट।

श्री मुक्तिलाल मोदी : नहीं महाराज पांच तो दे दो। आपकी बात तो मानता ही हूं।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : शुरू रखिये, शुरू रखिये। दो मिनिट।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो माननीय उपाध्यक्षजी, जैसे कि आज इन्दिरा नेहरू, नहीं इन्दिरा गांधी ने भी और विनोबाजी भी कहते हैं कि समाजवाद लाना है पर जहां समाजवाद है वहां बात यह है रशिया में क्या दूसरी जगह क्या टैक्स पब्लिक पर नहीं

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

होते। कोआपरेटिव सोसायटी हैं उनका तो ठीक है प्रोत्साहन देंगे। परन्तु मेरा निवेदन है कि आप सब लोग अपनी अपनी कॉन्स्टीट्युएन्सी में पूरी तरह से काम करेंगे तो यह काम हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आपने पहले कह दिया है। इसको काहे को दोहराते हैं। अब मेरा खयाल है आसन ग्रहण करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : और शिक्षा के लिये यह है कि खेतड़ी ठिकाने के लोगों को ले लिया पर सरकार ने उनका फिक्सेशन आज तक नहीं किया। वे परेशान हैं, ५४ से। तो दूसरी जगहों के फिक्सेशन हुए वहां के नहीं हुए। यह क्यों ?

औषधालय ज्यादा खोलने के लिये राजस्थान सरकार ने लम्बा-चौड़ा बज़ट बनाया। इसका प्रोविजन पूरी तरह से नहीं किया। डिस्पेन्सिरियां कम खोलें तो औषधालय तो खोलें जिससे जनता को फायदा तो हो। इस में राजस्थान सरकार को काफी रुपया मंजूर करना चाहिये था। मेरी यह, माननीय मुख्य मन्त्रीजी से और सबसे प्रार्थना है कि आप इन सारी बातों पर ध्यान देंगे और राजस्थान की उन्नति के अन्दर लग जावेंगे। नहीं तो, आज नहीं तो कल, आदमी का दिन तो आता ही है।

मेजर फतेहसिंह (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिवर्ष इस सदन के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाता है और यह एक वैधानिक पवित्र प्रणाली है लेकिन हमारी सरकार इसको पवित्र प्रणाली नहीं समझती है वह तो इसको केवल रस्म अदायगी ही समझती है। जैसा कि इस समय सदन को प्रतीत हुआ होगा कि हमारे मंत्रिमण्डल में से सिर्फ दो ही सदस्य बैठे हुए हैं। बजट पर चर्चा हो रही है, और बड़े ही गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है लेकिन हमारे मंत्रीगण इस विषय पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं समझता हूं कि मंत्रीमण्डल की चंद रेस्पान्सिबिलिटीज़ हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जब बजट के ऊपर चर्चा हो रही हो तो वित्त मंत्री महोदय यहां उपस्थित न रहें।...

श्री उपाध्यक्ष : Let us now come to the question. It has already been discussed. It was raised by Shri Shri-BhanSingh and something has been observed.

मेजर फतेहसिंह : श्रीमान्, मैंने कहा था कि केवल रस्मअदायगी की तरह ही यह बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं आपका ध्यान फाइनेन्स मिनिस्टर की स्पीच के इंगलिश वर्शन के पेज नम्बर ३० की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। इसके आखिरी पैराग्राफ में लिखा है last but two lines में :

"Deserving students are given stipend and the expenditure chargeable to Revenue came financial assistance is given to the children and destitute widows from West Pakistan'"

इसका क्या मतलब है? इस सारी भाषा का क्या मतलब है, मैं नहीं समझ सकता It is preposterous, absurd and meaningless. इससे यह ज़ाहिर होगा कि हमारी सरकार इस बजट को पेश करने में कितनी सावधान रही है। सिर्फ किसी फाइनेन्स सेक्रेटरी ने या किसी सेक्रेटरी ने यह बजट स्पीच तैयार

(मेजर फतेहसिंह)

कर दी होगी और हमारे माननीय वित मंत्री महोदय ने उस पर हस्ताक्षर कर दिये होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, एक शताब्दी पहले अमेरिका के एक दार्शनिक राष्ट्रपति एब्राहिम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेन्ट आफ दी पीपुल बाई दी पीपुल फोर दी पीपुल। याने प्रजातंत्र का अर्थ होता है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, यह शासन इस सदन के चुने हुए प्रतिनिधियों की भावनाओं के मुताबिक चलना चाहिए लेकिन यहां पर जो चर्चा होती है उसके ऊपर हमारी सरकार अमल नहीं करती और जब मैं इस सदन में बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो मैं यह अनुभव करता हूं कि यहां पर बोलना अंधों को दर्पण दिखाने या बहरे के सामने ढोल पीटने के समान होगा। फिर भी अपने कर्त्तव्य से प्रेरित होकर मैं कुछ अपने विचार रखने की कोशिश करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण में भी बताया गया था और वित्त मंत्री महोदय ने भी बताया और कई मंत्री महोदयों ने भी बताया और बताते रहते हैं कि हमारे राज्य में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था सुधरी है। लेकिन यह बात कितनी निराधार मालूम पड़ती है। हमने देखा है कि जब जब अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम होते हैं तो जो राष्ट्र यह समझता है कि बाहरी आक्रमण का भय दूर हो रहा है, तो वह, राष्ट्र की सेना में कमी करते हैं। राष्ट्र के बजट में खर्च कम करते हैं लेकिन हमारे यहां राजस्थान का क्या हाल है। अगर हमारी शांति और सुरक्षा की व्यवस्था सुधरी होती तो हमारे पुलिस के बजट में कमी हुई होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टे यहां तो खर्चा बढ़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि चोरों और डकैतों की समस्या सुधरी है। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं हुआ है। मेरा यह अनुभव है और मैंने कई पुलिस कर्मचारियों को और पुलिस अधिकारियों को इस प्रकार की चर्चा करते हुए सुना है कि अगर डाकुओं और चोरों की समस्या कम हो गई और डाकू और चोर अगर सब पकड़े गए या मारे गए तो कल जीमने किस के घर जायेंगे। यह बहुत गंभीर बात है। हमारे पुलिस अधिकारियों को यह सोचना चाहिए कि जनता का हित सर्वोपरी है और उसके स्वयं का सर्विस में रहना या नहीं रहना एक गौण चीज़ है क्योंकि वह लोग सोचते हैं कि अगर डाकुओं और चोरों की समस्या हल हो गई यह सब पकड़े गए या मारे गए तो पुलिस फोर्स में कमी होगी और इससे उनकी बेरोज़गार होगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of Order, Sir. यह जो इस प्रकार की बात कह रहे हैं वह उन्होंने किस आदमी या किस पुलिस वाले से कहते सुनी। किन्होंने यह कहा कि चोर या डाकू नहीं रहे तो नौकरी से निकाल दिये जायेंगे? इसका डर कैसे हुआ?

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : I believe the Hon'ble member does not know what is the meaning of a Point of order'.

(अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : He was eliciting information.

मेजर फतेहसिंह : First You (Shri, Jwala Prasad) sit down. I don't want any interruption यह कहते मैंने उन्हें अपनी आंखों से सुना है।

(हंसी)

और किससे कहते सुना है, यह भी मैं बताने के लिए तैयार हूं। जबकि पुलिस के जुर्मों के कारण मेरी गिरफ्तारी हुई थी और जब मैं ले जाया जा रहा था तो पुलिस कर्मचारियों को इस प्रकार की बात कहते सुना। उस तरफ से मुझे आश्वासन मिले कि ऐसे आदमियों के खिलाफ एक्शन लिया जायेगा तो मैं नाम बताने के लिए तैयार हूं। मुझे सच्चाई से प्रेरित होकर कहने की यहां आवश्यकता हुई। अगर सरकार एक्शन लेने के लिए तैयार है आप उनको सस्पेंड करने के लिए तैयार हैं तो इस प्रकार के उदाहरण देने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन आप उनके खिलाफ डिसिप्लीनेरी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हैं और फिर फिजूल यों ही मेरे बोलते समय बाधा डालते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं कह रहा था कि हमारी पुलिस फोर्स को यह भय है कि अगर यह डाकुओं की समस्या हल हो गई तो यह स्वाभाविक है कि बेरोज़गारी होती है आखिर उनके भी पीछे कुनबा है, परिवार है लेकिन आवश्यकता इस बात की है, कि उनके हृदय में परिवर्तन होना चाहिए। कौटिल्य ने कहा था प्रजा सुखे सुखम राजः यह प्रशासन का आदर्श होना चाहिए। शासक को समझना चाहिए कि प्रजा के ही सुख में उसका सुख है। लेकिन इस प्रजा के सुख में ये अधिकारी अपना सुख नहीं समझते। वे तो व्यक्तिगत स्वार्थ को पहले सामने रखते हैं इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को और उनकी मार्फत आई० जी० साहब को यह सलाह दूंगा कि हमारे लोगों के चरित्र को ऊंचा बनायें। चरित्र के उत्थान की आवश्यकता है। कहते हैं कि सुरक्षा और शांति की व्यवस्था सुधरी है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या १॥ साल पहले माननीय मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र उदयपुर में एक विधवा बोरा महिला का कत्ल नहीं हुआ था। क्या करीब दो महिने पहले उसी शहर में एक और बोरा महिला का कत्ल नहीं हुआ था। क्या वे कत्ल करने वाले पकड़े गए हैं? अगर नहीं पकड़े गए तो क्या हमारी शांति और सुरक्षा की व्यवस्था के सुधरने का यही एक आदर्श है, यही एक नमूना है। जिसके लिए आप कहते हैं कि सुधार हुआ है, हमने शांति और सुरक्षा के मामले में उन्नति की है। ध्यक्ष महोदय, मेरे खुद के क्षेत्र में एक घटना हुई जिसकी मुझे याद आती है। करीब १॥ साल पहले एक बलाई का किसी खाती महिला के साथ बलात्कार करने के कारण कत्ल हुआ था। खाती गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला लेकिन उसका एक मात्र प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी में खाती की औरत थी जिसके साथ बलात्कार किया गया था। पुलिस से और मुलजिम के परिवार वाले मिल गये। पुलिस येन केन प्रकारेण उस खाती को बचाना चाहती थी क्योंकि इन्वेस्टीगेटिंग ऑफिसर श्री नारायणसिंह एस. एच. ओ. ने १५००) रु० रिश्वत खाई........

श्री उपाध्यक्ष : Whether the case is sub-judice.

मेजर श्री फतेहसिंह : No, Sir, it has already been finished. तो उस महिला को गायब कर दिया जाता है। वह इस संसार

(मेजर फतेहसिंह)

से न मालूम कहां भेज दी जाती है, भगवान जाने। और इस तरह से मुलजिम को बरी कराने में पुलिस का हाथ होता है क्या पुलिस के ऐसे ही कारनामों से शांति और सुरक्षा की व्यवस्था सुधरेगी, कभी नहीं सुधरेगी। उपाध्यक्ष महोदय, कल माननीय श्री अग्रवाल ने एक उदाहरण दिया था कि किस प्रकार से पुलिस अधिकारी जुडिशियरी में हस्तक्षेप करते हैं वह एक बहुत गंभीर मामला था तभी तो हम कहते हैं कि एग्जीक्युटिव का और जुडिसियरी का सेपरेशन होना चाहिये। कल माननीय अग्रवाल ने बताया था कि किस प्रकार एक एस. पी. ने डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखी कि जिस प्रकार से मुलजिम को राजसमंद के मैजिस्ट्रेट द्वारा छोड दिया गया है। उस मेजिस्ट्रेट का वह एक्शन अनडिज़ायरेबल था और किस तरह से एस. डी. एम. से जवाब तलब किया जाता है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत गृह मंत्रीजी से पूछता हूँ कि यदि यह बात सच है तो क्या वे उक्त एस. पी. के खिलाफ डिसीप्लेनरी एक्शन लेने को तैयार है और यदि वे इसके लिये तैयार हैं तो हमें प्रसन्नता होगी। नहीं तो हम सोचते हैं कि इस प्रकार की घटना होने में उनका हाथ भी रहता है। उनकी मिली भगत है मैं चाहूंगा कि ऐसे एस. पी. के खिलाफ डिसीप्लेनरी एक्शन लेने के लिये आप तैयार रहें। जहां तक न्यायालय में पक्षपात का प्रश्न है राजस्थान हाई कोर्ट को चाहिये कि उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला लगावे। यदि इस करह की बातें होती रहीं तो न्याय नहीं रहेगा और मेजिस्ट्रेट्स काम अच्छी तरह से नही कर पायेंगे। माननीय उपाध्यक्षजी, समय बहुत कम है इसलिये थोड़े से शब्दों में दूसरे विषयों पर भी बोलना चाहूँगा।

भारत सेवक समाज की मार्फत, ऐसा मालूम हुआ है कि, हमारी राजस्थान सरकार कुछ लाख रुपये खर्च कराना चाहती है। डवेलपमेंट के मामले में, आखिर जहां तक डेवलोपमेंट का प्रश्न है, हमारे यहां भी अलग विकास का महकमा है। फिर इस तरह दूसरा पेरेलल महकमा और बनाने की क्या आवश्यकता है। जो काम भारत सेवक समाज की मार्फत कराया जा सकता है वह काम हमारे डेवलपमेंट विभाग के बी. डी. ओज, डिप्टी डवेलपमेंट कमिश्नर वगैरा भी कर सकते हैं। आखिर भारत सेवक समाज क्या चीज़ है। यह एक प्रकार का द्योतक है। मैं एक सैनिक हूं और सेना में रहा हुआ हूं। यह आम प्रिन्सिपल है कि जब एक कमान्डर यह सोचता है कि हमारी पराजय होने वाली है तो वह अपनी सेकन्ड लाइन ऑफ डिफेन्स बनाता है। इसी तरह से कांग्रेस का सत्ताधारी दल अपनी सत्ता के प्रभाव को डूबता देख कर यह एक प्रकार की डिफेन्स लाइन बना रही है ताकि वहां आकर उसको शरण मिल सके। जिस तरह से एक डॉक्टर मरते हुए मरीज को इन्जेक्शन देकर थोड़े समय के लिये जिन्दा रख सकता है उसी तरह थोड़े समय के लिये कांग्रेस को जिन्दा रखने का यह केवल उपाय है........

श्री श्रीभानसिंह : I can assure you that we will survive the independence.

मेजर फतेहसिंह : I want an assurance not from you but from the Government :

श्री उपाध्यक्ष : Let there be no assurance, please.

मेजर फतेहसिंह : जहां तक राज्य के धन के उपयोग का प्रश्न है इससे उपयोग नहीं होगा दुरूपयोग होगा। इस सदन में कई मौकों पर जल बोर्ड द्वारा खर्च किये गये पैसे की चर्चा हुई है और मेरा ख्याल है कि जहां तक भारत सेवक समाज का प्रश्न है यहां भी धन का दुरूपयोग होगा, समानान्तर महकमा होगा और उसके कारण असन्तोष फैलेगा खास तौर से हमारे अधिकारियों में। आखिर क्यों यह काम किया जाता है? उपाध्यक्ष महोदय, सत्ताधारी दल के बहुत से लोग मन्त्री, उप मन्त्री बन गये हैं। कई प्रान्तों में बन गये हैं और कई सेन्टर में बन गये हैं। आखिर कुछ लोग ऐसे भी बचे हैं जिन्होंने संस्था की सेवा की है, उन्हें भी कुल लाभ मिलना आवश्यक है। इसलिये सत्ताधारी दल ने जो लोग उनकी चाटुकारी करने वाले हैं उनको भी भारत सेवक समाज की ओट में कुछ मिलेगा लेकिन इससे राज्य के धन का दुरूपयोग होगा इसलिये इस बारे में मुझे कहने का पूरा अधिकार है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि भारत सेवक समाज नोन पोलिटिकल बोडि है और दूसरी ओर अगर यह गैर सरकारी संस्था हैं तो उसकी मार्फत सरकारी पैसा क्यों खर्च कराया जा रहा है। आखिर भारत सेवक समाज में है कौन लोग ? इसमें ९९ पर्सेन्ट वे लोग हैं जो कांग्रेस के सदस्य हैं इस प्रकार से तो दूसरी पार्टीज़ भी अपनी संस्थाएं कायम करेंगी और राज्य के धन को खर्च करना चाहेंगी जो सिद्धान्त के खिलाफ है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां डवेलपमेंट का काम चल रहा है, विकास योजनाएं चल रही हैं, लाखों रुपये खर्च हो रहे है और खर्च को देखते हुए राज्य की जनता को उतना लाभ नहीं हुआ है जितना होना चाहिये, लेकिन क्या उसका कोई कारण है? प्रथम बात तो यह है कि जो हमारे बी. डी. ओ. आदि, जो वहां पर काम करने वाले है, वे अधिकतर लोग शहरों के रहने वाले हैं और उनको गांवों की हालत का, वहां के वातावरण का और वहां की समस्याओं का पूरा ज्ञान नहीं है वे तो सिर्फ अपनी तनख्वा से काम रखते हैं इसलिए विकास की जो योजनाएं हैं वे अच्छी तरह से कार्यान्वित नहीं होने पातीं। दूसरा कारण जो हमारे डवेलपमेंट प्लान्स हैं वे पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। उसका कारण यह है कि इस महकमें में आर. ए. एस. केडर, आई. ए. एस. केडर और रेवेन्यू के महकमे से लिये हुए कर्मचारी हैं वे सोचते हैं कि आखिर में हम को थोड़े समय बाद अपने आर. ए. एस., आई. ए. एस. या जहां से आये हैं वहां वापिस जाना है. यहां तो सिर्फ समय निकालना है इसलिये वे इस काम में दिलचस्पी नहीं लेते। इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि हम यह चाहते हैं कि डवेलपमेंट विभाग और विकास योजनाएं सफलता से चलें तो डवेलपमेंट के लिये यह आवश्यक हो जाता है और मैं चाहता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी इस पर विचार करें कि इसके लिये हमको डवेलपमेंट सर्विस का एक सेपरेट केडर बनाना चाहिये ताकि उसी महकमे में उनकी तरक्की हो और सब कुछ मिलता रहे और दूसरे महकमों से उनको प्रेरणा नहीं मिलती रहे और वहीं उनकी तरक्की होती रहे। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक डवेलपमेंट प्लान्स में सफलता मिलने का प्रश्न है

(मेजर फतेहसिंह)

यह जनता के सहयोग पर निर्भर करता है और जनता का सहयोग अधिकारियों और सरकार को तभी प्राप्त होगा जब कि हम जनता का विश्वास प्राप्त कर सकेंगे। जनता का विश्वास प्राप्त करना सरकार और अधिकारियों के लिये बहुत आवश्यक है और जब जनता का विश्वास सरकार खो देती है तो उसका परिणाम बुरा होता है। इस अवसर पर मुझे तुलसीदासजी की वह कविता याद आ जाती है जब जनता का विश्वास जाता रहता है या जिस राजा में जनता का विश्वास नहीं होता उस शासक का नाश होता है :

जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी,
ते नृप अवसि नरक अधिकारी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में रोटी-रोज़ी का बड़ा प्रश्न है और इन समस्याओं को हल करना भी हमारे लिये बड़ा आवश्यक है। मैं आपकी आज्ञा से दो मिनिट और लेना चाहूँगा। करप्शन के सम्बन्ध में इस सदन में आम चर्चा रहती है लेकिन करप्शन मिटाने का अब तक कोई हल नहीं निकाला गया है, यह बड़ा आवश्यक मसला है। हम यहां पर बोल लेते हैं और सरकार सुन लेती है। एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट इसको मिटाने में सर्वथा असफल रहा है। और करप्शन है, इसको सबको मानना पड़ेगा। मैंने तो अपने कानों से अदालत में अधिकारियों को यह कहते हुए सुना है कि लोग दो रुपये दे रहे हैं, अधिकारी महात्मा गांधी के फोटो की तरफ हाथ करते हैं जिस फोटो में महात्मा गांधी हाथ उठाये हुए आशीर्वाद की मुद्रा में हैं और कहते है अरे दो रुपये क्या देते हो, ५ रुपये देने का तो उनका आदेश है। यह हमारे राष्ट्रपिता का अपमान है, इसको रोकना चाहिये। यह क्यों हो रहा है ? जैसे पानी में प्रविष्ट मछली पानी पीती है पर पानी को पीती हुई नज़र नहीं आती, उसी प्रकार राज्य में काम करने वाले कर्मचारी, जनता से रिश्वत लेते हैं, जनता के धन का दुरुपयोग करते हैं, जनता को पीड़ित करते हैं, पर पकड़े नहीं जाते यह हमारे राज्य की कमजोरी है।

मैं करप्शन का एक बहुत बड़ा उदाहरण दूँगा, जो बहुत गम्भीर मामला है। ५७ के चुनाव समाप्त हुए। मई महीने के बोम्बे के ब्लिट्ज़ अखबार में मुख्य पृष्ठ पर निकला :

"To constitute Rajasthan Ministry 17 M. L. As' bought for five lakhs rupees."

यह बड़ी गम्भीर समस्या थी, बड़ा गम्भीर मसला था, उसके लिये हमारे सारे सदन को विचार करना है।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): माननीय उपाध्यक्ष, मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब किस रेफेरेंस से बोल रहे हैं, ये सारी बातें ?

श्री उपाध्यक्ष : Which newspaper, You are referring it ?

मेजर फतेहसिंह : Blitze of Bombay, sir ?

श्री उपाध्यक्ष : Is it with you ?

मेजर फतेहसिंह : I had given a notice of question and that question was never answered in this House.

(मेजर फतेहसिंह)

That was during October Session and the question no. was 114.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं इस बात पर सख्त एतराज करता हूं कि कोई अखबार बाहर बात कह दे, उसको रेफेरेंस करके माननीय सदस्य इस सदन में इस तरह की बातें करें जब तक कि माननीय सदस्य के पास उसके लिये वजूद न हों प्रमाण न हो।

मेजर फतेहसिंह : श्रीमन् मैं माननीय मुख्य मंत्री के प्रति श्रद्धा रखता हूं, उनकी इज्जत करता हूँ पर मैं उनसे चाहूँगा कि मुख्य मंत्री यह कह दें कि वह खबर गलत है। अगर गलत थी तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये था।

श्रीउपाध्यक्ष : The Hon'ble member will please not make any reference about a paper which is not with him.

मेजर फतेहसिंह : I had given that paper in the Assembly Secretariat one and a half year ago. It must be there.

श्री उपाध्यक्ष : I have given my observations and you will please conclude your debate...

मेजर फतेहसिंह : That is alright. If the Government does not want to listen to me, I have nothing to say more.

श्री उपाध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, आज हम वाद विवाद कर रहे हैं, ५९-६० का बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने भाषण दिया था, उस पर। माननीय उपाध्यक्षजी, जो बजट सदन में प्रस्तुत हुआ है उसके सम्बन्ध में अनेक लोगों ने अनेक रायें यहां दी हैं, पर हम अपने वित्त मंत्री को इस बात के लिये धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना बजट बचत का प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की और वह कोशिश इतनी की जितनी कर सकते थे, क्योंकि वे पुराने तजुर्बेकार व्यक्ति हैं, वे जानते हैं कि घाटे का बजट हुआ तो वह नुकसान देह है। कहावत है कि घाटा नमक का भी नुकसान देह है। पर लोग आलोचना करने से नहीं चूके, एक शायर तो यहां तक कह गया है :

जब अपनी तंगदस्ती की बजट ने आहोज़ारी की।
तो फाइनेन्स मिनिस्टर ने समय पर चारायारी की,

नतीज़ा यह हुआ कि सेठों का
इज़ारा तो रहा कायम
और बढ़ा कर भाड़ा मोटरों का
किसानों की जानमारी की।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : ये शायर स्वयं आप हैं?

डॉ० बहादुरसिंह : नहीं साहब, दूसरा है। मैं तो कहने वाला हूं।

माननीय उपाध्यक्ष, यह एक गम्भीर बात है, हम कोशिश करते हैं कि हमारा खर्चा कम हो और हमारा बजट सरप्लस हो, यह शायर के दिल की टीस थी, वह उसने रखी है। फाइनेन्स मिनिस्टर किसी बड़े सेठ पर, अमीरों पर टेक्स लगाने में मजबूर थे, वे देखते हैं कि गरीब आदमी जिसके पास आने जाने के साधन नहीं है, जिसके पास कोई

(डॉ० बहादुरसिंह)

मोटर नहीं, और जो साधन हैं उन पर टैक्स लगा दें। फिर कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीयकरण करने जा रहे है। और राष्ट्रीयकरण के लिये ३० लाख रुपया रखा है। क्या इतनी बड़ी योजना के लिये वे इतनी सी रकम को पर्याप्त समझते हैं। थोड़ा भी राष्ट्रीयकरण करने का सोचते तो आपको टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आपका बजट काफी सरप्लस होता।

फिर आप इस बात पर नहीं सोचते कि टैक्स किस पर लगाना चाहिये और किस पर नहीं लगाना चाहिये। आप मद्य पर टैक्स लगाते हैं जब कि हमें मद्य निषेध करना है। मैं बताऊं कि किस प्रकार शराब का प्रचलन हमारे यहां बढ़ रहा है और हमारे अधिकारियों में बढ़ रहा है, और इसके लिये प्रमाण देता हूं, आंखों देखी बात बताता हूँ। हमारे यहां एग्ज़ीक्युटिव आफीसर म्युनिसिपेलिटी के हैं, शाम को ७ बजे बाद आप कभी उनके पास जाइये तो शराब पिये हुए मिलेंगे।....

श्री उपाध्यक्ष : Why to discuss a person here. We are discussing the principles of budget. Why to drag him who is outside the House?

डॉ० बहादुरसिंह : तो मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे अधिकारियों में किस प्रकार शराब का प्रचलन बढ़ रहा है और बराबर बढ़ता जा रहा है। फिर हम इस बात की कोशिश करते हैं कि राजस्थान में शराब-बन्दी हो, पर किस तरह से शराबबन्दी होगी, यह हमें सोचना है।

इसके साथ ही वित्त मंत्रीजी पुलिस पर विशेष कृपा करते हैं। जनता की गाढी कमाई में से राज्य के बजट का ६ प्रतिशत पुलिस को देना स्वीकार कर लिया है। गृह मंत्री जी अक्सर शिकायत करते हैं कि लोग पुलिस की आलोचना ज्यादा करते हैं पर मैं पुलिस की आलोचना नहीं करूंगा क्योंकि धौलपुर में सुख शान्ति है, जो अजीतपुर में डकैती हुई, वह पुलिस की गलती से नहीं हुई, जो डाका वहां पड़ा राजनैतिक कार्यकर्त्ता होने के कारण उसके वहां डाका पड़ा, पुलिस तो कोशिश कर रही है कि डाकेजनी को रोका जाय, पर दुर्भाग्य की बात है उस राजनैतिक कार्यकर्त्ता की कि उसके वहां डाका पड़ा। तो वित्त मंत्रीजी को इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या ही अच्छा होता कि ६ पर्सेन्ट की बजाय एज्यूकेशन का सारा धन जो एज्यूकेशन के लिये अलाॅट किया है वह सारा का सारा धन पुलिस को अलाॅट कर दिया होता।

आज राजस्थान शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, पर शिक्षा की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति शायद प्रत्येक कार्यकर्त्ता और जो प्राइमरी सेक्शन्स के टच में हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि प्राइमरी स्कूलों की क्या हालत है? हम शिक्षा के स्तर को सुधारना चाहते हैं पर किस प्रकार सुधारें, जब तक शिक्षक चरित्रवान् नहीं होंगे तब तक हम शिक्षा में सुधार नहीं कर सकते। एक नजीर में रखूंगा, नाम नहीं बताऊंगा, एक केस की तरफ ध्यान आकर्षित करुंगा। डायरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन एक शिक्षिका को सस्पेन्ड कर देते हैं, किस कारण से? वे कारण फाइल में मौजूद हैं पर एज्यूकेशन सेक्रेटरी स्टे आर्डर दे देते हैं। क्या बात है, एक तरफ तो चरित्र की बातें कहते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की कार्यवाही करते हैं?

(डॉ० बहादुरसिंह)

इसके साथ ही में यह कहना चाहूँगा कि २२ प्रतिशत जो शिक्षा के लिये अलॉट किया गया है इसका वास्तविक उपयोग नहीं किया गया तो हम तरक्की नहीं कर पायेंगे।

विकास की बातें हैं उनकी तो मैं सराहना करता हूँ। हम देखते हैं कि विकास के कामों में काफी प्रगति की है, तीन से चार पर्सेन्ट बढ़ गया है। विकास के कार्यों में खर्चा कर रहे हैं पर हमारा प्रशासनिक खर्चा है वह तो १७० पर्सेन्ट पहुंच गया है। यह भी जरा एक सोचने की बात है। क्यों? एक तरफ खर्चा बढ़ रहा है और कहां तक बढ़ायेंगे, कहां तक टैक्सपेयर पैसा देगा? यह सोचना पड़ता है। सार्वजनिक तौर पर लोग आलोचना करते हैं कि इस शासन में हर बात पर टैक्स है, जिन्दा होने से मौत तक टैक्स लिया जाता है। कहा यह जाता है कि विकास करना है तो टैक्स लेना है। लेकिन लेने का कोई तरीका भी तो हो। आमदनी बढ़ा लें और फिर लें तो कोई बात हुई। मैंने कई बार निवेदन किया था कि धौलपुर का यदि पार्वती बांध बन जाता तो आज तक कितनी आमदनी हो जाती। लेकिन उसका टाइम बराबर बढ़ रहा है, सुरसा की तरह बढ़ रहा है। जिन मदों पर खर्चा कर रहे हैं, वे तो हम कर ही रहे हैं लेकिन जो आमदनी के सीगे हैं उनको ढीला कर देते हैं। इसी तरह से मैं आपको इलेक्ट्रिक के लिए बताऊं कि यह आमदनी का जरिया है लेकिन क्या इसकी स्थिति है। राजस्थान की आमदनी बढ़नी चाहिये वह नहीं बढ़ रही है। हो सकता है कि यदि पावर हाऊसेज़ ठीक होते तो उद्योग धन्धे भी चलते, उससे सेल्स टैक्स की रकम भी कुछ बढ़ती। 'स्टेटिस्टिक्स स्टडी' है उसमें उद्योगों के लिए बड़े सुन्दर आंकड़े दिये गये हैं। ग्लासेज़ के लिए बताऊं कि सन् ५२ में १५६ टन उत्पादन किया, सन् ५३ में २०४ टन किया, ५४ में ३८४ टन किया और ५५ में ५४० टन उत्पादन किया। जब तक धौलपुर पॉवर हाऊस बराबर वर्क करता रहा तब तक उत्पादन भी बढ़ता रहा। आज राजस्थान में धौलपुर ग्लास वर्क्स के उत्पादन के मुकाबले में और कोई नहीं है। उसने सन् ५६ में ८१६ उत्पादन किया लेकिन जैसे जैसे पॉवर हाऊस ढलता गया और जैसे जैसे राजस्थान सरकार की विशेष कृपा होती गई, वैसे २ ग्लास उत्पादन के आंकड़े भी ढलते गये और सही स्थिति यह है कि जहां सन् ५७ में ६६६ टन का उत्पादन हुआ वहां ५८ में ६८४ टन का उत्पादन हुआ। मैं केवल ग्लास की बात नहीं करूंगा, यदि आप कॉटन क्लाथ की बात देखेंगे तो उसमें भी तीन हजार कम उत्पादन हुआ है। हम उत्पादन की बात करते हैं और कहते हैं कि पहले से वृद्धि हुई है लेकिन हमारे जो प्रस्तुत आंकड़े हैं वे इस बात के गवाह हैं कि हम इस बात की कोशिश नहीं करते कि उत्पादन बढ़े और जो लाभ होना चाहिये वह नहीं हो पाता। इसी तरह से हमारे और भी उद्योग हैं। हमारे मेडिकल व्यय में भी काफी कोशिश की गई कि वह बढ़े और काफी बढ़ाया। लेकिन इसकी समस्याएँ अनेक हैं, जैसे डाक्टरों की कमी। हम केवल डाक्टरों की कमी की बात तो करते हैं लेकिन बीमारी से निरोग होने की बात नहीं करते, बीमारियां हैं उनको रोकने की कोशिश नहीं करते। मुझे खुशी हुई थी इस बात की कि पिछले बजट भाषण में वित्त मंत्री महोदय ने बताया था कि हम योग आश्रम कायम कर रहे हैं लेकिन इसमें नदारद है।

श्री जनार्दनराय नागर : कुष्टाश्रम।

डॉ० बहादुरसिंह : अजमेर के कोढ़ियों के लिए ही।

(हंसी)

हमारे मेडिकल पर ५६.९ पर्सेन्ट का एक्सपेन्डीचर है। सबसे पहले तो यह आवश्यक था कि जनता के स्वास्थ्य का सुधार किस प्रकार हो। यदि एक्सपेन्डीचर को निरोध में लगाते तो उससे लाभ तो होता। एक तरफ तो हमारे मेडिकल के एक्सपेन्डीचर में बढ़ोतरी हुई है और हो रही है और दूसरी तरफ बीमारियां भी बढ़ी हैं और बढ़ रही हैं। फिर यह और किया कि लोगों को आॅलकोहल पिला कर ८ लाख रुपया और वसूल कर लें और उनके स्वास्थ्य में वृद्धि करें और लोगों में एनरजी हो कि अधिक से अधिक पैदा करें।

(घंटी)

और भी खर्च हैं जो लम्बे चौड़े हैं। लेकिन मैं उनको धन्यवाद दूँ कि डवेलपमेन्ट के ऊपर एक्सपेन्डीचर काफी बढ़ा कर रखा है। हमारे विकास पर ज्यादा खर्च करना चाहिये, यह ठीक है। लेकिन टार्गेट जो केन्द्र बिन्दु है उस पर कितना पहुंच पाते हैं, उस पर ही यह सब डिपेन्ड करता है। इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम डवेलप्मेंट की जो योजना है उसको पूरा नहीं कर पाते तो इसका मतलब यह है कि हम पीछे रह जावेंगे और मंजिल पर पहुंचने में नाकामयाब रहेंगे। मैं ज्यादा न कह कर....

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member, you will not persuade the matter. I am here to see all this,

श्री जनार्दनराय नागर : I was simply whispering him.

डॉ० बहादुरसिंह : मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि हमारे जो टार्गेट हैं वहां तक पहुंचने की भरसक कोशिश करनी चाहिये।

अब मैं मेरे विशेष विषय आयुर्वेद के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इस भाषण में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि राज्यपाल महोदय के भाषण में आयुर्वेद के विषय में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है इसलिए वित्त मन्त्री महोदय इसको उठाये। लेकिन इसमें भी नदारद। उन्होंने कहा था कि वैद्यों की तनख्वाह बढ़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो कट मोशन में आ जावेगा ?

श्री जनार्दनराय नागर : यह बहुत महत्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आपने तो जिक्र नहीं किया।

डॉ० बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद की जो स्थिति है वह बहुत ही दयनीय कर दी गई है। इसलिए या तो इसको अधिकारी गण पसन्द नहीं करते और चाहते हैं कि आयुर्वेद ही न हो तो मैं पसन्द करूंगा कि आयुर्वेद डिपार्टमेंट को खत्म कर दीजिये। जब राज्य शासित चीज़ नहीं रहेगी तो जनता अपने आप जिनको इसमें विश्वास होगा, पकड़ रखेगी इसको पनपायेगी लेकिन यदि आप चाहते हैं और जनता चाहती ही है कि

(डॉ० बहादुरसिंह)

आयुर्वेद उनकी वास्तविक चिकित्सा है और पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जनता इससे फायदा उठायेगी, राज्य को अधिक खर्चा करना चाहिये। लेकिन जो प्रस्तुत आंकड़े हैं उनसे प्रकट होता है कि आयुर्वेद पर एक्स्पेन्डीचर बराबर कम कर रहे हैं। किस प्रकार की दयनीय स्थिति उन गरीब वैद्यों की है जो औषधालय में आज काम करते हैं।

(घंटी)

इसके अलावा भी आप देखते हैं कि जहां जहां सरकार ने औषधालय खोले हैं ऐसा कोई स्थान नहीं मिलेगा कि जहां वैद्य न पहुंचे हों और चिकित्सा को दिल लगा कर न किया हो।

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय ज्यादा प्रेस कर रहे हैं इसलिए मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि गरीब वैद्यों के वेतन स्तर में सुधार करिये जो कि राज्य सेवा में लगे हुए हैं, जो जनता कि सेवा करना चाहते हैं उनको कम से कम आयुर्वेद बोर्ड द्वारा रिकमेन्ड किये हुए वेतन स्तर हैं, उनको वे दीजिये, आप उसको स्वीकार कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : राजा मानसिंह।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, कई दिन हो गये उठते-बैठते, लेकिन बोलने के लिए आज्ञा ही नहीं दी जा रही हैं आपकी ओर से।

श्री उपाध्यक्ष : राजा मानसिंह।

२.०० म० प०

राजा श्री मानसिंह (वेयर) : Mr. Deputy Speaker, Sir. I congratulate the Finance Minister on this Budget because I feel that he does not lack in the imaginations. He took a lot of imagination to draw and find out exactly how this budget is a surplus one. He has also taken a lot of imagination to try and find out what scheme the Government have in time to pay the Central Govt. loan which amounts to nearly three times, of the revenue receipt.

He takes a lot of imagination to draw and figure out how this budget is not antiagriculturist. For the last seven years, Sir, the budget being put forward by the Congress Government have been always anti-agriculturists. From new taxes to the figure of 58 lacs which have been proposed more than 50 lacs are to be realised directly or indirectly from the Agriculturists, in the form of 8 lacs on account of irrigation rates, 12 lacs on betterment levy, 8 lacs on excise duty and 30 lacs on Motor Vehicles. Whether these taxes will be realised to the extent of his imagination, Sir, remains to be seen. However, going through the speech, I have come across so many contradictory proposals which make me feel that there is doubt whether these taxes will be realised or not. There has been a mention that Rs. 25 thousand are to be placed at the disposal of the Social Welfare for the extensive prohibition propaganda. On the other hand Sir, we expect

(राजा श्री मानसिंह)

income from the Excise duty of 8 lacs. If this amount of Rs. 25 thousand is to be placed there, then it is hard for me to understand how can we expect full realisation of the taxes proposed. There are two ways of budget Sir. One is to increase the taxation, to meet the expenditure and the other is to reduce the expenditure to have less taxation. Our Congress Government is following the first way of budget. Here I don't want to suggest the reduction of expenditure. We have been told that the budget is going to be surplus by 19. '59 lacs. A surplus budget is not always a sign of good Government and, therefore, I suggest that this surplus should be turned into relief to the agriculturists and the betteament levy from which the Government proposes to increase their revenue by 20 lacs, should be given as relief. On the one hand Sir, the Government proposes to increase taxation on agriculturists and then on the other hand the Government proposes to bring down the prices of foodgrains especially at the time of harvest, which means the farmer will get less and will have to pay more in taxes. I feel, Sir, that the Government should take the respon-sibility to see that the prices of food grains do not fall to certain extent that it is disadvantagious to the agaiculturists

Regarding the new taxes on the motor vehicles carrying passengers and goods, I don't agree with it. But not agreeing with it Sir, I also know that the Government will have no intention of heaiing us in this house. These taxes can easily be avoided if there is a saving in the expenditure where there is so much wastage. However, I would like to point out that our carriers which ply especially to U. P. do not compete with the vehicles of that State plying in our State. U. P. buses which takes special permits to come in Rajasthan are charged only 10/- per running and all our vehicles which are required to go to U. P. have to pay heavy taxation. In public carriers on Agra-Bharatpur route our public carriers which have been given permits are not allowed beyond the means of Agra whereas the U. P. buses are allowed to come beyond Bharatpur route upto Jaipur. I feel, Sir, that the Government should pay some attention to this to safeguard the interests of the public vehicles of our State. I understand that the Government have got some sort of agreement with the Governments of Madhya Pradesh and Punjab that vehicles plying between Punjab and these States will not be required to pay tax. Similar thing should be done with the Government of U. P.

Going through the speech under the head 'Agriculture', I challenge the figures that have been put forward by the Hon'ble Finance Minister. We are told that there will be ten per cent increase in the Rabi grains,

(राजा श्री मानसिंह)

25 percent increase has been made in the consumption of Fertilisers etc. We have been told that five lac acres of land have been benefited through Bunding under the Medhbandi campaign.

Elsewhere in the speech, Sir, we are told that food production potential for the year 1959-60 is to be 2.5 lakh tons more than that of the year 1958-59. Taking into consideration all these figures, Sir, I would like to know why there is a food shortage in Rajasthan. It is quite obvious, looking at these figures that they are completely hypothetical and absolutely exaggerated.

I wouid like to demand, Sir, that Government should form an Evaluation Committee of the members of opposition to go into the matter of these figures. The Hon'ble Finance Minister has had very little opportunity in the speech to mention much about co-operative societies. Only one small paragraph has been devoted-specially when the Government policy is to change the whole economic structure of the society through co-operative societies. I have spoken in the House before on the position of societies and here I would like to mention that the Government feel that good work is being done only by advancing huge loans to these societies. This year we propose to advance loans amounting to Rs. 7.73 crores. There is no mention, however, Sir, as to what the Government proposes to do regarding the recovery of these loans. Public money is being given to societies irrespective of whether they work or not. Thus, public money is tied up which could be used for more productive work.

In the budget itself, Sir, there has been an increase in the budget provision shown under heading 'Direction and Superintendence of theSocieties'. It is twice the amount which the Government proposes to give in grants-in aid. It is a very interesting point Sir.

It is not clear where we are going after the introduction of ceilings on land holdings. For the surplus land, 'parat', for co-operative farms, we find under the heading 'Grants-in aid' that only 2 lakh rupees have been earmarked. If the Government seriously wish to hold the country into a ditch by forming Co-operative farms which will lead to collective farms. then atleast they should make an effort to improve the Co-operative epartment and make an effort to see that Co-operatiye farms function properly.

In Social welfare, we have been told that the Government is doing a lot of good work by constructing schools, hospitals and Panchayat Ghars. Most of these buildings that are constructed by the Social welfare Department are through the agency of Bharat Sewak Samaj. The work

(राजा श्री मानसिंह)

is done so badly that within a short period the buildings fall down and the public money is wasted. The result is that the amounts have to be sanctioned again for construction of these buildings. I would like to suggest that instead of giving Bharat Sewak Samaj the responsibility of constructing buildings for the Social Welfare Department, the work should be given to reliable contractors and there should be proper supervision by the department, so that public funds are properly utilised and not wasted.

A large part of the speech, Sir, is devoted to the rehabilitation of displaced persons. I agree, Sir, that help should be given to the displaced persons. We are told that displaced trainees are given stipends during their training period. But the trainees mainly take up this training only to get stipends and when their training period is over, most of them do not take up the vocation in which they have been trained. Only two percent of the trainees take up the vocation for which they have taken training. There is no follow-up programme, Sir, and I would like to suggest that the Government should look into the matter and have a follow-up procedure.

Both in the Governor's address and in the budget speech we have had mention of democratic decentralisation. The Government intends to form Jila Parishads, Panchayats Samities etc. by 2nd October, 1959. From what we have learnt from the discussion on the Balwant Rai Mehta Committee Report in this House we feel that these Zila Parishads and Panchayat Samities will be nothing more than Development Committees at the Block level or at the District level as they exist today. The Governor himself in his address has mentioned that these commitees would be only of advisory nature. Our Congress Government is very fond of using phrases such as socialistic pattern of society, democratic decentralisation, etc. which in fact they cannot define themselves. It is a fact, Sir, that District Boards, Tehsil Panchayats and Village Panchayats as they exist today, have been stripped of their powers by the formation of these Parishads and Samities.

The law and order situation requires mention specially when there has been an increase of nearly 24 lakhs in the Police budget. We have been told again and again that the law and order situation in Rajasthan is improving. Previously I had mentioned a few cases about the law and order situation in our State. I would now like to mention a few more instances which have occured in only half the district of Bharatpur. On 10th February, six thefts took place in one mohalla in Bharatpur city. On 13th February, a dacoity took place at village Babula. On 14th February, a theft took place at village Gunsara in which 3000/-were stolen. On 15th February a theft took place at Talpura in which 2000/- were stolen. On 16th

(राजा श्री मानसिंह)

February a theft took place in Kaunrer where Rs. 20,000/- were stolen and on the 17th February, a theft took place in Samai Khera where Rs. 3,000/- were stolen. On the night of 20th and 21st Feb. 2 dacoities took place in which two were killed in villages Parahi and in the market of Jurehra. These are few instances which I have given date-wise as to the law and order situation in our district. What takes place in the remaining 25 districts of Rajasthan, I do not know. But if this is an example, I think, Sir, our law and order situation is getting worse.

Without going into the merits of the unification of the High Court, I would like to say that the people of Alwar and Bharatpur are much troubled by the unification of High Court, as a result of which cheap and quick justice has been denied to them. There is no doubt, Sir that the Bench at Jaipur was very convenient to us and now, that the agitation is over, I feel that there is no justification for the Government to make it a prestige question. They should reconsider their decision to have a Bench of High Court at Jaipur. If the Government are reluctant to do this, then I would suggest that they should atleast order that the pending cases which were at Jaipur Bench before, should be heard at Jaipur.

Finally, Sir, coming back to the budget, I feel that there has been no mention regarding the dividends from our investments of Rs. 283.52 lakhs in shares etc. in 204 different concerns. I would like to know, Sir, how these public funds are safeguarded. I would also like to know that who recommends this money to be invested and in which concerns. I am sure, Sir, that if an impartial enquiry was made into this affair of investments in these concerns, many Mundhras will be found in this State also.

श्री परसराम (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि हम उत्तरोत्तर समाजवाद की ओर बैराबर बढ़ रहे हैं। मैं भी इसे महसूस कर रहा हूँ। जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं, अगर उनको सामूहिक दृष्टि से देखा जावे तो एक ही नतीजे पर पहुंचेगें कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह वास्तव में हमारे लक्ष्य की ओर ले जाने वाला है। योजना पर अधिक पैसा हम खर्च कर रहे हैं जिसका असर राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता के रहन सहन के स्तर पर पड़ने वाला है।

जो पिछड़ा प्रदेश था वह धीरे-धीरे पिछले दो बरसों में आगे बढ़ा है और आंकड़ों से पता लगता है कि आर्थिक स्थिति हमारी सुदृढ़ है और भविष्य में ऐसा लगता है कि हमारी हालत सुधरेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मनुष्य को पांच चीजों की मुख्य आवश्यकता है। खाने की, पीने की, मकान की, चिकित्सा की और शिक्षा की। इनको ध्यान में रखते हुए अगर हम बजट के प्रावधानों को देखें तो राजस्थान के लाखों

(श्री परसराम)

वासी को सम्यग् सुविधाएं मिलने वाली हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है ।

मैं खास तौर से दो तीन मुद्दों पर विचार करूंगा । सर्व प्रथम सिंचाई योजना पर कहना पसन्द करूंगा । इस मद पर १२ करोड़ से ऊपर रकम रक्खी गई है । मेजर, मीडियम और माइनर इर्रिगेशन पर । मेजर मीडियम वर्क्स से हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और दो चार सालों में हजारों एकड़ भूमि सिंचित होने को है । इसका असर वहां के रहने वालों पर पड़ेगा ।

पर माइनर वर्क्स पर ५० लाख का प्रावधान है । यह राजस्थान के विशाल इलाके को और मेजर और मीडियम के अन्तर्गत आने वाले हिस्से की न्यूनता को देखते हुए बहुत कम है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत वित्त मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि राजस्थान के बहुत से इलाके में मीडियम और मेजर की पोसिबिलिटी नहीं है । इससे बहुत बड़े इलाके को बड़े वर्क्स का फायदा नहीं मिलने वाला है । आपने माइनर के लिये काफी बन्धन भी लगाये हैं रिजिड रूल बनाकर कि २॥ तीन पर्सेन्ट रिटर्न आना चाहिये ।

जोधपुर डिविज़न के माइनर वर्क्स का सर्वे हुआ था पहले और वह इसलिये नहीं अन्डरटेक किया जा रहा है कि वहां रिटर्न कम होने वाला है । मैं अर्ज करूं कि माइनर इर्रिगेशन वर्क्स को रिटर्न के हिसाब से मत देखिये । उस एरिया की एसेस प्रॉस्पेरिटी कितनी होने वाली है और आसपास के इलाके में इससे कितनी सुविधा मिलने वाली है, इसको देखें । अगर इसको नहीं देखेंगे तो इससे ऐसा आभास होगा कि आपकी योजनाबद्ध तरीके में खामी है ।

इसके बाद स्वास्थ्य के मद को लीजिये । वाटर सप्लाई के सब हैड में दो तरह के प्रावधान हैं । एक अर्बन और दूसरा रूरल । अर्बन एरिया के लिये बीकानेर वालों ने विचार प्रकट किया था कि ५७—५८ में सात लाख का प्रावधान था, ५८—५६ में ३० लाख का और इस साल ६० लाख का है । इसके लिये धन्यवाद दिये वगैरह नहीं रहूंगा पर अर्ज करूंगा कि राजस्थान का २।३ हिस्सा पीने के पानी की समस्या से पीड़ित है । अगर इस समस्या को सारे राजस्थान के साथ, उसकी प्रगति के साथ रख कर हल नहीं सोचा गया तो इस इलाके के लोगों का जीवन स्तर दूसरों से नीचे ही बना रहेगा । आज वे पन्द्रह-बीस और तीस-तीस मील से पीने का पानी लाते हैं । ८ महीने पानी लाने का ही धन्धा रह जाता है । इतनी बड़ी लेबर इस तरह से वेस्ट जाती है । जहां आप मेजर और मीडियम वर्क्स से वहां के लोगों का जीवन स्तर उठाने जा रहे हैं वहां आप इनके जीवन स्तर का अन्दाज लगाइये ।

सरकार ने इसके लिये एक पर्मानेन्ट फेसिलिटी देने के लिये एक कमेटी बनाई है जिसका मैं भी एक सदस्य हूं । दो तीन महीने में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले हैं । अन्दाज़ है मेरा कि वह कमेटी पचास, साठ करोड़ की डिटेल्ड स्कीम प्रस्तुत करेगी पर अगर आप जिस तरह से प्रावधान रखने जा रहे हैं वही रखते रहेंगे तो इससे हम यही समझेंगे कि आपकी योजना में कहीं कमी है

(श्री परसराम)

यह इस बात का द्योतक है। अगर यह चीज आज आप नहीं लेते हैं तो वह बीस साल में पूरी नहीं होने वाली है। एक हिस्सा पीछे रह जाय और दूसरा आगे बढ़ जावे तो यह योजना नहीं कहलाती है।

जहां तक रूरल वाटर सप्लाई का सवाल है इसमें जो इनकम्पलीट पड़े हैं वे लोकल फण्ड की कमी से अधूरे पड़े हैं। इनको पूरा न किया जाकर दूसरों को ले लेना यह भी योजना के योजनाबद्ध न होने का सूचक है।

अब मैं पुलिस की मद पर आता हूं। इसके बारे में कल उस ओर बैठने वाले मेरे माननीय सदस्य ने काफी आलोचना की और इसमें एक ही खास कारण था कि जब राजस्थान में सुरक्षा और व्यवस्था की स्थिति सुधरी है तो ज्यादा रकम अब क्यों रक्खी। अगर एस्टीमेट को ध्यान से देखते तो एक चीज़ मिलती है जो मैंने देखी है। एन्युअल इन्क्रीमेन्ट की वजह से ८० हजार की वृद्धि हुई है। इसको रिडयूस करते हैं तो पिछले साल से चालीस लाख कम का यह बजट है। इस एन्युअल इन्क्रीमेन्ट से महंगाई का मुकाबला वे कर सकेंगे और स्टेन्डर्ड भी ठीक कर सकेंगे। इसके अलावा राजस्थान में बहुत बड़ी लाइबिलिटी भी हमारी है। ७०० मील लम्बी बॉर्डर की देखभाल भी हमें करनी है। इसमें तस्कर व्यापार होता है, डाकू शरण लेते हैं। तो इसकी रोक थाम और निगरानी के लिये ५—६ हजार की पुलिस रक्खी जाती है। इनका एडीशनल खर्चा देखते हुए और ये सब कारण देखते हुए कोई बढ़ोतरी हुई है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने तो बहुत कह डाला इस पर और यहां तक कह डाला कि वित्त मंत्री महोदय की इस मद पर हस्ताक्षर करते समय कलम क्यों नहीं टूट गई और दवात क्यों नहीं फूटी। ये सब बातें कहीं, वे यहां नहीं हैं। मैं यह अर्ज करूं कि राजस्थान में जहां मनचले लोग तरह तरह के आन्दोलन खड़े कर देते हैं, भूस्वामियों का आन्दोलन लीजिये, हाई कोर्ट का लीजिये, स्टूडेन्ट्स का आन्दोलन लीजिये तो इनको रोकने थामने का जहां प्रश्न है पुलिस की मदद सरकार को जरूरी हो जाती है। उधर बैठने वालों की यह जिम्मेदारी नहीं है। इधर बैठने वालों की जिम्मेदारी है कि जनता की सुरक्षा की रक्षा की जावे। लेकिन यह कह देना कि पुलिस डिपार्टमेन्ट में सब चोर और डाकू हैं और पुलिस में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, यह मैं नहीं मानता हूं। किसी एक दो अधिकारी की गलती से इतना बड़ा नतीजा निकाल लेना मैं समझता हूं ठीक नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान उनकी बजट स्पीच के इंगलिश वरशन की तरफ, जो उन्होंने पैरा ५० में कहा है उसकी ओर दिलाऊंगा। इस पैरा में लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण का ज़िक्र किया है। वह इसलिए कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उन्होंने दो तारीखें बताई हैं जब से कि विकेन्द्रीकरण की नीति पर अमल किया जायेगा। लेकिन उनके भाषण से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन का जरूर ज़िक्र किया है लेकिन उस फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन के फलस्वरूप विकेन्द्रीकरण पर होने वाले खर्च का प्रावधान मैंने किसी मद के अन्तर्गत इस बजट में नहीं पाया। दो तीन माननीय सदस्यों ने कल पंचायतों को

(श्री परसराम)

अधिकार देने के लिए और उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी देने के बारे में कुछ शंका प्रकट की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक आपकी मार्फत सदन के माननीय सदस्यों से यह अर्ज करूंगा कि जहां तक पंचायतों का प्रश्न हैं, जितने भी डवेलपमेन्ट के काम हैं यह सब पंचायतों द्वारा आज भी करवा रहे है। एन० इ० एस० ब्लाक्स में सबके सब काम आज पंचायतों की मार्फत होते हैं। उस समय तो आप ज़िम्मेदारी देते हैं जहां कि ५० फीसदी पब्लिक को कन्ट्रीब्यूशन देने का प्रश्न है। तो पंचायतों को अधिकार देते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि पहला तो लैंड रेवेन्यू की वसूली का सवाल है और दूसरे उनको जो अख्यिारात देने का प्रश्न है, विकेन्द्रीकरण की नीति के फलस्वरूप तहसीलों में कुछ पंचायतों को अधिकार दिये जायें। उसके बारे में कामयाब होते है तो इसी व्यवहारिकता के तौर पर और सामान्य प्रशासन को देखते हुए इस तरह के अख्तियारात नहीं दिये जायें। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जनता की विकास कार्यों के प्रति रुचि है और जब हम आज से पांच साल पहले का राजस्थान देखते हैं और पांच साल के पहले के राजस्थान से आज जो राजस्थान में विकास के कार्य हो रहे हैं उनका कम्पेरीज़न करते है तो हम एक ही नतीजे पर पहुँचते हैं कि विकास कार्यों के फलस्वरुप जो राजस्थान में प्रगति हो रही है वह वास्तव में उस ओर लक्ष्य है कि जिस लक्ष्य को मानकर योजनाओं के अनुसार राजस्थान का और राजस्थान के साथ साथ हिन्दुस्तान का प्लानिंग है और प्लानिंग के फलस्वरूप यहां के रहने वाले करोड़ो और लाखों आदमियों का जनजीवन ऊंचा उठेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : I was to reply from 2.30, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : The Hon. Member will please finish it early.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर शहर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया है इस पर काफी वाद विवाद हो रहा है ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य १५ मिनिट में ही समाप्त करें ताकि गवर्नमेंट का रिप्लाई आरम्भ हो।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं बहुत थोड़े समय में ही समाप्त करने की कोशिश करूंगा।

बजट में सबसे पहली बात मैं यह देखता हूं कि हम जनता के लिये जिस धन को खर्च करना चाहते हैं वह कहां तक जनता को लाभ दे रहा है और जिस नीति के आधार पर हम खर्च कर रहे हैं उस नीति से कहां तक लाभ दे सकेंगे या नहीं, इन पर हमें विचार करना चाहिये। जहां तक बजट का सवाल है वित्त मन्त्री महोदय ने बहुत ही कलात्मक दृष्टिकोण से बज़ट को रखा और उसमें कुछ ऐसी भी बातें रखीं कि जिनसे कुछ लोगों को राहत मिले और उसके साथ ही साथ कुछ ऐसी भी बातें रखी हैं कि जो लोग पिछड़े हुए हैं उनकी तरफ उनका ध्यान नही भी गया। मैं जहां तक समझता हूँ कि बज़ट में जो सबसे बड़ी चीज़ खास कर के किसानों के लिए, कृषकों के लिए

(श्री मुरलीधर व्यास)

और खासतौर से मजदूरों के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो समाजवादी दृष्टिकोण रखा गया है वह यह रखा गया है कि जो कुछ हम खर्च कर रहें हैं उससे वाकई हम उन्नति के पथ पर चल रहे हैं या नहीं तो इसका सबसे बड़ा दृष्टिकोण जो होता है वह यह है कि जो काम करने वाले लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको कहां तक लाभ होता है और उसके साथ ही साथ हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और जो साधन हैं उनको हम कहां तक जुटा पाये हैं, यह देखने की चीज़ है। क्योंकि श्रम ही धन है और जब यह धन बढ़ेगा तो देश की हालत भी अच्छी होगी। इस मामले में जो हमारी योजना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि हम खेती का उत्पादन बढ़ायेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य रखा गया है था कि हम अपने देश में उद्योगों को बढ़ायेंगे और बेकारी की समस्या को दूर करेंगे। यह बुनियादी उद्देश्य हमारी सरकार ने रखे थे और उस योजना के आधार वाकई हम कहां तक पहुँचे हैं, इसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने यह कहा कि करोड़ों रुपया राज्य का खर्च हुआ। आज हम एक अरब रुपये के कर्जदार हो गए। यह मैं मानता हूँ कि कर्जदार हुए लेकिन यह करोड़ों और अरब रुपया खर्च होने के बाद में लाखों हाथ बेकार रहें और उनको काम नहीं मिले और उसके साथ ही साथ यह भी हम महसूस करें कि लोग भूखे और नंगे हैं और उनको रोजी नहीं मिलती है तो आखिर इसकी गहराई में हमें जाना चाहिये कि इसका कारण क्या है ? मैं जहां तक समझ पाया हूं कि हमारी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था वह हम राजस्थान में सफल नहीं कर पाये हैं। इस योजना में यह था कि औद्योगिक विकास किया जाये और इसके अन्दर ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दे सकेंगे। तो, जो आज औद्योगिक विकास हुए और वह लोगों को काम दे सके या नहीं। जहां तक मैं समझता हूं इसमें हमने कोई सफलता प्राप्त नहीं की। प्राइवेट सेक्टर के अन्दर ही ज्यादा से ज्यादा उद्योग खुले और पब्लिक सेक्टर का कोई ख्याल इसके लिए नहीं रखा गया। जहां तक मैं देखता हूं कि उद्योगों को खोलने के लिए पब्लिक सेक्टर की तरफ हमारी सरकार ने कोई ख्याल नहीं रखा है। आज पब्लिक सेक्टर में जो पूंजी लगी हुई है उसका कहां तक इस्तेमाल होता है, उसका भी ख्याल नहीं किया गया। आज राजस्थान में जो साधन हैं उन्होंने किस प्रकार से पब्लिक सेक्टर में या को-आपरेटिव की तरफ मदद पहुंचाई है इसका भी ख्याल नहीं रखा गया है। ८० लाख रुपया रॉयल्टी का बढ़ा। रॉयल्टी हमारी बराबर बढ़ती जा रही है। हमारी रॉयल्टी बढ़ती है जब कि हमारे राज्य के अन्दर बहुत से धातु और पदार्थ हों और लोगों को लीज़ देकर रॉयल्टी बढ़ती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यह रॉयल्टी इस प्रकार से आप बढ़ा कर वाकई लोगों को राहत दे रहे हैं क्या। हमारा उद्योग बढ़ रहा है लेकिन जो कुछ माल उत्पन्न होता है उसका लाभ राजस्थान को कहां तक मिल रहा है। जितना भी यहां पर कहना हो कहना चाहिये। खास चीज़ यह है कि उनको व्यक्तिगत लीज़ पर दिया है और देकर रॉयल्टी बढ़ाई जाने का एक मात्र उद्देश्य रखा तो किसी भी हालत में आप अपने राज्य में उद्योग का विकास नहीं कर सकेंगे। एक तो

(श्री मुरलीधर व्यास)

सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि जो लोग खान में काम करते हैं उनको फायदा नहीं होता। जिनको लीज़ पर दिया जाता है उनको व्यक्तिगत मुनाफा करने में प्रोत्साहन मिलता है लेकिन साथ ही श्रमिक जो काम करते हैं वे फायदा नहीं उठा पाते हैं। तीन साल के लिये या एक साल के लिये या दो साल के लिये लीज़ मिला है तो लीज़ पर लेने वाले का लक्ष्य यह रहता है कि अधिक से अधिक वह अपने मुनाफे को दृष्टि में रख कर खान को खोद कर नष्ट कर देता है। दूसरे पंचवर्षीय योजना में जो दृष्टिकोण विकास का था वह यह था कि जो भी ऐसे उद्योग हैं उनको हम स्वयं चलावें या प्राइवेट सेक्टर में लोगों का सहयोग लेकर इनका विकास किया जाय यदि ऐसा किया जाता तो वास्तव में हमको फायदा होता। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि जामसर में जिप्सम की खान है। हिन्दुस्तान में जितना जिप्सम पैदा होता है उसका ७५ पर्सेन्ट इस खान से निकल कर सिंधरी फर्टिलाइज़र कारखाने में जाता है। इस खान को २० साल के लिये गवर्नमेंट ने लीज़ पर दिया। केन्द्रीय सरकार ने ८ रु० प्रति टन के हिसाब से मूल्य तय किया और वह खान मालिक मजदूरों को १ रु० प्रति टन के हिसाब से मज़दूरी देकर ७ रु० प्रति टन का फायदा स्वयं उठाता है और १००० टन जिप्सम रोज निकाला जाता है। क्या सुन्दर उदाहरण है। एक ओर तो आपने उसको फायदा दिया कि कम से कम ४ लाख टन जिप्सम सिंधरी फर्टिलाइज़र उससे लेता है तो उसको कितना फायदा उस व्यक्ति को आप देते हैं। इस पर भी उसके काम करने का तरीका ठीक नहीं है। वह ऊपर की मट्टी हटा कर जल्दी जल्दी से अच्छा अच्छा जिप्सम निकालता जाता है और बाकी को दबाता जाता है। नतीजा यह होगा कि बहुत दबा दिया जायगा और मुनाफे की गुंजायश हमेशा के लिये बैठ जायगी। इस प्रकार से दूसरी खानों की भी यही स्थिति है। मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार की नीति भी बज़ट में स्पष्ट होनी चाहिये। राज्य सरकार को किसी प्रकार से ऐसी खानों को अपने कब्जे में लेकर अधिक से अधिक धन जनता के फायदे के लिये पैदा करना चाहिये, व्यक्तिगत मुनाफे की गुंजायश नहीं रखनी चाहिये और सहकारिता के आधार को स्वीकार करना चाहिये। इस प्रकार की बहुत सी चीजें हैं। खानों के सम्बन्ध में एक नीति रॉयल्टी का दृष्टिकोण सामने रख कर नहीं बनानी चाहिये बल्कि सरकार को खुद को अपने हाथ में लेकर चलाना चाहिये। इसमें लाखों रुपये रॉयल्टी के आते हैं लेकिन यह चीज़ भी होती है कि जिसको ठेका दिया जाता है उसके साथ सरकारी अधिकारी मिल जाते हैं। जमीन का जितना हिस्सा ठेके पर दिया जाता है उससे काफी अधिक भूमि पर वे लोग काम करते है और अधिकारी लोग ठेकेदार के साथ मिल कर हमारे धन का दुरुपयोग करते हैं क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते। मैं इसके कई उदाहरण दे सकता हूँ। बीकानेर में पंजाब के लोगों को गंगाशहर के पास जितने भट्टे एलॉट किये हैं उनको मैंने स्वयं ने देखा है कि जितनी जमीन का ठेका लिया है उससे बहुत अधिक जमीन पर माल तैयार करते हैं और सरकार को पता नहीं लगता है। इससे कितना दुरुपयोग होता है। सरकार को अपनी रॉयल्टी की नीति बदलनी चाहिये।

(श्री मुरलीधर व्यास)

पब्लिक सेक्टर में सरकार स्वयं चलावे ।

बीकानेर ग्लास फैक्ट्री की बात मैं बराबर कहता रहा हूँ। दो आदमियों के झगड़े के बीच में यह फैक्ट्री बंद पड़ी है और ८०,००० रु० सरकार के यों ही पड़े हैं, ब्याज मिला कर लाख से ऊपर होते। आज उसकी ५० हजार की भी कीमत नहीं रह गई है। सारा माल लोग ले गये, दीवारें टूट गई, कोई चौकीदार नहीं, जमादार नहीं और कोई देखने वाला नहीं और सरकार के रुपये यों ही जा रहे हैं। आज अगर उद्योग का विकास करना है तो ग्लास के लिये जिप्सम, लिगनाइट, कोयला जो कुछ चाहिये वे साधन यहां पर उपलब्ध हो सकते हैं फिर भी ग्लास फैक्ट्री बनी बनाई बन्द पड़ी रहे और सरकार का पैसा डूबता हो तो सरकार को उस पर कब्जा करना चाहिये और यह सोचना चाहिये कि ऐसी चीज़ को चला सकते है या नहीं। और यदि चलाते हैं तो कितने आदमियों को काम मिलेगा। बेकारी की समस्या उद्योग से हो सके तो दूर करनी चाहिये। लेकिन आपका ख्याल इस ओर नहीं पहुंचता। बेकारी दूर करने का जो साधन है उस ओर ख्याल नहीं करते तो यह समस्या हल नहीं हो सकती।

दूसरी बात किसानों के बारे में सरकार की जो नीति है, उस बारे में कहना चाहता हूं। बजट में जितने टैक्सेज़ रखे हैं उनमें आबकारी के अतिरिक्त दूसरे टैक्सों का सीधा असर किसानों पर पड़ेगा और साथ ही साथ यातायात के विकास पर भी पड़ेगा। किसानों के लिये सरकार ने नीति बनाई है। आगे जाकर सीलिंग आने पर किसानों के पास एक हद से ज्यादा जमीन नहीं रहेगी, उनकी इन्कम भी ज्यादा नहीं रहेगी और उसके बाद भी आपकी यह नीति रही कि किस प्रकार किसानों से ज्यादा से ज्यादा लें तो सफलता नहीं मिलेगी। बज़ट में यह घोषणा की है कि ६।। लाख रु० खुशहाली टैक्स के रूप में वसूल करेंगे, एक एकड़ ज़मीन के लिये २६४ रु० वसूल करेंगे। आप अंदाज लगाइये कि सीलिंग की योजना लागू होने के बाद उनके पास कितनी ज़मीन रहेगी, कितने साधन रहेंगे, कितनी आमदनी रहेगी और यदि आमदनी इस आधार पर रहेगी तो आप कैसे वसूल करेंगे। १५ साल में २६४ रुपये के हिसाब से वसूल करेंगे तो उसके पास २५.३० एकड़ भूमि रहेगी, उस हिसाब से कितना वसूल करेंगे और फिर यह अंदाज लगाइये कि बीकानेर में जब गंगासिंहजी ने नहर बनाई थी उस समय उन्होंने भी खुशहाली टैक्स लगाया था, जो १८ से २० ६० था। आपका ज्यादा हो जाय तो आपका दृष्टिकोण किसान के प्रति क्या रहा और आगे जो नीति है उसमें किस प्रकार वसूल करेंगे। एक ओर खुशहाली टैक्स, दूसरी ओर लगान, नहरी टैक्स और दूसरे ऊपर से हमारे टैक्स उन पर पड़ेंगे तो किसानों के लिये सरकार की जो नीति सीधी और साफ बननी चाहिये जिसके आधार पर आगे का निर्माण करना चाहते हैं उसके आधार पर जो पालिसी है उसमें सफलता नहीं मिलेगी और यदि ऐसा किया ही गया तो किसान दब जायेंगे, उसका दूसरा रास्ता निकालना चाहिये।

किसानों के लिए सहकारी समितियों की हमारी य जना को-ऑपरेटिव बेसिस पर आधारित होगी। आज मैं कहना चाहता हूं कि

Page No 69

(श्री मुरलीधर व्यास)

जो भी को-ऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके जरिये किसानों को कहां तक मदद मिलती है, इसको गहराई से देखना चाहिये। जिस प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने रिज़र्व बैंक को सर्वे रिपोर्ट दी थी और उसको कार्यान्वित करने को कहा था। जो किसान पूरे भार से दबा है उसको किस प्रकार राहत दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं उसके लिये सारे राजस्थान में हर तहसील हैड क्वार्टर पर एक कोऑपरेटिव बैंक खोलनी चाहिये जिसके जरिये वहां पर कर्जा दिया जा सके। लेकिन किसानों पर जो ऋण है उनको कम करने के लिये या मदद देने के लिये कोई स्कीम नहीं है।

इसके अतिरिक्त दूसरी बातें जो बजट में आई हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यह सोच रहे हैं कि एक पॉलिसी बनायेंगे जिसके अनुसार अनाज के व्यापार को हाथ में ले लेंगे। लेकिन बजट में कहीं देखने में नहीं आयेगा कि इतने रुपये लगा कर किस प्रकार से काम चलायेंगे। कुछ रुपये इस काम के लिये भी रखने चाहिये थे, लेकिन मुझे बजट में कहीं नजर नहीं आया।

कुछ रुपया रखा रहता और इसको किस प्रकार खर्च करेंगे यह तो नीति सरकार ने बनाई होगी पर वह इस बजट में हमें नज़र नहीं आई। जब माल आयेगा और उस समय आपने रिज़र्व नहीं किया तो आगे जब आप अनाज के भावों पर कन्ट्रोल करना चाहेंगे तो किस प्रकार चलायेंगे, पर इसका इसमें कहीं उल्लेख नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनिट और। इसके अतिरिक्त शिक्षा के सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं वह इतनी ही है कि प्राइमरी स्कूल्स के शिक्षकों के लिये ५० रुपया कम से कम वेतन किया, इसके लिये धन्यवाद देता हूं, पर साथ ही कहना चाहता हूँ कि ५० रुपया वेतन रखा गया है उसमें कई टीचर ऐसे भी मिलेंगे जो म्युनिसिपेलिटीज़ के अन्तर्गत काम करते हैं। हमारे बीकानेर में म्युनिसिपेलिटी प्राइमरी स्कूल्स चलाती हैं और टीचर्स म्युनिसिपेलिटीज़ के अन्तर्गत काम करते हैं। उनके कोई ग्रेड्स नहीं हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के लिये रखा है तो आपका ऐसा प्रयास होना चाहिये कि बाकी शिक्षक बच गये हैं, उनके ऊपर भी यह लागू करेंगे। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपने मैट्रिक वालों के लिये रखा है, पर ऐसे भी बहुत से टीचर्स हैं जो मैट्रिक पास नहीं हैं पर दस-दस, बारह-बारह साल से काम कर रहे हैं, उनके लिये भी आपको इसके अन्तर्गत इसी तरह का दृष्टिकोण रखना होगा।

अपना तो सरप्लस बजट है, १२ लाख की बचत बताई है, राजस्थान एक बैकवर्ड स्टेट है, इसके साथ ही साथ हमारे सामने कई समस्याएं हैं, इसके माने यह है कि हमने सब कुछ कर लिया है अब कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, बजट को इस हालत में बचत का बजट रखना, इसके माने यह हैं कि हमने सब कुछ कर लिया है, अब हमें कुछ नहीं करना है। तो, ऐसी सूरत में जो बजट बचत का बताया है, उसे मैं ठीक नहीं समझता।

अब एक मुख्य बात मैं और कहना

(श्री मुरलीधर व्यास)

चाहता हूं, वह यह है कि इस बजट में गिरे हुए हरिजन वर्ग के जीवनस्तर को ऊंचा उठाने के लिये कोई बात नहीं रखी है। इस चीज़ को मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि म्युनिसिपेलिटीज़ में जो हरिजन काम करते हैं, उनका जीवन स्तर बहुत नीचा गिरा हुआ है। जब आपने १२ लाख की बचत बताई है तो म्युनिसिपेलिटीज़ के अन्तर्गत काम करने वाले हरिजन कर्मचारी जो कि मैला ढोते हैं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये जब तक म्युनिसिपेलिटीज़ को विशेष ऐंड दे कर कोशिश नहीं की जायगी, उनका जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठेगा। इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये राजस्थान सरकार को अगर म्युनिसिपेलिटीज़ को विशेष ऐंड देना पड़े तो वह देनी चाहिये और हर तरह से इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये राजस्थान सरकार को प्रयास करना चाहिये। अगर आपको १२ लाख की बचत है तो म्युनिसिपेलिटीज़ के हरिजन कर्मचारियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये म्युनिसिपेलिटीज़ को विशेष ऐंड देनी चाहिये। यही सुझाव मैं इसमें देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : The Government will now reply.

२.५४ म. प.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् ५९–६० के बजट पर इस सदन में पिछले तीन दिनों से चर्चा चल रही है। इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने जो इस ओर बैठने वाले और उस ओर बैठने वाले हैं, इस बहस में अपना हिस्सा लिया। कई माननीय सदस्यों ने बहस के दौरान में, अलग अलग विभागों की जो कार्यप्रणाली है उसमें किस प्रकार से सुधार किये जाने चाहिये और क्या क्या सुधार किये जा सकते हैं, इस बारे में अपने अपने अलग अलग विचार बताये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सब चर्चाओं में न पड़ कर ज्यादा उन्हीं चर्चाओं में पड़ना पसंद करूंगा जो कि विभाग मेरे से सम्बन्धित हैं।

सबसे पहले माननीय सदस्यों ने जो इस सदन में कहा, कुछ ने हमारे इस बजट के बारे में माना भी है कि इसमें बहुत सी अच्छाइयां है और कुछ खामियां भी हैं और कहा कि अच्छाइयों के लिये ज्यादा चर्चा में पड़ना पसंद नहीं करेंगे, खामियों की चर्चा करना पसंद करेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि समाजवाद की ओर बढ़ने का कहते हैं और इस बात का दावा किया जाता है कि योजनाओं के द्वारा बेकारी को मिटायेंगे, पर इस बजट के द्वारा उस बेकारी को मिटाने का उन्हें दर्शन नहीं हुआ। माननीय उपाध्यक्ष, इस बजट के आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि आज तक राजस्थान के जितने बजट बने हैं, उन सबसे ज्यादा खर्चा इस बजट में किया जा रहा है, हमारा यह बजट ६४॥ करोड़ का बजट है। इसमें जनहित के कामों में, योजना के कामों में करीब ४८॥ करोड़ रुपया खर्च होगा। इसमें जो खर्चा किया जायगा, अलग अलग विभागों के जरिये, उसके अलग-अलग आंकड़े अलग-अलग मदों में डिटेल में मौजूद हैं, मैं ज्यादा डिटेल में पड़ना पसंद नहीं करूंगा, यही निवेदन करूंगा कि बेकारी के

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नाम से कोई स्पेसिफिक हैड इसमें मौजूद नहीं हैं, पर जितने मद हैं और उनमें जिस प्रकार खर्चा किये जाने के तरीके है, उनको देखें तो एक आउटलुक मिलता है और एक आउटलुक बनता है कि एक तरफ बेकारी मिटाने की बात कहते है, दूसरी तरफ मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कामों को चलाने के लिये काम करने वाले आदमियों के मिलने में हमें मुश्किल हो रही है। पढ़े लिखे शिक्षित समाज को जाने दीजिये, जिसमेंथोड़े बेकार हैं, पर वह तबका जो श्रम कर के रोज़ी कमाना चाहता है, उसके लिये बजट में इतने काम खुले हुए हैं कि वह कहीं भी जा कर काम कर सकता है, सड़कों के, भवन निर्माण के, इर्रिगेशन बंध बनाने के बड़े बड़े काम चल रहे हैं, उनमें मजदूरों की कमी है। राजस्थान केनाल का इतना बड़ा काम है कि १० करोड़ रुपये की पूंजी इसके लिये रखी है, वहां सिर्फ पांच, छ हज़ार आदमी काम करते है। वहां जितने भी आदमी काम करना चाहें, कर सकते हैं, राजस्थान सरकार ने कहा भी है कि इस काम को प्रगति से करना चाहिये, जो भूमिहीन लोग हैं, आने वाले जीवन में जिनको अच्छा बनाना चाहते हैं, वे इस इलाके में जा कर काम करेंगे तो पानी आने पर उनको जमीनें देंगे, बसावेंगे, काम देंगे। तो काम की आज कमी नहीं है, कोटा में चम्बल का काम चल रहा है, बीकानेर में राजस्थान केनाल का काम चल रहा है, सड़कों का काम सभी इलाकों में चल रहा है, तो आज श्रम का काम करने वालों के लिये काम की कमी नहीं है। ज्यादातर इस देश के रहने वाले लोग श्रम का काम ज्यादा करते हैं, बच्चे आज कल पढ़ने लिखने लगे हैं। पर पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिये ज़रा बेकारी का सवाल है, वे इस प्रकार का श्रम का काम करना पसंद नहीं करते, उनके लिये थोड़ी सी दिक्कत है।

इसके भी आंकड़े हैं, हिसाब लगायें तो पता चलेगा कि कितने ही लाख उनकी नौकरियों के लिये हैं। जब इतने विभाग खुलते हैं, इतने सारे काम चल रहे हैं तो कई एल. डी. सी., यू. डी. सी. बनेंगे, कई अफसर बनेंगे। इतने सारे नये काम चल रहे हैं, उनमें कई टेक्निकल आदमी काम पर लगेंगे। तो बेरोजगारी को मिटाने की तरफ तो आम तौर से आप देखें तो, सभी तरह से इसमें मौजूद है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने, खास तौर से मेरे विभाग सार्वजनिक निर्माण से सम्बन्ध रखने वाली बातों की चर्चा की और कहा कि राजस्थान की सड़कें आज भी खराब हैं। किसी ने यह भी कहा कि सड़कें हमारी कॉन्स्टिट्युएन्सी में नहीं बनी हैं, हमारे क्षेत्र में नहीं बनी है, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज भी इस पर फिर निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में सड़क निर्माण योजना का एक नक्शा पहले ही माननीय सदस्यों के सामने रख छोड़ा है और सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि आगे आने वाले पांच वर्षों में ये सब बना कर रख छोड़ेंगे। पिछले साल के बजट में १६० लाख की धन राशि थी, लेकिन यह कहा गया कि खर्च नहीं किया जा रहा है उसके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि हमने पिछले साल के बजट में यह धन राशि रखी थी और उसके बावजूद भी वित्तीय वर्ष के अन्त तक २२५ लाख रुपया खर्च कर पायेंगे,

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स लेकर यह किया गया है।

इस दृष्टि से देखियेगा कि पिछले साल जो प्रावधान बजट में रखा था उससे अधिक ही खर्च किया है। इसी प्रकार भवन निर्माण के लिए जो प्रावधान है उससे भी अधिक साल के एन्ड तक खर्च कर पायेंगे। जितना प्रोविज़न बजट में होता है और सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स आपके सामने लेते हुए हम काम करते हैं, प्रगति की जा रही है और करना चाहते हैं, लेकिन यह कहे कि अमुक इलाके में सड़क नहीं बनी हैं, इसलिए काम नहीं हो रहा है, यह तो उचित नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि मरम्मत के लिए अधिक रुपया रखा जाना चाहिये। मैं माननीय सदस्यों को, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो टोटल लेन्थ ऑफ सड़कें हैं उनके लिए करोड़ों रुपया मेन्टीनेन्स के लिए रखा जावे तब हो सकता है। लेकिन हमारे सीमित साधन हैं, लेकिन जो साधन हमारे पास तरक्की की रफ्तार को धीमी न करते हुए उपलब्ध हो सकते हैं, मेन्टीनेन्स के लिए भी हमने रुपया रखा है और हर साल हम उस रकम को बढ़ाते भी जा रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि पहले ७५ लाख रुपया रखा था फिर ८५ लाख मेन्टीनेन्स के लिए किया और फिर १०५ लाख किया और अगले साल कुछ काम करेंगे और जिन सड़कों की ज्यादा हालत खराब है उनकी मरम्मत भी कराई जावेगी लेकिन वर्षों की, सदियों की बिगड़ी हुई हालत को सुधारने में रीज़नेबल समय, माननीय सदस्य स्वयम् जानते हैं, लगेगा। फिर सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में यह कहा गया कि इसमें सुधार करना चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि बहुत से काम सहयोग से करना चाहिये, सहकारी समितियां बना कर उनको काम देना चाहिये। मैं आपके ज़रीये, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को सूचना देना चाहता हूं कि मैं स्वयम् इस मत का हूं कि कॉन्ट्रेक्टर्स की जो एजेन्सी है वह ठीक प्रकार की एजेन्सी नहीं है और उस वज़ह से कई दिक्कतें होती हैं, यह एक प्रकार का शोषण का तरीका है और उससे ज्यादा मुनाफा कमाया जाय, तो कमाया जाय, इसलिए मैं आपके जरिये माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहूंगा कि मैं पूरा जागरुक हूं, इस बात से, सरकार पूरी जागरुक है और उसकी यह इच्छा है कि सहकारी समितियों को ज्यादा से ज्यादा पनपाया जाय, उनको साधन सम्पन्न बना कर भवन निर्माण, सड़क निर्माण के कार्य ज्यादा से ज्यादा तादाद में उनसे करवाये जायं और विभागीय तौर पर ज्यादा से ज्यादा किये जा सकते हैं, वे किये जायं। हमने इस ओर प्रयत्न भी किया है। पिछले एक दो साल का चित्र मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं तो आपको विदित होगा कि ५५ लाख के काम हमने विभागीय तौर पर किये हैं। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर में सहकारी समितियां हैं उनको सहयोग भी दिया गया हैं और आगे इस प्रकार से सहकारी समितियों को पनपाने के लिए विभागीय इन्जीनियर्स की लगन लगी हुई है कि उनको पनपाना चाहिये। तो विभागीय तौर पर भी करना चाहते हैं और सहकारी समितियों को भी पनपाना चाहते हैं। इतने दिन आदमी मिलने की ज्यादा दिक्कत थी। ज्यों २ सिचुएशन ईज़ी होती जावेगी, विभागीय तौर पर काम करेंगे ताकि इसमें

Page No 73

(श्री नाथूराम मिर्धा)

खर्चा कम हो और बीच की जो एजेन्सी है वह इस प्रकार मुनाफा न प्राप्त कर सके । तो सरकार इसके लिए पूरी तरह से जागरुक है । आने वाले तीन चार वर्षों में ५० प्रतिशत काम विभागीय तौर पर और ५० प्रतिशत काम सहकारी समितियों से करवाने का नक्शा लेकर चलते हैं ।

दूसरा विभाग ट्रान्सपोर्ट है, जिसके बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने चर्चा की और कहा कि यह कर यात्रियों पर पड़ेगा और गरीब लोगों पर इसका असर पड़ेगा इस-लिये यह कर नहीं लगना चाहिये । मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके ज़रिये माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि कहने के लिए बात भले ही कह दें लेकिन जब हम यह सोचते हैं कि आम लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है और उसके लिए ज्यादा बड़ी रकमों की आवश्यकता पड़ती है और ज्यादा बड़ी रकमें वे थोड़े लोगों से नहीं आ सकतीं । ज्यादा रकम खर्च करने के लिए ज्यादा रकम की प्राप्ति उसी तबके से प्राप्त करनी पड़ेगी जिनमें थोड़ा थोड़ा देने की शक्ति है । आप सब कहते हैं कि टैक्सेशन डाइरेक्ट होना चाहिये, ठीक बिलकुल डाइरेक्ट लगाया है, ब्रॉड बेस्ड होना चाहिये, बिल्कुल ब्राड बेस्ड है । यह सब यात्रियों पर लगेगा । जो यात्री मोटर में बैठेगा उसी पर वह कर लगेगा । मोटर में बैठने के लिए जहां आठ आने या नौ आने देते हैं, उस पर एक पाई, दो पाई कर, मैं समझता हूं कि, अधिक नहीं है । सब चाहते हैं कि सड़कें बनें, नहरें निकलें, बांध बनें, लेकिन इस प्रकार साधन नहीं जुटाये जावेंगे तो कहां से बनेंगे । इस तरह से ३० लाख रुपया छोटे लोगों से लेंगे जो मोटरों में बैठ कर चलना पसन्द करते हैं । टिकिट के साथ इस कर का भी इन्तजाम करना हम पसन्द करेंगे । चाहे उसमें सेठ बैठे, किसान बैठे, साहूकार बैठे, जो भी मोटरों में बैठेंगे उनको वह कर देना पड़ेगा, देना भी जरूर चाहिये और इस प्रकार जो लिया गया टैक्स है वह किसी की जेब में नहीं जाता किन्तु वह तो स्टेट एक्सचेकर में जाता है और उसमें से निकल कर लोगों की भलाई और विकास के लिए ही जाता है । मैंने डिस्कशन के बीच में भी ज़िक्र कर दिया था कि स्पीच में एक अहमियत की चीज़ आनी चाहिए थी वह बाकी रह गई है और न ही वह माननीय सदस्यों के ध्यान में आयी कि इस प्रकार का प्रावधान है या नहीं । १५ लाख मोटर ट्रान्सपोर्ट के राष्ट्रीयकरण के लिए सोचते हैं, वह टोकन प्रोविज़न रखा है, टोटल अमाउन्ट नहीं हैं । टोकन क्यों रखा इसके लिए ज्यादा चर्चा में न पड़ कर इतना ही निवेदन करना पसन्द करूंगा कि पूरा इसके लिए प्लान में न रख कर रिएप्रोप्रियेशन या सेन्टर का एलोकेशन का प्रबन्ध करके किसी तरह इसको एड्जस्ट करके, किसी मद में बिठा कर, प्राइवेट ओनर्स का क्या हिस्सा होना चाहिये आदि, हम ज्यादा से ज्यादा कर सकें इस मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके कानून कायदे के फाइनेलाइज़ेशन के बारे में स्टेट लेवल पर विचार विमर्श हो रहा है और वह गम्भीरता से जारी है । हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया है । मैं महसूस करता हूं कि इस सदन के सभी सदस्य इसको पसन्द करेंगे ।

दूसरी बात जो मेरे विभाग को लेकर कही

(श्री नाथूराम मिर्धा)

गई, वह है एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के बारे में। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में मैंने गत साल बजट के भाषण का उत्तर देते हुए आंकड़े बता बता कर इस चीज का विश्लेषण किया था, उस समय मैने सारे आंकड़े रक्खे थे और इसके अलावा पांच सात रोज पहले एक रेडियो वार्त्ता के दौरान में सभी प्रकार के आंकड़े किस प्रकार की योजनायें हैं, रबी अभियान का मतलब क्या था, आदि सब बातों का विश्लेषण किया था जो काफी अखबारों में भी प्रकाशित हुआ और जिसको माननीय सदस्य भी जानते हैं। हमने एनीमल हस्बेन्ड्री के लिये भी अच्छी रकम रखी है जिस समय माननीय वित्त मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ रहे थे उस समय जब पशुओं का जिक्र आया कुक्कुटों का, बकरों का, तो कुछ माननीय सदस्यों को वह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ लेकिन इस गरीब देश के गरीब लोग जो गांवों में रहते हैं, उनके लिये मुर्गे, मुर्गियां, भेड़, बकरे, कुक्कुट, आदि उनकी आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिये आवश्यक है। आज हमारे देश के ८० फीसदी लोग, जो गांवों में रहते हैं, उनके लिये पशुधन एक बहुत आवश्यक धन है। अगर उनका मेन्शन बजट में किया जाता है तो यह बहुत उचित है। उसमें यह बताया गया था कि किन किन स्कीम्स के ज़रिये हम इस पशुधन को डवेलप करना चाहते हैं। उन लोगों को सन्तोष होना चाहिये हम गांवों में अच्छे बकरे देंगे, अच्छे सांड देंगे, अच्छी भेड़े देंगे....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : ये हमने पहले देखे नहीं....

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने देखें तो सब हैं लेकिन उसको विकास करने के के दृष्टिकोण से आपने नहीं देखा। नस्ल सुधार का यह सवाल है, वह आपने कभी सुधारने की कोशिश नहीं की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे खयाल से इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों के नोटिस में आया होगा कि पशुधन में सुधार करना हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना के पहले साल में, इसकी बहुत कम प्रगति हुई है, अब यह काम काफी तेजी के साथ चलने लगा है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आपने जब से पशु विभाग सम्भाला है, पशुधन की तरक्की हुई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह ठीक है, आप यह तो महसूस करते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : केवल गांवों की तरक्की नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आप पर निर्भर करता है।

एक माननीय सदस्य : इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रीजी की है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इन दोनों विभागों का काम माननीय सदस्यों की ज्यादा चर्चा का विषय रहा है। लोगों को बीज का वितरण ठीक प्रकार से नहीं हुआ और जितनी तादाद में बीज चाहिये था वह भी प्राप्त नहीं हुआ, इस प्रकार का जो बीज के सम्बन्ध में क्रिटीसिज्म हुआ अच्छे बीज और सुधरे हुए बीज की

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जितनी तादाद में मांग थी उतनी तादाद में हम अवेलेबल नहीं कर सकते, यह सही है। गेहूं का जितना रकबा राजस्थान में सेकन्ड फाइव ईयर प्लान के अन्तिम समय तक या थर्ड फाइव ईयर के प्रथम वर्ष में हम उसके लिये सुधरे हुए बीज की पर्याप्त व्यवस्था कर पायेंगे। इस बजट में भी आपने देखा होगा कि इस साल तक चालीस फार्म जो सौ सौ एकड़ के होंगे, उनमें हम सुधरे हुए बीज पैदा कर रहे हैं, इसके लिये ३४.४५ फार्म तो हमने एस्टेब्लिश कर दिये, उनमें इसी साल फसल भी हो रही है। आने वाले साल में वितरण के लिये अच्छा बीज और सुधरा हुआ बीज ज्यादा अवेलेबल होगा। रहा सवाल वितरण करने का, इसमें कई प्रकार की कठिनाइयां हो सकती है। लेकिन अब हम सहकारी समितियों के ज़रिये जैसा कि इस बजट में दिया हुआ है वितरण कराने की व्यवस्था करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ज़रिये माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे देश की आधारभूत शिला गांव की सहकारी समितियां ही हो सकती हैं जिनके जरिये, जिनके निर्माण के ज़रिये हम देश को उन्नत कर सकते हैं। यह केवल विभाग का काम नहीं, किसी एक मंत्री का काम नहीं, जो जनतन्त्री व्यवस्था के अंग है, जो माननीय सदस्य जिन जिन इलाकों से निर्वाचित होकर आये हैं और वे लोग जो पब्लिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उन सभी लोगों को सही प्रकार की सहकारी समितियों के निर्माण के लिये गांवों में प्रचार करना चाहिये और सही सहकारी समितियों का वे निर्माण करायें। इससे प्रोडक्शन की फेसीलिटीज़ बढ़ सकती है और इसके अलावा सरकार द्वारा जो भी मदद वे लेना चाहें, मिल सकती है। इस प्रकार की जो सब रिसोर्सेज़ हैं, उन सब को मोबीलाइज़ करके देश के प्रोडक्शन में लगायी जानी चाहिये। सहकारी समितियों द्वारा जहां कहीं फ्रेश लैन्ड उपलब्ध हो, वह दी जा सकती है, प्रोडक्शन के लिये मार्केटिंग की व्यवस्था सहकारी समितियों द्वारा हो सकती है। सहकारी समितियों को हर प्रकार की आर्थिक सुविधा देने के लिये हमारी सरकार और हमारे देश का रिज़र्व बैंक भी तैयार है, इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस प्लान के मूवमेन्ट में पूरा सहयोग दें। हमारे राजस्थान में जिन लोगों ने भी आकर सहकारी समितियों का मूवमेंट देखा है वे चाहे विदेशी लोग हों या हमारी भारत सरकार के प्रतिनिधि हों, सबने इस बात की तारीफ की है कि राजस्थान की जो सहकारी समितियां है, वे स्वयं अपने पांवों पर खड़ी है। हमारी यहां की ज्यादातर सहकारी समितियां बैंक्स के रूप में या मार्केटिंग सोसाइटीज़ के रूप में कार्य करती हैं इसलिये बाहर के लोगों की इसके लिये अच्छी समितियां रहीं है। बहुत से माननीय सदस्य जो सहकारी समितियों के अन्दर राजनीति को लेकर घुसेड़ देते हैं, तो उनकी सहकारी समितियों के बारे में जो दृष्टिकोण होता है उनमें और हमारे दृष्टिकोण में बड़ा अन्तर आ जाता है।

श्री मदनसिंह : यह बीच में घुसेड़ने से माननीय मंत्री का क्या मतलब है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे कहने का मतलब राजनीति के प्रपंच को जो सहकारी समितियों के बीच में डाल देते हैं उससे है।

Page No 76

(श्री नाथूराम मिर्धा)

आपकी बात मैं अच्छी तरह समझता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह समझते हैं ! उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी समितियों के निर्माण का बहुत बड़ा काम है, उसको करने के लिये प्रोडक्शन साइड और मार्केटिंग साइड दोनों को डवेलप करने के लिये माननीय सदस्यों का इस ओर पूरा सहयोग हम चाहते हैं। जो सहकारी समितियां ठीक ढंग से नहीं चलती उनको सुचारू रूप से चलाने के लिये विभाग हमेशा तत्पर रहेगा। यह हो सकता है शुरू, शुरू का मूवमेंट है, इसमें किसी प्रकार की कमी भी रह सकती है, ज्यादातर गांव के लोग उसमें होने से सही प्रकार से रेजोल्यूशन बनाना अकाउन्ट को ठीक तरह से मेन्टेन करना यह उनको आ नहीं सकता फिर भी इन सारी दिक्कतों के होते हुए इस मूवमेंट को पनपाना और सही ढंग से पनपाना हमारा और आपका, दोनों का कर्तव्य है। इससे हमारे प्रान्त का उत्पादन बढ़ेगा, मार्केटिंग बढ़ेगा और सही लाइन्स पर आयेगा। अगर हम सहकारिता सब क्षेत्रों के अन्दर लागू करें और इसके द्वारा देश का ज्यादा से ज्यादा कार्य कराने लग जांय, सही तरीके से सही सहकारी समितियों द्वारा तो दूसरे देशों के अन्दर अलग वातावरण होते हुए अलग तरीके से हम अपने देश को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। देश में उत्पादन और वितरण सही तरीके से सहकारी समितियों द्वारा ही हो सकता है। यह बहुत बड़ा काम है। केवल एक विभाग नहीं कर सकता, न विभाग का मंत्री ही कर सकता है। माननीय सदस्यों को भी इसमें पूर्ण सहयोग देना चाहिये तभी हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। खरीफ का अभियान आगे आ रहा है। जहां तक लैन्ड अलॉटमेंट का प्रश्न है, ऐसी सहकारी समितियों द्वारा ही हम कराना चाहते हैं

श्री अर्जनदास : Sir, the Hon. Minister is doing this way (a gesture by hand). He should not do this while addressing me.

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो केवल छुटपुट बातें करके सदन को उस ओर ले जाना चाहते हैं, उन्होंने काम करना सीखा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : No, he wanted to humour the House.

श्री अर्जनदास : आप मेरी तरफ यह करते हैं इसलिये मैं कह रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपकी तरफ नहीं कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, ये ऐसे प्रश्न है जिन पर हमें बड़ी गम्भीरता से से विचार करना पड़ेगा। हमारे देश के सामने और प्रान्त के सामने बड़े बड़े काम पड़े हैं और कभी कभी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को ऐसा लगता है कि सारी नैतिकता का ठेका उन्होंने ले रखा हो। नैतिकता के नाम पर कोई किसी पटवारी की चिट्ठी सदन में लाकर रखता है लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि पटवारी डिसमिस हो गया यह बात जानते भी होंगे, लेकिन उस बात को सदन में ले आये···

श्री लक्ष्मीचन्द्र (सांचोर) : तहसीलदार का क्या किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई चिट्ठी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लिखने से तहसीलदार का दोष हो गया।

श्री लक्ष्मीचन्द्र : एक्शन लेना चाहिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : तहसीलदार के पास चिट्ठी पहुंची नहीं।

श्री लक्ष्मीचन्द : इन्क्वायरी करनी चाहिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : तहसीलदार के पास पहुंची नहीं। आपने बताया तो उसे डिसमिस कर दिया।

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble Minister should speak about his own Department.

श्री नाथूराम मिर्धा : मान लीजिये कि तहसीलदार के पास चिट्ठी पहुंच जाती तो आपकी जेब में यह कैसे आ गई ?

(हंसी)

श्री लक्ष्मीचन्द : जेब में इस प्रकार आई है····

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्य···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज़।

श्री नाथूराम मिर्धा : कई माननीय सदस्यों में एक प्रकार का····

श्री अर्जुनदास : On a point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : State your point of order.

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order.

श्री उपाध्यक्ष : There cannot be two points of order at a time. Mr. Arjun Das, please.

श्री अर्जुनदास : We cannot raise. The Hon: Minister will please feel that it is not good to point out like that to the Hon: member. In this House nobody is allowed to stand even a little finger. The Hon. Minister is realy raising his finger towards you, Sir. It is objectionable.

श्री उपाध्यक्ष : Well, I don't take it.

श्री पी० के० चौधरी : My point of order is this that this budget speech either the Finance Minister or the Leader of the House should reply and if other Ministers reply, then this should be strictly confined to say about their own Departments. He is just speaking about Revenue Department and the Revenue Minister is sitting besides him.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष, यह जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी इस सरकार की है।

(हंसी)

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मैं भी सरकार का, मिनिस्ट्री का नुमाइन्दा हूं इसलिए कोई विभाग का, विभाजन का, प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उपाध्यक्ष : The Chair is not demanding any explanation. The point of order is not well taken.

श्री पी० के० चौधरी : I will draw your attention to Parliamentary practice. The Hon. Ministers...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर प्लीज़। I have considered the issue.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष, बिलकुल पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस पर चल रहा हूँ।

(हंसी)

तो माननीय उपाध्यक्ष, ठीक है, नैतिकता सब के अन्दर होनी चाहिए और सबको नैतिकता रखने का हक है, पर कोई यह मान कर चलने लगता है कि नैतिकता हमारे में ही है, दूसरों में नैतिकता बिलकुल नहीं है, तो जरा अफ़—सोस होने लगता है। बाकी, सब नैतिकता रखते हैं और उसके हिसाब से काम चलाते हैं। यह ठीक है कि इस प्रकार की छोटी मोटी बातों की गड़बड़ी हो सकती है, इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी जनता है,

(हंसी)

इतने बड़े सरकारी कर्मचारी हैं। मैं नहीं कहता कि काम में कोई दोष नहीं है। जो दोष करते हैं, उनको नोटिस में लाये तो उस व्यक्ति के खिलाफ़ कार्यवाही की जायगी, एक्शन लिया जायगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह मान कर नहीं चलते हैं कि दोष नहीं, या दोष का पता नहीं करना चाहते हैं। हम इस बात को मान कर चलते हैं कि राज्य सरकार का काम अच्छा चलना चाहिए····

३. २२ म० प०

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पुनः पदासीन)

सरकारी काम लोगों के भले के लिए चलाना चाहते हैं। इस भावना से माननीय सदस्य कहते हैं तो उसका असर होता है और उस पर कदम उठाते हैं। परन्तु अपनी बात को कहना और उसका पालन नहीं करना, यह कहां तक ठीक है। हम एक दूसरे से छिपे नहीं हैं

(हंसी)

ऐसे लोग बढ़ चढ़ कर बात करते हैं तो उसका अफ़सोस होता है और उसका जवाब देना पड़ता है। मैं आपके ज़रिये यह निवेदन करना चाहूंगा कि बराबर राजस्थान आगे बढ़ा है और प्रगति की ओर हम चलते रहे हैं और चलते रहे तो निश्चित तौर से राजस्थान आगे बढ़ेगा, बेरोज़गारी मिटेगी और उससे देश का भला होगा, राजस्थान का भला होगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : आपके डिपार्टमेंट के मुतल्लिक मैंने कहा कि इस विभाग द्वारा जो पशु—मेला सांचोर में हुआ, उसमें घोटाला हुआ, उसके बारे में नहीं कहा।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछ लिया, उसका

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जवाब मैंने दे दिया। उसको आप घोटाला मानते हैं और आप अपने तरीके से बात करना चाहते हैं, वह नहीं हो सकता। जो बात थी, वह इस प्रकार की बात नहीं है। १० हज़ार रुपये उस मेले में खर्च किये, आपने उसके लिए कहा कि पानी के घड़े क्यों खरीदे, टेन्डर क्यों नहीं मांगे। आप जानते हैं कि मेले में इमीजियेट इन्तज़ाम करा, उस समय मिट्टी की मटकियों के लिए टेन्डर मांगते, जो छः पैसे में मिलते हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : तीन हज़ार रुपये एक व्यक्ति को दिये, उसके टेन्डर नहीं मांगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने जो सवाल पूछा था, उसका डिटेल में जवाब दे दिया था। इसमें कुछ तथ्य है नहीं

(हंसी)

जितनी सी बात इलाज करने की थी, वह करदी है।

श्री अध्यक्ष : यह मेले के लिए पूछ रहे हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : क्या मन्त्री जी का मतलब है कि जिसको आप घोटाला कह रहे हैं, वह घोटाला नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : जिसको आप मनुष्य कहते हैं, उसे आप जनक कहते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बजट पर साधारण (सामान्य) वादविवाद में, जो तीन रोज़ से हो रहा है, अनेक विभागों के बारे में अनेक बातें कही गई हैं। बजट के बारे में जो आम बात कही गई है, उसके बारे में मैं कुछ निवेदन करना नहीं चाहता, उसके सम्बन्ध में वित्त मंत्री जी आपको बतायेंगे। कुछ बातें, जो मेरे विभाग से सम्बन्ध रखती हैं, उनके बारे में मैं कुछ आपसे निवेदन करना चाहूँगा।

एक बात, जो आम तौर से कही गई, वह यह कही गई कि पुलिस का खर्चा दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। शायद एज्यूकेशन के महकमे के अलावा कोई ऐसा महकमा नहीं, जिसका खर्चा पुलिस विभाग से ज्यादा हो और कुछ भाई तो यहां तक भी कह गये कि न हमको पुलिस चाहिए, न हमको थाने चाहिए, न हमको चौकियां चाहिए...

श्री पी. के. चौधरी : हमको राम राज्य चाहिए।

श्री रामकिशोर व्यास : अगर वह दिन आये समाज में, जिस रोज़ थाने, चौकी और पुलिस की जरूरत न हो, तो निहायत खुशी का मौका होगा। वह वक्त आये, जिसमें कि फाहियान आया था और उसने लिखा था कि हिन्दुस्तान में चोरी नहीं होती, डाके नहीं पड़ते, कोई माल नहीं उठता, कोई अपराध नहीं करता। ऐसा समय आ जाय, हम चाहते हैं, वह समय आये...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व): सवाल यह है कि उस समय को लाये कौन।

श्री रामकिशोर व्यास : लेकिन वह स्थिति आज नहीं है। जो आज स्थिति है, उसको समझना होगा। आज के रोज़ यह

(श्री रामकिशोर व्यास)

कहना कि पुलिस की जरूरत नहीं, थाने और चौकियों की जरूरत नहीं, मैं समझता हूं प्रेक्टिकल बात मालूम नहीं होती है । लेकिन हम सोचते हैं कि जो चौकियां हैं वे कम हों। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति हैं, उसके लिए कहें कि पुलिस की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ, यह कहना मुनासिब नहीं है । मैं चाहता हूँ जिन महाशयों ने, मित्रों ने यह बात कही है, वे ठंडे दिल से सोचें । मैं उनके सामने कभी यह समस्या रख दूँ कि आपके जिले में से, आपकी कॉन्स्टिट्युएन्सी में से कौन से थाने आप कम कराना चाहते हैं, कौन सी चौकियां कम करना चाहते हैं, तो वे कहां तक अपनी बात पर कायम रहेंगे, यह सोचने की बात है । मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सुझाव उन्होंने रखे हैं वे सहर्ष स्वीकार हैं, अगर आप अपने जिले के लोगों को, अपनी कॉन्स्टिट्युएन्सी के लोगों को इस बात के लिए तैयार करें कि कौन कौन सी चौकियां कम करनी हैं, कौन कौन से थाने कम करने के लिए वे तैयार हैं....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): आप उटा देंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपका सुझाव आये तो खुशामदीद । वैसे हम इसमें सोच भी रहे हैं कि क्या क्या कम किया जाय । आपका सुझाव आयेगा, तो खास तौर से ध्यान रखेंगे ।

पुलिस के लिए बजट में रुपया रखा गया है, उसके बारे में कहा गया कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़ी गड़बड़ी की, उनकी कलम क्यों नहीं टूट गई, उनकी दवात क्यों नहीं टूट गई, ऐसा कौन सा आसमान फट रहा था, कौन सी बिजलियां कड़क रही थीं, जिसकी वजह से फाइनेन्स मिनिस्टर ने इतना पैसा रखा । मेरी समझ में नहीं आया कि फाइनेन्स मिनिस्टर ने कौन सी ज्यादती की है । अगर पुलिस के लिए रुपया रखा तो क्या बेजा काम किया जिससे उनकी कलम टूट जाती, दवात टूट जाती....

श्री पी. के. चौधरी : आप भूल जाते हैं, कलम से वे लिखते नहीं है ।

श्री रामकिशोर व्यास : एक बात सभी साहबान ने कही, खर्च के बारे में, उसको जरा ठंडे दिल से सोचें तो ठीक होगा । दलील यह दी जाती है कि चूंकि लॉ एन्ड ऑर्डर ठीक हो गया, शांति सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, इसलिए पुलिस को क्या जरूरत है, पुलिस पर इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है । यह बात ठीक है, यह ठीक कहा गया है कि शांति सुरक्षा की व्यवस्था ठीक है, काबू में है, नियंत्रण में है लेकिन जिन कारणों से यह व्यवस्था आई है, जिन कारणों से यह दिन नसीब हुआ है, क्या उन कारणों को आप मिटाना चाहते हैं ? जिस पुलिस की ईमानदारी से यह दिन आपको देखने को मिला है, उस पुलिस की आपको ज़रूरत नहीं है, आप उन सब बातों को पसन्द नहीं करना चाहते हैं, जिन कारणों से यह दिन आया है । उसको खत्म करना चाहते हैं तो फिर आपको पांच सात वर्ष पीछे जाना पड़ेगा और बाद में दस्ते अफसोस मलना पड़ेगा कि हमने गलती की है । मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह काम जल्दी करने का नहीं है, यह काम तेजी में नहीं करने का है, सारे स्टेट की बात को सोचने की जरूरत है कि वाकई पुलिस का खर्चा बढ़ा है या नहीं, कितना

Page No 81

(श्री रामकिशोर व्यास)

बढ़ा है, कैसे बढ़ा है और कितना कम करने की जरूरत है, कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप उसके आंकड़ों पर मुलाहिज़ा फरमायेंगे। ५१–५२ में जो पुलिस फोर्स थी उससे आज बढ़ी नहीं है, कुछ कम ही हुई है। अफसर और कॉन्स्टेबल्स की संख्या कुछ घटी है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : अफसरों का नम्बर कम है या ज़्यादा हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं अर्ज कर दूंगा सब। तो फोर्स के कम होने पर भी खर्चा बढ़ा कैसे, यह मैं बताता हूं। एक माननीय सदस्य ने जिनके लिये मेरे दिल में इज्जत है, तजुर्बा भी उनको बहुत है, एक बात फर्माई कि न मालूम किस चालाकी से या किस तरकीब से यह बजट पास करवा लिया। मैं निवेदन करूं कि यह कोई सवाल नहीं। यह तो काफी लोगों की नज़रों से होकर गुजरा है। काफी काट छांट और कैंचियां चलनी हैं। इसके बाद भी वाजिब बात तो माननी ही पड़ती है। तो यह चालाकी की बात सुनकर अफसोस तो हुआ। आखिर चालाकी की इसमें क्या बात हुई। कैबिनेट ने भी इसको देखा फाइनेन्स ने देखा, सभी ने देखा, सदन ने भी देखा।

अब इसमें मोटे रूप से २४ लाख का ज्यादा खर्चा है, गये साल से। वह कैसे है यह बताता हूं। इसमें ८ लाख का नया खर्चा है, बाकी सब पुराना है। इस ८ लाख में भी १॥ लाख रेकरिंग है, बाकी नॉनरेकरिंग है। बाकी १५, १६ लाख में ९ लाख डीयरनेस जो बढ़ा, वह हैं। ६ लाख के करीब ग्रेड इन्क्रीमेन्ट वगैरह है। तो यह मोटा हिसाब है। डिटेल में इस समय मैं नहीं जाऊंगा।

अब मैं बताऊं ५१–५२ में २१ करोड़ के आसपास बजट था। आज उससे दो करोड़ का डिफरेन्स है। तो इस तरह से आठ नौ साल के पीरियड में दो करोड़ बढ़ा है। रुपया तो बढ़ा है पर कैसे बढ़ा यह सोचने की बात है। इसे अनेलिसिस करने की जरूरत है। मोटे तौर पर समझ लीजिये कि ९ साल में एन्युअल इन्क्रीमेन्ट की कुछ रकम है, हिसाब लगाया गया तो करीब ७० लाख के यह हुआ। ८,९ लाख रुपया एन्युअल ग्रेड इन्क्रीमेन्ट का मिलता है। इसके अलावा दो इन्क्रीमेन्ट दिये पांच पांच रुपये के ५८ और ५७ में। इसके हिसाब से २०।२२ लाख के करीब वह हो जाता है। कुछ इन्टीग्रेशन और रेशनेलाइज़ेशन जो अजमेर का हुआ उसमें, बढ़ा। इस तरह से यह एक करोड़ तो यों ही हो जाता है। अब रहा एक करोड़ रुपया।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : On point of information Sir, I would like to know from the Hon. Minister who is calculating these figures due to the increase in the pay scales, but at the same time there must be some saving by people retiring from service etc.

श्री रामकिशोर व्यास : अब एक करोड़ बाकी रहता है।

श्री पी. के. चौधरी : एक करोड़ राइट ऑफ कर दें।

श्री रामकिशोर व्यास : आप सुनें तो सही। सुनने के बाद आप अपनी राय बदल देंगे। अब अजमेर के आने से जो रिऑर्गेना-

(श्री रामकिशोर व्यास)

इज़ेशन हुआ उससे ५० लाख रुपया बढ़ा। १४, १५ लाख, सन् ५७ में कन्सेशन्स अनाउन्स किये थे उसमें बढ़ा जैसे मैस अलाउन्स, मेडिकल फैसेलिटिज़ आदि दिये थे और ८, ६ लाख रुपया इस साल का इन्क्रीमेन्ट अब ५० लाख एक हुए, १४ लाख ये और ६ लाख ये और २७ लाख के करीब मिसलेनियस इम्प्लीमेन्ट्स इधर उधर हुए। तो यह दो करोड़ का हिसाब मैंने आपको बताया। आना पाई के हिसाब से जरुर नहीं बताया है। तो कोई आइटम नहीं बढ़ाया हो, ऐसी बात नहीं है। अब इसमें हमने आर्म्स और एम्यूनिशन्स भी नये लिये हैं, पहले हालत बहुत खराब थी, उसे भी सुधारा है, यूनीफार्म नहीं थी, वे भी कराई हैं वेहिकल्स नहीं थीं, वे भी ली हैं, तो धीरे धीरे यह सब करना पड़ा। तो कुल सालों में २०,२५ लाख का और खर्चा हुआ। इस पर डिटेल में डिमान्ड के वक्त कहा जा सकता है।

अब यह सवाल रहा कि इतने की क्या जरूरत है, कम कर दीजिये। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोब्लेम मेरे दिमाग में यह है और सोच भी रहे हैं कि इसे कुछ कम किया जाय पर दो तीन मोटी मोटी बातें मैं निवेदन करु कि पुलिस का काम जो है महज इतना ही नहीं है कि कोई ओफेन्स हो जावे उसको पकड़ कर चालान कर दे बल्कि उसका प्रीवेन्टिव साइड भी है और यह भी बड़ा इम्पोर्टेन्ट साइड है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : On a Point if order, sir. There is some intrudence n the House. Is that in order?

श्री अध्यक्ष : He is not disturbing the House.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : I think according to the parliamentary practice communication inside the House with an outsider is not desirable.

श्री अध्यय : But there is no disturbance.

श्री रामकिशोर व्यास : तो अब हमें परिस्थिति देखनी पड़ेगी कि क्या अब वह वक्त आ गया है जब काट छांट की जा सकती है, यह विचारने की बात है। मैं मना नहीं करता। पर यह सोचना होगा कि क्या ऐसी स्थिति हो गई है कि कम करने से वापिस वही आठ साल पहले वाली स्थिति तो नहीं पैदा हो जावेगी, यह आप सोच लें। फिर आप यह न कहें कि अब चोरियां होने लग गई, डाके पड़ने लग गये और शान्ति व सुरक्षा फिर खतरे में पड़ गई है। तो उसको बनाये रखने के लिये भी यह जरुरी है कि अभी उस में कोई कमी न की जाय। अगर अब भी लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्या ठीक नहीं हुई है, चोरियां हो रही हैं और डकैतियां हो रही हैं तो फिर पुलिस में खर्चा कम करने की बात क्यों करते हैं? इसलिए यह अभी बहुत गौर करने की बात है। आप उसमें से कितना कम करेंगे और कैसे कम करेंगे और हमें बहुत ही कॉन्शियसली वाच करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि हमारे भी कुछ पड़ौसी मुल्क हैं। हमारे यहां की ही व्यवस्था ठीक होने से काम नहीं चलता, दूसरे जो राज्य हैं उनकी क्या परिस्थिति है। कई दफा ऐसे मौके आते हैं कि राजस्थान के डाकू नहीं तो कभी पाकिस्तान

(श्री रामकिशोर व्यास)

के डाकू आ जाते हैं और कभी मध्यप्रदेश के डाकू आ जाते हैं तो कभी यू० पी० के डाकू आ जाते हैं और हमारे राज्य में आकर आतंक फैलाते हैं, इसके प्रति भी हम जागरूक रहते हैं। तो, जो हमारी नेबरिंग स्टेट वाले कुछ करते हैं तो उसको भी संभालने की जरूरत है। यह समस्या दूसरे प्रान्तों की भी है और उनको वाच करने की काफी जरूरत रहती है। अक्सर यह कहा गया है कि आर० ए० सी० का खर्चा सेन्टर से राजस्थान सरकार को लेना चाहिये। मैं आपको बताऊं कि इसके लिए हमने कोशिश की है, उनको कई बार इस मामले पर रिप्रेज़ेन्ट भी किया है लेकिन वे ऐग्री नहीं करते हैं? हां, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करने पर यह हो सकता है कि भारत सरकार नॉनरेकरिंग ग्रान्ट दे दे लेकिन वह रेकरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी राजस्थान की आर० ए०सी०के मामले में मानते हैं, इसलिए आर० एस० सी० के लिए यह कहना कि भारत सरकार ही इसका खर्चा वहन करे, यह सम्भव नहीं है। अगर सेन्टर पे करने को तैयार है तो ठीक है, लेकिन वह तैयार नहीं है। आर० ए० सी० के लिए यह कहना कि उसको कम कर दिया जाये आज की परिस्थिति को देखते हुए रिडक्शन पॉसीबल नहीं है और बॉर्डर को खाली छोड़ दें, यह सम्भव नहीं है।

इसके अलावा एक बात और कहूँगा। यह बात नहीं है कि मैं पुलिस विभाग के बारे में क्रिटिसिज़्म सुनना नहीं चाहता या उसके बारे में जो दोष बताये जाते हैं वह सुनना पसन्द नहीं करता। मैं आपको पूरा यकीन दिलाना चाहता हूँ कि यह बात सही नहीं है। क्रिटिसिज़्म यदि वह फेयर क्रिटिसिज़्म हों तो उनको मैं वेलकम करूंगा। असल में बात यह भी है कि मैं अपने विचार अर्ज करता हूं। बहुत से मामलात ऐसे हैं कि जिनको मैं खुद नहीं देख सकता और कईयों की ठीक इनफर्मेशन मुझे नहीं मिलती। मुझे आपके जरिये भी बहुत सी इनफर्मेशन मिलती है और जो आप क्वेश्चन्स रखते हैं उनके जरिये भी बहुत सी इनफर्मेशन मिलती है लेकिन मैं आप से दो बातें इस सम्बंध में अर्ज करना चाहता हूं और वे ये हैं कि आपके जितने भी क्रिटिसिज़्म हों वह फेयर होने चाहिए। वैसे आपकी तरफ से जो भी क्रिटिसिज़्म होंगे मैं उनको वैलकम करता हूं, क्रिटिसिज़्म करने भी जरूर चाहिए, सुझाव भी जरूर आने चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या खराबियां हैं। लेकिन इन सारे क्रिटिसिज्म होने के बाद मैं दो बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो यह है कि यह नीति होनी चाहिए जिसको मैं चाहता हूं और गवर्नमेन्ट भी चाहती है कि पुलिस और पब्लिक के बीच में ज्यादा से ज्यादा को-ऑपरेशन बढ़ना चाहिए उनके आपस के फीलिंग्स कम होने चाहिए। एक लीगेसी जो बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है उसको ग्रेजुएली कम करना चाहिए। आपस में एक दूसरे के नज़दीक आना चाहिए। तो इन क्रिटिसिज्म का ऐसा रूप न आ जाये कि वह दोष बढ़ता ही जाये। वैसे इसकी शुरुआत ही है, हमें उसमें कुछ सफलता भी मिली है, वैसे अभी बहुत गुंजाइश है काम करने की। पब्लिक कोऑपरेशन के मामले में उन्होंने बहुत कुछ किया है लेकिन जो नीचे का लेवल है उनमें अभी भी सुधार करने की आवश्यकता है। उनके व्यवहारों के बारे में कई बार शिकायतें आती हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि

(श्री रामकिशोर व्यास)

को-ऑपरेशन दिन व दिन बढ़ना चाहिए और यह सब आपकी ही मदद से सम्भव हो सकता है। जो गल्फ दोनों के बीच में पड़ी हुई है वह कम होनी चाहिए। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्रिटिसिज्म वेलकम हैं लेकिन वह क्रिटिसिज्म, ऐसे क्रिटिसिज्म न हों कि जिनकी आप बढ़ोतरी करना चाहते हैं उनके ऊपर इन क्रिटिसिज्म का उल्टा असर पड़े। जिनको आप मॉरेलाइज़ करना चाहते हैं, जिनका आप नैतिक स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं, उनके दिमाग पर अगर उल्टा असर पड़ता हो तो ऐसे क्रिटिसिज्म से क्या फायदा! आपका उद्देश्य उनकी उन्नति करने का है लेकिन उसका परिणाम उल्टा निकलता है तो वह मामला ठीक नहीं बैठता। एक आदमी रिश्वत खा जाता है या दूसरा गुनाह करता है उसकी वजह से आप जनरल फरमादें कि सारा पुलिस डिपार्टमेन्ट चोर है, बेईमान है और उसमें भ्रष्टाचार हैं, यह कहां तक ठीक है। मैं यह नहीं कहता कि उसमें ऐब नहीं है लेकिन एक दो केस की वजह से आप सारी जनरल बातें सारे डिपार्टमेंट के लिये कह दें, यह ठीक नहीं है। क्योंकि जिन के लिए आप कहते हैं वे यह फील करते हैं जब आप उनको कहते हैं कि रिश्वत लेते हैं, चोरी करते हैं, बेईमान हैं तो उनका ऑनर तो सेफ ही नहीं है इसलिए वह और भी काम करने में नहीं हिचकिचाते और इस तरह से उन पर उल्टा असर पड़ता है। इसलिए यह जो पिक्चर है उसको आप इस लाइट में कन्स्ट्रक्टिव बना दें कि जिसने भी गलत काम किया है, चोरी की है, रिश्वत ली है या बेईमानी की है उसके लिये आप जरूर शिकायत करें, यह खुशी की बात है। पर सारे डिपार्टमेंट के लिए कह देना, जहां कि बीस पच्चीस हजार आदमी हैं, ठीक नहीं है। उसमें से हो सकता है कि दस-बीस आदमी खराब हों लेकिन उनकी वजह से आप सारे के सारों को बेईमान बना दें तो यह कहां तक ठीक है, आप स्वयं ही सोचो। आप ईमानदार को भी बेईमान बना दें तो यह तो आपका उद्देश्य नहीं है। जो खराब हैं उनको अच्छा बनायें, यही आपका लक्ष्य होगा। मैं आपको बताऊं कि अभी कल ही मुझे एक महाशय का पत्र प्राप्त हुआ उसमें ऐसा था कि किसी आदमी का एक हज़ार रुपया गिर गया और किसी पुलिस वाले ने उठा लिया वह उसने लेकर थाने पर जमा करा दिया और रुपया ओनर को मिल गया। मुझे ओनर ने कल ही एक चिट्ठी लिखी कि मुझे रुपया मिल गया। तो, मैं आपसे कह रहा था कि सभी लोग तो दुनिया में बेईमान नहीं होते हैं....

श्री मदसिंह : जो ईमानदार हैं उनको आप टिकने भी तो नहीं देते हैं, ट्रान्सफर कर देते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : हम तो इस बात की कोशिश करते हैं कि ईमानदार रहें, आप बेइमानों को बेईमान कहें तो ठीक है परन्तु ईमानदार को भी बेईमान कहें तो कहां तक ठीक है ?

श्री मदनसिंह : मैं तो कभी नहीं कहता।

श्री रामकिशोर व्यास : आप ठीक कहते है। उसको आज जनरलाइज़ कर दें तो यह ठीक नहीं है। इन्डीविजुअल किसी

(श्री रामकिशोर व्यास)

की गलती हो तो इन्क्वायरी वगैरह करवा सकते हैं। अगर दूसरी स्टेट्स से पुलिस के मामले में हम राजस्थान को कम्पेयर करें तो राजस्थान में खर्चा पुलिस पर कम रहता है। मध्य प्रदेश जो है वह नेबरिंग स्टेट है।

श्री पी० के० चौधरी : इर्रिगेशन पर कुछ नहीं बोले, वह भी आपका है।

श्री रामकिशोर व्यास : आप उस विषय में कुछ बोले ही नहीं। जैसे मध्यप्रदेश है तो मध्यप्रदेश पुलिस पर ५ करोड़ रुपया खर्च करती है। वह अपने बजट से ज्यादा है। पंजाब भी ज्यादा करता है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : तनख्वाह कम है या ज्यादा है?

श्री रामकिशोर व्यास : कम भी है, ज्यादा भी है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं इस मामले में कि कहां खर्च में कमी हो सकती है, कौन सी चौकियां कम हो सकती हैं उसको हम एग्ज़ामिन कर रहे हैं और इसके लिए एक कमेटी बैठाई है वह जांच कर रही है कि कहां कमियां की जा सकती हैं, किस तरह से सारे खर्चे का नेशनेलाइजेशन किया जा सकता है। जो भी गड़बड़ियां होती हैं उनके लिये हम एक्शन जरूर लेते हैं लेकिन उसकी पब्लिसिटी कम करते हैं।

एक पॉइन्ट पर जल्दी से बोल कर समाप्त करता हूं और वह है सैपरेशन ऑफ एग्ज़ीक्यूटिव फ्रॉम ज्युडिशियरी। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि इसके बारे में हमने एक कमेटी बैठा रखी है जिसके चेयरमेन जस्टिस बापना हैं और कमेटी इस समय करीब करीब कन्क्लुज़िव स्टेज पर ही है और जैसे ही उसका रिज़ल्ट आयेगा उसको देख कर जो कुछ भी हम कर सकते हैं, वह करेंगे। अभी अभी जैसे ३६ मुनसिफ मजिस्ट्रेट्स बनाये हैं यह भी कहा गया कि एज़ीटेशन के मामले में सेन्ट परसेन्ट कन्विक्शन्स हुए हैं तो मैं आपको बताऊं कि जब कि लोगों ने कबूल ही कर लिया तो कनविक्शन तो होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं उनके बारे में मैं डिमान्ड्स के टाइम पर निवेदन करूंगा। इर्रिगेशन के ऊपर डिमांड आने वाली है उसी समय राजसमन्द के बारे में कहूंगा क्योंकि इस पर भी कुछ कहा गया। इसके पेपर्स मैंने मंगाये हैं, अभी आये नहीं हैं।

श्री गिरधारीलाल (नोखा): क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि यह जो इस समय आर० ए० सी० का खर्चा है यह राज्य सरकार कब तक उठाती रहेगी? इसके लिए सेन्टर से बात की है या नहीं? अगर बात की है तो क्या रहा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : जब तक बोर्डर की समस्या है।

(विराम)

श्री मोहनलाल सुखाडिया : अध्यक्ष महोदय, इस बजट के प्रस्तुत होने के बाद...

श्री भैरोंसिंह : वित्त मंत्रीजी को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा क्या?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे बाद में वे ही फरमावेंगे।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है उसके सम्बंध में हमारे श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह बिल्कुल महत्वपूर्ण बजट नहीं है, इसमें अक्रे और न जाने क्या क्या भरे हुए हैं इस तरह की सारी बातों का जिक्र किया। मैं समझता हूं इस बजट को गहराई से देखा जाता तो बहुत कुछ इसमें से जानकारी के लिये प्राप्त किया जा सकता था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करूं कि आज सारे भारत-वर्ष में हम एक योजनाबद्ध तरीके से अपने अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के प्रयत्न में लगे हुए हैं और जिस जगह विकास के लिये अधिक कार्य किया जा सकता है, हमको जितना ज्यादा धन प्राप्त हो सकता है उतना ही नहीं बल्कि राज्य की ज्यादा प्रगति करने में कामयाब हुए हैं। सौभाग्य से राजस्थान के अन्दर अब तक के राजस्थान के जितने बजट आये हैं और पिछले वर्ष का भी बजट था, उसके मुकाबले में सबसे ज्यादा विकास कार्य के लिये धन राशि रखी है। मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्यों को जानकारी है कि पिछले वर्ष हमारे प्लान के खर्चे में करीब २० करोड़ रुपयों का प्रोविजन किया गया था, उसके मुकाबले में इस साल सीलिंग के अन्दर और बाहर, कुल मिलाकर हमारे इस बजट में जो रकम रखी गई है वह ३८.५ करोड़ है जिसमें राजस्थान केनाल का खर्चा भी शामिल किया गया है। राजस्थान केनाल, मैं समझता हूं, जितनी महत्वपूर्ण है उसके सम्बंध में चर्चा करने की सदन में आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह ३८.५ करोड़ का बजट प्लान एक्सपेन्डिचर के लिये राजस्थान विधान सभा और राजस्थान राज्य में पहली बार इतना बड़ा आयोजन किया जाने वाला है। इसके लिये हम पर जिम्मेदारियां भी काफी आती हैं क्योंकि हम अपने प्लान को यदि पूरा करना चाहते हैं तो यह स्वाभाविक बात है कि इसकी पूर्ति के लिये हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। हमारे यहां अब तक जो प्लान की प्रगति हुई है, मैं समझता हूँ माननीय सदस्यों ने उसको गहराई के साथ देखा होगा और उनको यह संतोष हुआ होगा कि अब तक जो पिछले तीन वर्ष समाप्त हुए इन तीन वर्षों में राजस्थान राज्य में जो कुछ प्लान पर खर्चा हुआ वह भारत वर्ष की औसत से कुछ ज्यादा है, ५० पर्सेन्ट....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व): On a point of information, Sir. I would like to know that the figures given by him. He says, about 38 crores has been Inside ceiling and outside the ceiling, total budget comes to 48 crores so after our plan policy, we are running our budget by 10 crores only.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I am sorry.

टोटल हमारा जो बजट है वह ६४ करोड़ का है इसलिये मैं समझता हूं कि मैंने जो निवेदन किया वह ठीक है। अब मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करूं कि किस तेज़ी के साथ हम विकास के लिये राजस्थान में सफल हुए हैं। जो पहली पंच वर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में कार्य किया, सन् ५१–५२

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

में २ करोड़ १७ लाख के करीब खर्च कर पाये थे, ५२,५३ में २ करोड़ ८३ लाख रू० खर्च कर पाये थे, ५३–५४ में ५ करोड़ २२ लाख रूपये, ५४–५५ में ८ करोड़ १६ लाख रूपये, ५५–५६ में १३ करोड़ ११ लाख रूपये, ५६–५७ में १३ करोड़ ६ लाख रूपये, ५७–५८ में १५ करोड़ ३ लाख रूपये, ५८–५६ में १६ करोड़ रूपये रखे थे और इस साल यह रकम बढ़ा कर हमने २४ करोड़ कर दी है जिसमें से कुछ रूपये राजस्थान के पोरशन के केनाल पर खर्च होंगे बाकी राजस्थान के हिस्से में खर्च होने वाले हैं, ऐसी व्यवस्था है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हम राजस्थान के विकास के लिये इतनी बड़ी धन राशि खर्च करके उसका विकास करना चाहते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हमें मान कर चलना होगा कि हम पर भी ज़िम्मेदारीयां आयेंगी। जो फ़ाइनेन्स कमीशन राजस्थान में आया और उसने जो रिपोर्ट दी उसके बाद में यह आशा की गई कि राजस्थान का बजट संतुलित हो और हम इस बात का प्रयत्न करें कि आगे घाटे का बजट होकर पेचीदगी पैदा न हो। अध्यक्ष महोदय, इस साल भी यह सवाल था कि या तो ११ करोड़ रूपये राजस्थान अपने रिसोरसेज़ से प्राप्त करे या जो कुछ बजट रखें वह हमारे सीलिंग पर हो, २४ करोड़ का है उसमें कमी होने दें, मैं समझता हूं माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि राजस्थान कई कारणों से पिछड़ा रहा है उसको यदि आगे ले जाना है तो हमें यह प्रयत्न करना होगा कि १०५ करोड़ का जो पूरा प्लान है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करें और यदि हम इसमें सफल नहीं होंगे तो इसका असर न केवल दूसरे प्लान पर ही पड़ेगा बल्कि तीसरे प्लान पर भी पड़ेगा और जो तीसरा प्लान बनेगा उसके अन्दर भी कमज़ोरी हो जायगी। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है और अभी से हमें पूरे तौर पर ख्याल रख कर चलना होगा। तीसरी योजना बनाने का कार्य अभी से शुरू हुआ है। जो योजना बने वह इस प्रकार की हो जिससे राजस्थान में जो बहुत सी कमियां रह गई हैं उनको जिस हद तक हो सके उस हद तक पूरा करने में प्रयत्नशील हों। जब इतना बड़ा प्रयत्न एक राज्य में करना होता है तो स्वाभाविक होता है कि उसका असर एक दूसरे पर पड़े बिना नहीं रहता।

इस बजट में जो पैसेन्जर फेअर टैक्स के बारे में कहा गया है उस के बारे में भी यहां पर कहा गया और आम तौर से यह बात कही गई कि आम लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक हद तक ठीक है कि जो सफ़र करेंगे उन पर असर जायगा और कुछ जो ट्रान्सपोर्ट चलाते हैं उन पर भी जायगा यदि हम यह कहें कि आम लोगों पर कुछ नहीं जायगा तो यह उचित नहीं होगा, जायगा। लेकिन आज जो प्लान का इतना बड़ा आयोजन करना चाहते हैं उसका असर सब को भुगतने को तैयार रहना पड़ेगा तभी इतनी बड़ी कल्पना करके आगे बढ़ने में प्रयत्नशील हो सकते है। अभी इस प्रकार का टैक्स पंजाब में भी है, हमारा बजट प्रस्तुत हुआ उससे पहले मध्यप्रदेश में भी लगाया गया है और कहां कहां है इसकी जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है। लेकिन यह इस

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

प्रकार का टैक्स है जिसमें जो सड़कें बनाई गई हैं और जो दूसरे वर्क्स होंगे उसका लाभ या रिटर्न किसी तरह से राजस्थान सरकार को वाजिब तौर से होता है तो उसमें माननीय सदस्यों का सहयोग प्राप्त होना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ बार बार इस प्रश्न को उठाया जाता है, जो खास तौर से मंहगाई से सम्बन्ध रखता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि पिछले जो कुछ महीने निकले, वे राजस्थान के लिए ही नहीं, सारे देश के लिए अन्न की दृष्टि से पेचीदगी भरे महीने थे लेकिन हमने राजस्थान में इस मुश्किल के वक्त को, क्रिटिकल वक्त को, थोड़ा ठीक तरह से सम्भालने की कोशिश की। इसमें कमी रही होगी, मैं नहीं कहता कि कमी नहीं रही लेकिन जितनी बड़ी मुश्किल थी, पंजाब जैसे अन्न के भंडार के सामने यह मुश्किल आई, वहां राजस्थान के अन्दर हमने इस पीरियड को निकाला एक ऐसी व्यवस्था करके, जिससे कहीं पर बहुत ज्यादा मुश्किल न हो। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हम मंहगाई के बारे में बहुत बात करते हैं, शायद ज्यादा वक्त नहीं होगा, कुछ समय के अन्दर राजस्थान के अन्दर स्थिति आयेगी, जब भाव काफी नीचे आ जायेंगे। मंहगाई की वजह से बहुत सी बातों की अगले वर्ष के बारे में कल्पना करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ यह उचित बात नहीं होगी। हम यह मान कर चलें कि खरीफ की और क्रोप की बम्पर करीब आने वाली है, उसका असर आगे जाकर क्या होने वाला है। आज भी चने का भाव काफी गिरा है। मुझे तो यहां तक जानकारी दी है कि गंगानगर की एक आध तहसील से कुछ लोगों को कहा गया कि साढ़े आठ रुपये मन चना लाख दो लाख मन चाहिए, तो मिल सकेगा। इस तरह से एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को सूचित किया है। इस वक्त भी चने का भाव १४ रु० मन और १५ रु० मन हो गया। इसके अलावा बाजरा कल ही करीब साढ़े तीन सेर के आस पास जयपुर के अन्दर बिका है। तो ज्यों ही रबी की फसल बाजार में आती है, तो भाव जो आज हैं, वे कम होने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि खाद्य के अन्दर ज्यादा उत्पादन होगा और जैसा कि आपको ज्ञात है कि राजस्थान ज़ोन गेहूँ के लिए अलग कर दिया है, उससे भी राजस्थान में वह समस्या खड़ी नहीं हो सकती है और मुझे आशा है कि आगे के बारे में विचार करें तो इस बात को दृष्टि में रखते हुए करें कि खाद्यान्नों के भाव जो आज हैं, वे यही न रह कर निश्चित तौर पर कम होंगे।

४. २. म० प०

स्टेट ट्रेडिंग के सम्बन्ध में कहा गया, कई माननीय सदस्यों ने इसके बारे में कहा। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि धीरे-धीरे सरकार तो एक प्रकार से व्यापारी की तरह बनती चली जा रही है। आज स्टेट ट्रेडिंग की बात कहते हैं तो वे कहते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। फिर कहीं नल लगाते हैं तो कहते हैं कि नल से व्यापार किया जाता है, पानी बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अगर माननीय सदस्यों की यह राय हो जाय कि जहां एक बार नल लग जाय, तो वहां पानी फ्री कर दिया जाय और बाकी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

के राजस्थान को कह दिया जाय कि नल जहां लगा है, वहां पानी फ्री रहेगा और दूसरी जगह नल की आशा नहीं करनी चाहिए। तब तो यह बात हो सकती है वरन केपीटल एक्सपेन्डीचर के लिए कर्जा लेते हैं। कर्जे के लिए श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य को एतराज होता है, कर्जे को किस तरह चुकाया जायगा, इसकी उन्हें चिन्ता होती है। मैं निवेदन करूं कि केपीटल एक्सपेन्डीचर में से नल पर खर्चा होता है, इसे चुकाने के लिए, नल लगाने के जो दाम आये हैं, वे लेते हैं। अगर वह नहीं लेंगे तो वह कर्जा कितना ज्यादा हो जायगा, उन रुपयों का क्या होगा? इसलिए यह व्यवस्था करते हैं तो माननीय सदस्य के पार्टी वाले कोटा में आन्दोलन शुरु कर देते हैं और कहते हैं, नहीं, नहीं, पानी की रेट बढ़ाओ मत, अगर बढ़ा देते हो तो वाजिब नहीं होगा।

इसके बाद बैटरमेंट लेवी का सवाल आया। माननीय सदस्य कहते हैं, बैटरमेंट लेवी नहीं होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि यह बैटरमेंट लेवी जो लगाई जाती है, मैं समझता हूँ सभी माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि यह आवश्यक है, आवश्यक इसलिए है कि आज जो कुछ कर्ज़ा है, १०० करोड़ का कर्जा कहिये, जो भी कर्ज़ा है, वह कर्ज़ा सारे राजस्थान पर है और मान लीजियेगा कि आज राजस्थान में राजस्थान केनाल आती है, भाखरा केनाल आती है, या चम्बल केनाल आती हैं, या मीडियम इरींगेशन वर्क्स बनाते हैं, तो इनकी वजह से जो करोड़ों रुपयों का खर्चा होता है, ५० करोड़ रुपया राजस्थान केनाल पर खर्च होगा, २७ करोड़ रुपया भाखरा पर खर्च हुआ, ५० लाख चम्बल केनाल पर होगा यह सारा कर्ज़ा सारे राजस्थान के ऊपर है। इससे जो तात्कालिक लाभ पहुंचता है, कुछ लाभ इन इलाकों में पहुंच सकता है। बैटरमेंट लेवी का एक सिद्धान्त है, और वह यह है कि जब कि नहर नहीं थीं, उस वक्त जमीन की कीमत थी, वह जमीन की कीमत, आज जब नहर का पानी पहुँचा है, इसके बाद, इस कीमत में एक तरह से बढ़ावा हुआ है, कुछ एडवान्टेजेज़ हुए हैं, उसका ५० प्रतिशत से ज्यादा बैटरमेंट लेवी के रुप में नहीं लगाना चाहते। इसी आधार पर बैटरमेंट लेवी तय की जाती है और वह भी १२ साल में इन्स्टालमेंट्स में वसूल की जाती है। मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करूं कि हम पहले भाखरा को लेकर चले। १८० रुपये के करीब-औसत तौर पर बैटरमेंट लेवी तय होती है एक एकड़ पर यानी एक एकड़ पर १८० रु० लेते हैं, और यह रुपया १२ साल में लेते हैं। इस प्रकार १५ रुपया सालाना के हिसाब से बैटरमेंट लेवी चार्ज होती है। कई माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि भाखरा जैसी नहर जिन इलाकों में आई और जहां १५ रुपया एक साल में बैटरमेंट लेवी के रूप में लेंगे, इस १५ रुपये को एक मन एक्स्ट्रा गेहूँ पैदा करके-एक व्यक्ति दे सकता है और राजस्थान के ऊपर जो कर्जा है, उसको चुकाने की समस्या हल हो सकती है। इसमें सब का ही सहयोग प्राप्त होना चाहिए। आज चम्बल के अन्दर वर्षा का पानी ज्यादा आने की वजह से वहां जमीन की कीमत कुछ ज्यादा है, क्रोप अश्योर्ड होने की वजह से करीब ७५ रु० एक एकड़ के आस पास बैटरमेंट लेवी तय की जाती है। मीडियम इरींगेशन वर्क्स जहां बने हैं वहां ५० रु० एक एकड़ पर बैटर-

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मेंट लेवी तय की जायगी। मैं नहीं समझता कि उसके बारे में अगर एक नीति बना ले कि नहीं, जहां पानी आ जाय, वहां बैटरमेंट लेवी वसूल न हो, मैं समझता हूं कि सारी बातें बड़ी मुश्किल हो जायेगी। आज राजस्थान केनाल से आशा करते हैं, और प्राजेक्ट्स को इसलिए आगे बढ़ाया रहा है कि इनमें जो कुछ खर्चा होगा, वह बहुत कुछ पूरा हो सकता है और प्रोडक्शन काफी आगे बढ़ेगा। जहां तक किसानों का प्रश्न है, पहले से जमीनों की कीमत बढ़ी हैं और फसल अच्छी हुई है। पानी आने के बाद १२ साल के बाद उनके पास हमेशा के लिए अधिक कीमत की ज़मीन रहती है, वह ज्यादा कीमत की चीज़ होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली जमीन उनके पास होगी। मैं समझता हूँ कि इस स्थिति में अगर बैटरमेंट लेवी का विरोध होता है तो उसका मतलब यह होता है कि एक जगह जहां एक आदमी की पैदावार करने की कैपेसिटी ज़्यादा हुई है, डवलपमेंट वर्क्स की वजह से कैपेसिटी ज़्यादा हुई है, उससे कहें कि धीरे-धीरे वह राजस्थान के लिए कुछ कन्ट्रीब्यूट करें। इसमें अगर विरोध की बात आये, तो मुश्किल बात होगी और उसका असर पूरे राजस्थान पर पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि इस दृष्टि से सभी माननीय सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा और हम अपने यहां ज़्यादा पैदावार बढ़ाने में कामयाब होंगे।

इसी प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, यहां पर विरोध किया गया इस बात का कि बेकारी की समस्या राजस्थान के अन्दर काफी बढ़ी हुई है और सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर पाई है। अभी तक हमारे पास बहुत आंकड़े नहीं थे, धीरे धीरे आंकड़े इकट्ठे कर पाये हैं, उससे ज्ञात होता है कि ऐसी स्थिति नहीं हो पाई है कि हमने कुछ नहीं किया है। उसके मुकाबले में कुछ करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जो कुछ जानकारी प्राप्त हो सकी है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। १९५७ में जो ऑल इन्डिया सर्वे, नेशनल सर्वे सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की तरफ से हुई, वह इस बात की भी थी कि जो ग्रेजुएट्स हैं, उनकी सर्वे की कि कहां कहां कितने कितने अनएम्प्लाइड हैं और उन्होंने जो सर्वे की, उस सर्वे का परिणाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं अलग अलग स्टेट्स के कम्पेरीजन में राजस्थान की स्थिति आपके सामने रख दूं। आंध्र में ७·७ परसेन्ट एक तरह से बेकार ग्रेजुएट्स की तादाद है, आसाम में ०·८ है, बिहार में ३·७ है, बम्बई में १·१····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This percentage is on what basis? Population of that State?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह भी मैं कह दूँगा, वह भी है। मैं नम्बर भी बता दूँ, आंध्र में १९६० आदमी, ५५ महिलायें टोटल २०१५····

श्री पी. के. चौधरी : The Question was whether this ratio is in proportion to the total unemployed or in proportion to the population.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I mean total number of graduates and corresponding number of unemployed. मैं समझता हूं उसके आधार पर आसाम के अन्दर, मैंने आपसे निवेदन किया, ०·५ है····

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : टोटल नम्बर ऑफ ग्रेजुएट्स में वे ग्रेजुएट्स भी शामिल हैं, जो सर्विस में हैं। या यह नम्बर उनका ही है जो अनएम्प्लायड हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अन-एम्प्लॉयड का पर्सेन्टेज बता रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : किस पर आयेगा यह पर्सेन्टेज ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अनए-म्प्लॉयड का पर्सेन्टेज बोल रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : अनएम्प्लॉयड का पर्सेन्टेज दे दिया। अनएम्प्लॉयड जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, उनका विवरण बताया कि ७·७ पर्सेन्ट हैं, यह पर्सेन्टेज किस बेसिस पर है ? जो टोटल स्ट्रेन्थ है ग्रेजुएट्स की, उनमें से जो अनएम्प्लोयड हैं उनके हिसाब से पर्सेन्टेज है या टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से जो ग्रेजुएट्स अनएम्प्लोयड हैं उनका पर्सेन्टेज है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो ग्रेजु-एट्स हैं, उनमें जो अनएम्प्लोयड हैं उनका पर्सेन्टेज है। जैसे मान लीजिये १०० ग्रेजु-एट्स हैं और ७ अनएम्प्लोयड हैं तो पर्सेन्टेज ७ पर्सेन्टेज हुआ। मैं समझता हूं इसमें बहुत आसान बात है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): आसाम और उड़ीसा का ·७ बताया है जो बेकार हैं, तो यह ग्रेजुएट्स में से बेकार हैं उनके टोटल नम्बर के अनुसार बताया है या जो सारी जनसंख्या है, उसके अनुसार है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवे-दन किया कि अगर राजस्थान में १००० ग्रेजुएट्स हैं और उनमें से १५ अनएम्प्लोयड हैं तो परसेंटेज १॥ आयेगा।

आसाम	·७
बोम्बे	३·७
बिहार	१३·१
केरल	५·५
मद्रास	·६
मध्य प्रदेश	·२
मैसूर	५·७
उड़ीसा	·७
पंजाब	४·६
राजस्थान	१·६ टोटल, ४६६ पुरुष और २१ महिलाएं।
यू. पी.	१६·५
वेस्ट बंगाल	२०·३

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से थोड़ा फिर स्पष्टी-करण चाहूंगा। १६५७ में यहां सर्वे हुआ है, उसका पर्सेंटेज या तो उस समय ग्रेजुएट्स थे कुल उनका पर्सेंटेज है या ५७ में जितने ग्रेजुएट्स निकले हैं, उनमें से जिनको एम्प्लो-यमेंट नहीं मिला उनका पर्सेन्टेज है ? १६५७ के सर्वे के आधार पर यह पर्सेंटेज बताया गया है तो इसमें दो बातें हो सकती हैं, एक तो यह कि ५७ में आन्ध्र में कुल जितने ग्रेजुएट्स थे, उनमें से जो अनएम्प्लोयड थे उनका पर्सेन्टेज है या दूसरी बात यह है कि ५७ में आन्ध्र में जितने ग्रेजुएट्स निकले उनमें से अनएम्प्लोयड रहे, उनका पर्सेन्टेज है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : निकलने पर नहीं, जो टोटल ग्रेज्युएट्स हैं उनका पर्सेंटेज है।

श्री भैरोंसिंह : चाहे वे पहले सर्विस में हों?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम): राजस्थान में इस समय कुल कितने ग्रेज्युएट्स हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ये फिगर्स मेरे पास नहीं हैं, जो थे वे दे दिये।

श्री अर्जुनदास : Even according to that report, what is the number of Graduates in Rajasthan in 1957?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करूं कि टोटल नम्बर ऑफ ग्रेज्युएट्स थे उनका पर्सेन्टेज बताया है कि ४६६ मैंने और २१ वीमेंन अनएम्प्लोयड ग्रेज्युएट्स का नम्बर था उस समय की गई सर्वे के आधार पर आता है।

तो, कुल मिला कर अनएम्प्लोयमेंट की बात कहते हैं, उसका कितना असर है, यह इन आंकड़ों से मालूम हो जाता है।

श्री पी० के० चौधरी : How many women?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : २१।

श्री पी० के० चौधरी : मैं तो इससे ज्यादा जानता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Are these figures based on the employment exchanges statistics?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने तो रेफरेंस दे दिया है, जिस कमेटी ने सर्वे किया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ४२९ फीगर बताई हैं, ४२० प्लस नाइन, वह एम्प्लोयमेंट एक्स्चेन्ज के आधार पर है। एम्प्लोयमेंट एक्स्चेन्ज तो २० पर्सेन्ट भी एम्प्लोयमेंट नहीं दिला सकता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की तरफ से सर्वे कराई गई थी, उस रिपोर्ट में जो फीगर्स हैं वे ही मैंने रखे हैं। तो सेम्पल के तौर पर मैं रखना चाहता था। क्या इस समय होंगा, एम्प्लोयमेंट एक्स्चेन्ज की तरफ से जो एम्प्लोयमेंट दिलाने के लिये प्रयत्न किये गये, उन प्रयत्नों के फीगर्स की एक किताब निकली है, जो माननीय सदस्यों के पास होगी उससे मालूम होगा कि राजस्थान के एम्प्लोयमेंट एक्स्चेन्ज के जरिये राजस्थान में १९५६ में ५६०४ आदमियों को एम्प्लोयमेंट दिया गया और ५७—५८ में १२६२१ आदमियों को एम्प्लोयमेंट दिया गया। अब इससे एक्स्पेन्ड ही हो रहा है, यह मुझे निवेदन करना था।

जैसा कि मैंने शुरू में कहा सारी इन्फर्मेशन कम्प्लीट देखना चाहें तो इर्रिगेशन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू होंगे, पी० डब्लू० डी० के जगह जगह काम शुरू होंगे, उनकी सबकी तादाद को जोड़ें तो फीगर्स काफी बढ़े हुए मिलेंगे। अलग अलग स्कीम्स हैं उनसे लोगों को एम्प्लोयमेंट मिलता है। इर्रिगेशन की निगाह से देखें तो लोगों को काफी एम्प्लोयमेंट मिलता है। २५ बीघा अनइर्रिगेटेड लैंड है, उससे जितने लोगों को एम्प्लायमेंट मिलता है, उसी २५ बीघा ज़मीन पर इर्रिगेशन का प्रबन्ध कर देने पर कहीं ज्यादा लोगों को एम्प्लोयमेंट मिलता है। लो इन्कम हाउसिंग ग्रुप स्कीम्स के जरिये लोगों को काम मिलता है, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ के जरिये लोगों को

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

एम्प्लोयमेंट मिलता है। तो कई दिशाओं में राजस्थान में इन स्कीम्स के ज़रिये एम्प्लोयमेंट दिया गया है, दिया जा रहा है और आगे एम्प्लोयमेंट मिलेगा।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह टेम्परेरी है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे इन्टरप्ट न करें तो अच्छा है। यह टेम्परेरी नहीं बढ़ने वाला है। आप इन्हें टेम्परेरी समझ कर कहीं संतोष न कर बैठे कि आपको फिर बोलने का मौका मिलेगा।

इन्डस्ट्रीज़ और माइनिंग साइड है, उससे भी बताना चाहता हूं कि एम्प्लोयमेंट बढ़ रहा है।

The production of gypsum has increased from 6.4 lakh tons in 1955 to 9 lakh tons now, limestone from 8 lakh tons to 12 lakh tons, Bentonite from 600 tons to 2200 tons, Manganese from 2,000 tons to 12,000 tons Iron ore from 57,000 tons to 1 lakh tons, Lead and Zinc from 69,003 tons to 1½ lakh tons, Soapstone from 25,000 tons to 38,000 tons.

मैं इसलिये रखना चाहता था कि जो यह कल्पना की जाती है कि प्लान बढ़ रहे हैं, एम्प्लोयमेंट नहीं बढ़ रहा है, तो यह सही नहीं। आज तो जिन कामों को हाथ में लिया है उन कामों की वजह से एम्प्लोयमेंट बढ़ा है, बढ़ रहा है। पॉवर को ले लीजिये, पॉवर बढ़ता है तो पॉवर बढ़ने की वजह से एम्प्लोयमेन्ट बढ़ता है। हमें २१००० किलोवाट पॉवर इस साल अवेलेबल होगा तो इसकी वजह से एम्प्लोयमेन्ट काफी तेजी से राजस्थान में बढ़ेगा, तो एम्प्लोयमेंट वाला फिगर राजस्थान सरकार के सामने नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए चारों ओर प्रयत्न किया जाता है। इसके साथ हमारी रेस्पोन्सिबिलिटी....

श्री भोलानाथ (लक्ष्मणगढ़): ओन ए पाइन्ट ऑफ इन्फर्मेशन, सर, मैंने निवेदन किया था कि १० हजार पढ़े लिखे बेरोजगार तो ३१-५-५८ को एम्प्लोयमेंट एक्स्चेन्ज में रजिस्टर हो चुके थे और लगभग २६ हज़ार अदर सेक्शन्स में आते हैं, वे एम्प्लोयमेंट एक्स्चेन्ज में रजिस्टर्ड हो चुके थे तो लगभग ४० हजार आदमी अपने आपको अनएम्प्लोयमेंट पर एम्प्लोयमेंट एक्स्चेन्ज में रजिस्टर करवा चुके हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : रजिस्टर्ड करवाये हुओं में से लोगों को एम्प्लोयमेंट मिलता जाता है और जितने वहां रजिस्टर्ड हैं वे सभी अनएम्प्लोयड हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिये। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी एम्प्लोयड हैं वे बेटर ओपोर्च्युनिटी के लिये भी अपने आपको एम्प्लोयमेंट एक्स्चेन्ज में रजिस्टर करवाते हैं। ३१ मई, १६५८ में सेम्पल सर्वे किया गया तो इन रजिस्टर्ड लोगों के बारे में पता लगाया तो उनमें से बहुत से कहीं न कहीं एम्प्लोयड थे जिनका कि रजिस्टर में उनका नाम चला आता था। इसलिए निवेदन करूंगा कि इसके साथ में अन्दाज लगा कर नेट रिजल्ट पर पहुँच सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): जो काम पर हैं वे भी...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो रिपोर्ट

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

ही नहीं करे तो क्या किया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : जांच करे तब।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो बड़ा मुश्किल होगा।

श्री भोलानाथ : दूसरी बात मैंने यह कही थी कि १७ पर्सेन्ट तो अनएजुकेटेड को मिलता है और ८ या ६ पर्सेन्ट ही एजुकेटेड को एम्प्लोयमेन्ट मिलता है। यह एक बड़ी अजीब बात है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो सिंपल सर्वे किया गया और उस रजिस्टर में अन्-एम्प्लोयड के नाम लिखे हुए थे उसमें २८ प्रतिशत ऐसे थे जो एम्प्लोयमेन्ट पर लगे हुए थे। मैंने यह बात इसलिए रखी कि यह कहा गया कि एम्प्लायमेन्ट की सरकार का ध्यान नहीं है या सरकार को जानकारी न हो, यह कतई नहीं है। एक माननीय सदस्य जो फुलेरा से आये हैं उन्होंने कहा......

श्री भोलानाथ : मेहरबानी करके इसको फिर से चेक कर लीजिये, शायद मैंने कल गलत कह दिया हो कि ८.६ पर्सेन्ट एजुकेटेड को ही एम्प्लोयमेन्ट, एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज द्वारा मिलता है। यह चेक करने की बात है। यह एक सीरियस बात है, इस पर विचार करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ८.६ पर्सेन्ट तो नहीं, सन् ५७ में ६१७१६ ने रजिस्ट्रेशन करवाया उनमें से ८१०० के करीब को एम्प्लोयमेंट मिला, तो टोटल १२ पर्सेन्ट के करीब आयगा।

तो मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इकोनोमिक कमेटी गवर्नमेन्ट की ओर से बिठाई गई है वह घास काटती है क्या? मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि ऐसा नहीं है। इकोनोमिक कमेटी की ओर से जो प्रोपोज़ल्स आये हैं उनमें से २५ लाख के प्रोपोज़ल्स मंजूर कर दिये हैं और २१ लाख के पेन्डिंग हैं जिनको जल्दी से जल्दी स्वीकार किया जावेगा। और विभाग के प्रोपोज़ल्स तैयार किये जा रहे हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी अमल किया जाय। लेकिन कई माननीय सदस्यों ने कहा कि बजट में तो प्रोपोज़ल्स रख दिये जाते हैं लेकिन अमल में नहीं आते, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी बात नहीं है और न ही माननीय सदस्यों के सामने ऐसी बातें आवेंगी।

यह भी कहा गया कि सरप्लस बजट तो इसको बताया है लेकिन एक्चुअली यह डेफिसिट बजट निकलेगा। पिछले साल के बजट के सम्बन्ध में भी कहा गया कि ५७ लाख का डेफिसिट बजट हो गया जब कि वह सरप्लस बजट रखा गया था। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि बाईजीलाल की शादी के लिए रुपया देने की हमको क्या जरूरत है। मैं नम्रता पूर्वक माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि, यह तो राजस्थान बना था उस वक्त दिया गया था और जांच आदि में यह चलता रहा। यह तो खर्चा हो चुका था। इस साल तो इसका एडजस्टमेन्ट किया गया है। यह नहीं है कि देना है और इसलिए इसको रखा गया है या देना चाहते हैं, लेकिन एतराज चलते आ रहे थे और अब इसको केवल इसमें एडजस्ट किया गया

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

है। इसी तरह से १ करोड़ रुपया जो फूड ट्रेडिंग का चलता आ रहा था, राजस्थान बनने से पहले जो स्टेट्स थी और वार टाइम में ज्यादा से ज्यादा फूड ट्रेडिंग हुआ था, तो उस वक्त से मिला कर जो टोटल घाटा आया वह आठ साल का कुल मिला कर एक करोड़ का हुआ, वहां इस साल के बजट में एडजस्ट किया गया है। इसी तरह से २० लाख रुपया युनिवर्सिटी का देना था उसको भी एडजस्ट किया गया है। इस तरह से (एडजस्टमेन्ट का कुल मिला कर १, ३०,५०,०००) रुपया है इस बजट में जो १६ लाख ५० हजार का सरप्लस बताया गया था, तो एडजस्टमेन्ट किया गया है यह एक्चुअल रुपया देना हो, खर्च करना हो, या खर्च कर दिया और सेन्क्शन नहीं ली हो ऐसी बात नहीं है, यह तो पहले ही खर्च कर दिया गया था। यदि इसको निकाल देते है, एडजस्ट नहीं करते हैं तो यह सरप्लस बजट होता है।

श्री पी० के० चौधरी : शोर्ट फाल रहा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की रिसिट्स होती है वे भी होती है, रिसिट्स होती हैं, शिडयुल्ड एक्स्पेन्डीचर होता है, कोरेसपोन्डिंग एक्स्पेन्डीचर करते हैं कई चीजों के लिए, लेकिन सरप्लस पास करके डेफिसिट हो जाता है, यह कहना गलत है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जो डीयरनेस बढ़ाया गया है ५) का, वह भी अलग है। वह तो इस साल में जो खत्म हो रहा है, इस साल के एन्ड तक के एक्स्पेन्डीचर में आ गया। उसको मिला कर तो ७३ लाख से भी ऊपर जाता है, जो सरप्लस रहता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि साल के एन्ड में सरप्लस को डेफिसिट कर देना यह कभी भी प्रयोजन नहीं हो सकता।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि ११० करोड़ का कर्ज हो गया, कर्ज होगा तो सरप्लस कैसे होगा, राजस्थान तो दिवालिया स्टेट है और न जाने क्या २ जोड़ दिया गया, तो मैं समझता हूं कि डेवलपमेन्ट की इकॉनोमी को, अर्थशास्त्र को जो कोई अध्ययन करते है, कोई इन्कार नहीं करेगा कि फोरिन एक्सचेन्ज की डिफिकल्टी को मीट आउट करने के लिए, वर्ल्ड बैंक और फोरिन कंट्रीज़ के पास जाकर लोन्स लेकर और अपने यहां लोन्स रेज करके सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट और स्टेट गवर्नमेन्ट्स हर एक इस कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा विकास करें। लेकिन यदि रेवेन्यू को एक्सपेन्डीचर, तनख्वाहों आदि पर करते जांय और उसके लिए कर्ज करते जाय और स्टेट को कर्जदार बना दिया जांय तो वह तो गलत बात हो सकती है। लेकिन इस स्टेट ने इस तरह के कर्ज में राजस्थान को नहीं डाला है। जो कुछ किया है, मैं आपसे निवेदन करूं कि एक नोट साइक्लो स्टाइल्ड सर्कुलेट हुआ है उसको माननीय सदस्यों ने देखा होगा तो उससे ज़ाहिर है कि ११० करोड़ के असेट्स बिल्ड किये गये, भाखरा चम्बल आदि स्कीम्स को हाथ में लिया गया, जो लोन्स लेने हैं, जैसा कि श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा और यदि २६ करोड़ जोड़ दिया जाय तो कुल असेट्स जो डेबिटेड हैं....

श्री भैरोंसिंह : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, सोलिड असेट्स कितने हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

समझता हूं कि १३८ करोड़ के कुल असेट्स हैं...

श्री पी० के० चौधरी : What is a solid asset, Sir ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : This is a different term which one has to understand from the Hon'bleM ember आपका मकसद हो कि इलेक्ट्रिसिटी पर कितना खर्च हुआ उसका डेप्रिसियेशन क्या है, भाखरा डेम बना उसका क्या डेप्रिसियेशन है, तो मैं तो निवेदन यह कर रहा हूँ कि कुल १३६ करोड़ के असेट्स थे एज़ अगेन्स्ट ११० करोड़ के कुल मिलाकर, जो लिस्ट की तादाद आपने कल बतायी। राजस्थान स्टेट को किसी भी प्रकार से खतरा हो, ऐसी बात नहीं है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेटरमेन्ट लेवी और दूसरे असेट्स हैं, कुल मिला कर यह राजस्थान की स्थिति बनती है। इनडाइरेक्टली जो असेट्स डेवलप होते हैं वे अलग हैं। जैसे उदाहरण के लिए निवेदन करूं कि जिस किसान की जमीन पहले ५०) की थी वह और डेवलप हुई है और असेट्स बढ़े हैं। यह समझना कि राजस्थान स्टेट दिवालिया हो गई है, यह कतई गलत है। जो हमारी फाइनेन्शियल पोज़िशन है वह काफी साउन्ड है और यह सोचने का कोई प्रश्न खड़ा नही होता कि जो रुपया खर्च कर रहे हैं उसका कोई रिटर्न नहीं आने वाला है बल्कि आने वाले वर्षों में राजस्थान की केपेसिटी डेवलप होगी और धीरे २ डेवलप होगी। क्योंकि हमने भाखरा पर ज्यादा खर्च किया, चंबल बान्ध के ऊपर खर्चा किया उसके रिटर्नस मिलने अभी शुरू हुए नहीं। इसी तरह से राजस्थान केनाल पर हमें बहुत खर्चा करना होगा। यह सही है कि आज इस सरकार पर इस राज्य पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आकर पड़ी है उस ज़िम्मेदारी को हम स्वीकार करते हैं और उसी के कारण हम उसके बिल्ड करने में उसके असेट्स की तैयारी में लगे हैं वे आगे जाकर रिटर्न देने वाले हैं और वे इतना रिटर्न देने वाले हों उससे केवल राजस्थान का खर्चा ही नहीं बल्कि उस पर जो कर्ज़ा है उसको भी भुगतान करने में मदद मिले। कर्जे से भयभीत होने या हम यह सोचने लगें कि यह बहुत अजीब बात कर दी ऐसी बात नहीं है। मैंने इस बारे में यू० पी० के बजट से भी जानकारी की है यू० पी० गवर्नमेन्ट के बजट में सवा तीन सौ करोड़ रुपये का डेट है। यह आवश्यक है जब कि हम अपने प्रान्त को डेवलप करना चाहते हैं, जब हम इसके लिये असेट्स बिल्ड करने जा रहे हैं तो वैसी हालत में बिना कर्ज किये काम चलने वाला नहीं और इसी चीज़ को ध्यान में रख कर राजस्थान ने इतना कर्ज़ा किया।

एक बात और कही गई और वह यह कि हमारा एस्टेब्लिशमेन्ट पर खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। एक हद तक इस बात को ठीक कहा जा सकता है। एस्टेब्लिशमेन्ट का कुछ खर्चा है और उस खर्चे के लिये हमें कुछ विशेष बातों की ओर ध्यान रखना होगा। राजस्थान ही केवल एक ऐसा प्रदेश है जहां पर प्राइमरी एज्युकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी एज्युकेशन तक जितना खर्चा होता है वह सारा का सारा सरकार को उठाना पड़ता है। दूसरी जगह दूसरी स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट बोर्डस या लोकल बोडीज़ इस प्रकार के खर्चे को बरदाश्त करती है लेकिन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हमारे यहां उन सारे खर्चे को सरकार बरदाश्त करती है इसकी वजह से भी यह प्रशासन पर ज्यादा खर्च दिखाई देता है। इस पर्सेन्टेज़ के अन्दर धीरे-धीरे कमी हो रही है और हम इस ओर प्रयत्नशील भी है। एक उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि सन् ५७ ५८ में कुल एस्टेब्लिशमेन्ट पर खर्चा आता था ५०.६ लेकिन ५९-६० में वह खर्चा ४८.२ है। एस्टेब्लिशमेन्ट कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण हमारा खर्च बढ़ाये रखने के अन्दर काफी रेस्पोन्सिबल है।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूं आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि राजस्थान में इस समय जो कुल मिला कर शिक्षा पर हम खर्च करते हैं भारतवर्ष के अन्दर अन्य राज्यों में जितना खर्च होता है इस शिक्षा पर उसके कुछ आंकड़े मैंने गत सेशन में रखे थे। हम राजस्थान में १९५९-६० के बजट से शिक्षा के ऊपर व्यय कर रहे है २१.५. पर्सेन्ट खर्चा रखा गया है हमारी आमदनी का। इसके मुकाबले अलग अलग स्टेट्स के आंकड़े इकट्ठे करवाये थे उसमें राजस्थान, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन सब स्टेटों से राजस्थान में सब से ज्यादा पर्सेन्टेज था। राजस्थान में हम यदि किसी प्रकार का टैक्स लगाते हैं तो कहा जाता है कि इस प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिये। लेकिन इतना होते हुए भी मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि हम इस राज्य को कहां से कहां ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं इस बात को अगर आप लक्ष्य में रखें तो हमारी जिम्मेदारियां काफी बड़ी हैं। उनकी पूर्ति के लिये हमें काफी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। उन एफर्ट्स में माननीय सदस्यों का पूरा सहयोग प्राप्त होता रहेगा, यह मैं आशा करता हूं। उदाहरण की तौर पर पहली पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर हमारी स्टेट की शिक्षा का पर्सेन्टेज़ जो लेटेस्ट फीगर्स मेरे पास हैं उसके मुताबिक २३.९ आया। जब कि हम इस बात का प्रयत्न करना चाहते हैं कि इस प्लान की समाप्ति तक फीगर्स ५५ से ६० के आस पास पहुँच जाय। उसके मुकाबले आप इन एफर्ट्स की कल्पना कीजिये। इस एफर्ट्स तक पहुंचने के लिये कितना प्रयत्न हमें करना होगा। इसके मुकाबले में जब कुछ प्रोपोज़ल्स टैक्स के रूप में करते हैं जिसकी सदन में ज्यादा टीका हुई वह टैक्स तीस लाख रुपये का बसेज़ और ट्रान्सपोर्ट गुड्स पर है। यह मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जितना व्यापक काम हमारे सामने पड़ा है उसको पूरा करने के लिये हमें कुछ एफर्ट्स करने होंगे उसमें माननीय सदस्यों का सहयोग हमें ज्यादा से ज्यादा बल देने वाला है और कामयाबी देने वाला हो सकता है। जो कमियां हो उनको आप अवश्य कहें लेकिन एक तरफ जब आप तनख्वा बढ़ाने के लिये कहते हैं यह मैं भी मानता हूं कि आज काफी लोगों के सामने अपना खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है, उनकी तनख्वायें कम है। जब हम पांच रुपये की वृद्धि करते हैं तो वह भी कुछ भाइयों को बुरा लगता है। सब बात यह है कि पिछले अरसे में इस बात की कोशिश की गई है कि हम धीरे-धीरे इस दिशा में भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। पहले पांच सालों पर आप निगाह डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें काफी अन्तर आया है। इन महंगाई के वर्षों में जब कि सारी अर्थ व्यवस्था का ढांचा बिगड़ता जा रहा है आने वाले वर्षों में

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जब कि प्रोडक्शन की बढ़ोतरी होगी और भावों में और दूसरी बातों में भी कमी होगी, उसको भी हमें लक्ष्य में रख कर चलना है। आप किसी तरफ बढ़ा लीजिये कुल मिला कर रुपया तो इकट्ठा करना होगा और उसके लिये आम जनता पर वज़न पड़ता है। एक तरफ तो आप चाहते हैं कि कर्मचारियों की तनख्वा बढे. और दूसरी तरफ हमारे फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य मांग करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट और तहसीलों में कमी नहीं होती, तहसीलों जिलों में और थानों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता....

श्री पी. के. चौधरी : I never said that. I said that......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कुछ माननीय सदस्य यह सुझाव देते है कि इनमें कमी होनी चाहिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सभी माननीय सदस्य सहयोग देते हैं और हम जैसा कि उनसे आशा करते है, उनके कहने के अनुसार यदि कुछ न कुछ खर्च करने के अन्दर कामयाबी हो सकती है, तो सब मिला कर निर्णय कर दें कि १७ ही जिले रहें तो गवर्नमेन्ट कभी भी यह करने में नहीं झिझकेगी। लेकिन यह चाहते नहीं। जो भी सम्भावना खर्चे के कमी करने के सम्बन्ध में हो उसको स्वीकार करने में हमें एतराज नहीं हो सकता। जब हम यह काम करेंगे तो उनका प्रचार उसी दिशा में होगा। जैसा कि कल एक माननीय सदस्या ने कहा, जो आज नहीं आयी हैं कि जो फर्स्ट डिविज़न में लड़के आयेंगे उनको हमने स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था की है और उन लोगों के लिये जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो आगे पढ़ाने के लिये खर्चा नहीं कर सकते वे आगे पढ़ने के लिये महरूम नहीं रह सकें, इसलिये यह व्यवस्था हमने की है, उनको आगे पढ़ने का पूरा अवसर मिले। यह एक बेसिक निर्णय हमारा है लेकिन माननीय सदस्या ने रखा कि केवल फर्स्ट डिविज़न वालों के लिये यह क्यों होना चाहिये दूसरों के लिये क्यों नहीं। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि विदेशों में तो युनिवर्सिटी एज्युकेशन के लिये केवल उन्हीं लोगों को अलाउ करते हैं जो विशेष योग्यता हासिल करते हों लेकिन हमारे यहां तो कई बार दो बार तीन बार फेल होने वाले केन्डीडेट के लिये भी कॉलेज का एडमिशन अनिवार्य होना चाहिये, ऐसा कहा जाता है। इन सारी बातों का खयाल करते हुए माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे उचित बातों में सहयोग देंगे, जो आपके सामने सुझाव आये हैं उन सुझावों में इस सदन के माननीय सदस्यों का सदा सहयोग प्राप्त होता रहेगा तो हमें इन चीजों को हल करने में काफी कामयाबी रहेगी।

अन्त में मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सांभर के नमक के बारे में यह बात कही गई कि बजाय हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी को सौंपा जाय, यह कार्य राजस्थान गवर्नमेन्ट को अपने हाथ में लेना चाहिये। मुझे इस बारे में सदन को जानकारी देनी है, अभी इस बारे में बातचीत चल रही है, राजस्थान सरकार का उसमें उचित हिस्सा रहे, इस बारे में हम प्रयत्नशील है। हम चाहते हैं कि हमारे नमक के ज़रिये हमारा यह उद्योग ज्यादा से ज्यादा विस्तार पाये, इस मामले में हम प्रयत्नशील हैं। खास खास बातें थी, वह मैंने आपके सामने स्पष्ट

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

की और भी बातें डिमान्ड के समय आ सकती है। उस वक्त भी यदि आवश्यक हुई तो मैं सदन के समक्ष अपनी बातें पेश करूंगा।

श्री मदनसिंह : आपके डिपार्टमेन्ट पर आप ही रोशनी डालेंगे, रेवेन्यु मिनिस्टर साहब ने कहा था।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्वे के आधार पर आंकड़े दिये थे। वह रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वह सबको देखने को मिले इसलिये माननीय मुख्य मन्त्री महोदय उसे टेबुल ऑफ दी हाउस पर रख दें तो उसे हम देख लें, और यह भी जान लें कि फिगर्स किस आधार पर बने हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं, जो बहस दो दिनों से बजट पर चल रही है, उसके कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालूं, मैं माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा संयम....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : आपको कम छोला है।

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : और सौजन्य के साथ उस भाषण को सुना और उस पर और बजट की मदों पर चर्चा की।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : जवाब भी संयम से दिया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कुछ माननीय सदस्यों ने भाषण की भाषा की प्रशंसा की, कुछ ने जो बचत का बजट इस साल पास किया गया, उसको दाद दी। उससे कोई बहुत खुश होने की मुझे जरूरत नहीं थी। थोड़ी बहुत हुई थी कि चलो दाद तो मिलने

(हंसी)

लगी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि मेरी आलोचना के बहाने हमारे योग्य वित्त सचिव की सराहना यहां काफी की गई और मैं सचमुच पसन्द करता हूं कि ऐसे सचिवों को और साथियों को (हंसी) कि जिनके सुझाव पर या प्रस्ताव पर या नोट्स पर आंख मींचकर दस्तखत कर दूं, यह उनकी भी काबलियत का सुबूत है।

श्री भैरोंसिंह : और अपनी व्यवस्था का सुबूत है।

श्री जनार्दनराय नागर : आपकी तो है ही।

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इतने काबिल सचिवों और साथियों को अपने साथ रखना और रख सकना, उनको दाद देना यह क्या मामूली बात है?

(हंसी)

अब मैं आपसे थोड़ा सा कुछ प्रारम्भिक निवेदन कर देना चाहता हूं। अभी यहां यह कहा गया कि यहां सदन में जो कुछ कहा जाता है वह बहरे कानों पर पड़ता है। ये शब्द तो मेरे हैं पर भाव उनके हैं। पर ऐसी

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

बात नहीं है। पिछली दफा आलोचना हुई । उसमें एक यह था कि वित्त मन्त्री जी का भाषण बहुत क्लिष्ट है । तो अब के मैंने कोशिश की कि वह भाषण सरल हो और रोचक हो। सो जाहिर था कि वह लम्बा होता ।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : इसको अब के किससे लिखवाया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्यय : और दूसरी यह आलोचना की गई थी कि पिछली बार भाषण सुना, पर समझे कुछ नहीं और यह भी कहा गया कि बड़ा पोथा है, कहां तक गोता लगावें। अब के कोशिश की कि चुनी चुनाई चीजें आपको इसमें से दे दूं। वे दी हैं। तो हमारे माननीय मित्रों में से कुछ ने कहा कि जैसे खर्चे का आकार बढ़ता है वैसे "दा साहब" का भाषण भी बढ़ गया।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : यह "दा साहब" क्या ?

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह इनवर्टेड कोमा में है।

तो, मैं यह आपको निवेदन करना चाहता था कि मैंने इस दृष्टि से इस बार भाषण की रचना की और एक खास बात है । इससे पहले थोड़े दिन हमारे राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ था तो उसमें जितनी बातें खास तौर पर आ सकती हैं वे आ गई हैं, उनको दोहराने से बचाया है। तो, इस भाषण को लेते समय उनके भाषण को भी साथ रखें तो अपने राज्य की प्रगति और स्थिति का एक सही चित्र आपके सामने आ जावेगा । इसलिये जो इशारा किया गया कि फलां बात का ज़िक्र नहीं है तो वह इसलिये नहीं आया। एक बात का ओमिशन जरूर रह गया है कि जिसका मुझे अफसोस है और इसकी पूर्ति ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब ने अब कर दी। वह है, ट्रान्सपोर्ट को नेशनलाईजेशन करने का।

श्री जनार्दनराय नागर : आयुर्वेद के लिये रह गया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसके लिये कहूंगा, मैं। अब यह रह जाता है कि बजट बचत का है या घाटे का।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह तो माया जाल है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अब बचत है १२ लाख की तो कैसे कहेंगे कि घाटे का है। फिर भी कहें तो अपनी अपनी ही तो निगाहें हैं और अपनी अपनी समझ है । आखिर आप यह देखिये, कहा यह गया कि ५८ लाख का कर लगा कर इसको बचत का बताया गया। पर थोड़ा आप सोचेंगे कि ५८ लाख का कर क्यों लगाना पड़ा । बहुत आसान था नहीं लगाना, विकास कार्यों को स्थगित कर देते। तो जितनी आपकी रेवेन्यु की आमदनी है उसके मुकाबले में एडमिनि-स्ट्रेशन का मामूली खर्चा है। उसके बाद भी काफी बचत रह सकती थी। कोई जरूरत नहीं थी, कर लगाने की। पर विकास कार्यों को हम छोड़ नहीं सकते। उनको करना है इसके लिये बचनबद्ध थे, ११ करोड़ के आय साधन अधिक प्रस्तुत करने की। इसके सिलसिले में

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

५८ लाख हमने कर के ज़रिये इकट्ठा किया ।

श्री भैरोंसिंह : आपको यह बजट कितना सरप्लस बनाना है इसके पहले टार्गेट फ़िक्स्ड कर लिये थे कि बारह करोड़ का सरप्लस करना है और टैक्सेज फिर इम्पोज़ करने हैं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : १२ लाख है, करोड़ नहीं । इसी तरह वह पांच करोड़ की बात कही थी ।

(हंसी)

श्री सतीशचन्द्र (जौहरी बाजार, जयपुर) : दा साहब, जल्दी करिये । पांच बज जावेंगे ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तो और बातों में न जाकर जो मुद्दे की बातें छूट गई हैं माननीय मन्त्रियों के जवाब देने से उन्हीं पर मैं प्रकाश डालना उचित समझता हूँ । कर्जे के बारे में हमारे माननीय सदस्यों को कुछ घबराहट लगी । तो वैसे हमारी स्थिति अच्छी है । इसके ऊपर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रकाश डाल दिया है । फिर भी....

श्री भैरोंसिंह : जरूरत नहीं है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तो अच्छी बात है । तो, मैं यह बता रहा था आपको कि कुल ११० करोड़ रुपया जो कर्जा है, अपने पर उसमें से....

श्री मूलचंद डागा (पाली) : ११२ है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पर ११० और ११२ में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक अरब से ऊपर की चीज़ में, इससे फरक नहीं पड़ता । ४४ करोड़ रुपया भाखरा और चम्बल और राजस्थान कैनाल के लिये है । उस रुपये की अदायगी के लिए बैटरमेंट लेवी और ज़मीन की बिक्री की व्यवस्था अपने पास है । १५ साल के अन्दर अन्दर वह रुपया अपना चुका सकेंगे । अब रह जाता है ६८ लाख रुपया...

श्री भैरोंसिंह : करोड़ ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ६८ करोड़ । आपकी आवज यहां तक आ गई ।

(हंसी)

इसके लिए मैं निवेदन करूं कि फाइनेन्शियल कमीशन ने कन्सोलिडेशन करके उस पर अंतिम निर्णय दिया है । वह सुविधानुसार विचार करके निर्णय करेगा, जो डाइरेक्शन देगा, उसके मुताबिक हम इस स्थिति में हैं कि वह रुपया अदा कर सकेंगे । ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुआ तो चार आठ साल की म्याद ज़्यादा लेनी पड़ेगी । इससे ज़्यादा इस सम्बन्ध में अपने को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है...

श्री जर्नादनराय नागर : इसमें ब्याज शामिल है, दा साहब ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ब्याज हर साल दे देंगे । ब्याज का प्रोवीज़न रहता है प्रति वर्ष....

श्री भैरोंसिंह : क्या वित्त मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस वर्ष में कितना कर्जा चुकाना था, उसमें से कितना कर्जा चुका पाये ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): यह क्वेश्चन अवर में पूछें । आप अपनी बात कहिये ।

श्री मदनसिंह : अगर आप १९६१ से नहीं पधारे तो कौन बतायेगा ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : अब माननीय मंत्री जी को अपना भाषण देने दें ।

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एक बात यह कही थी कि कुचामन में रसायनिक मिश्रण की चक्की बनाई गई है, बिना स्थिति की जांच किये कि यह चक्की वास्तव में उपयोगी है या नहीं, वे रासायनिक पदार्थ वहां मिलते हैं या नहीं । इसकी जानकारी किये बिना उसे सब्सिडी दी गई है। मैं आपके द्वारा यह बताना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष, कि खादी कमीशन के द्वारा यह सहायता दी गई है, राजस्थान खादी बोर्ड के द्वारा नहीं । फिर जिस समय खादी आयोग दे दी, तो प्रारम्भिक जांच करवा ली थी और जो पत्थर इसके उपयोग में लाया गया है, वह वहां आस पड़ौस में मिलता है, वह काफी मज़बूत है, जिसकी चक्की वहां आम तौर पर बिकती है, उससे भी इधर ८, १० रोज़ पहले उनके टेक्नीकल मैन जांच करने आये थे दिल्ली से, उन्होंने जांच की है और जांच करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट वहां पेश की है, मंत्रालय में । उसकी जानकारी हमें नहीं मिली है । कहने का मतलब यह है कि जांच जरूर हुई है और जहां तक राजस्थान सरकार का सम्बन्ध है, हमने एक पैसा उसमें नहीं दिया है....

श्री जर्नादनराय नागर : आपसे राय ली होगी ?

श्री भैरोंसिंह : क्या वित्त मंत्री जी कहने का मतलब यह है कि एमरी स्टोर वर्क चल रहा था, उसके बारे में राजस्थान सरकार से कोई लोन नहीं दिया गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपने सब्सिडी देने की बात कही थी ।

श्री भैरोंसिंह : सब्सिडी या इन्डस्ट्रियल लोन नहीं दिया गया, यह कहा था ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपने सब्सिडी के लिए कहा था ।

श्री भैरोंसिंह : इन्डस्ट्रियल लोन के लिए कहा है, आप प्रोसीडिंग्स देख लें ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह मैं देख लूंगा ।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : आपने लोन दिया है, कागजात के अन्दर दिया है....

श्री श्रीभानसिंह : आपके कहने से वे कैसे कह सकते हैं, जब तक कि प्रोसीडिंग्स न देख लें कि आपने कहा या नहीं ।

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : शिड्यूल्ड

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

एरिया के बारे में यह कहा गया था कि कुछ भाग उदयपुर का शिड्यूल्ड एरिया घोषित कर दिया जाय। मैं आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, यह बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए केन्द्रीय सरकार से लिखा पढ़ी चल रही है। अभी केन्द्रीय सरकार ने अन्तिम निर्णय नहीं लिया है....

श्री जर्नादनराय नागर : सात साल से चल रहा है...

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : भारत सेवक समाज के सम्बन्ध में पांच करोड़ का जिक्र किया गया। वह पांच करोड़ नहीं है, पांच लाख रुपया है।

एक हटूंडी महिला आश्रम के आडिट का जिक्र आया है। मैं इस सम्बन्ध में जानकारी देना चाहता हूं, माननीय सदस्य को पूरी जानकारी नही है। यह ऑडिट १६५४–५५ का नहीं है, १६५७–५८ यानि पिछली साल ऑडिट कुछ देरी से हुआ है। इस आश्रम के जो भिन्न–भिन्न अंग है, बाल मंदिर इत्यादि, उनका ऑडिट हो चुका है। वैसे सारी संस्था का ऑडिट आडिटर के पास चला गया है और पांच सात दिन में हो जायगा। यह बताया कि पांच सात साल से नहीं हुआ है....

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ऑडिट होने से पहले हटूंडी महिला आश्रम को ग्रान्ट इन एड मिलती, वह दी गई है। यह कानून के अनुसार नहीं दी जानी चाहिए थी।

(घंटी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानमेरे पास उपलब्ध नहीं है। जो बात कही थी, उसकी जानकारी प्राप्त करके मैंने कहा था....

श्री जर्नादनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड एरिया के बारे में बहुत चलता हुआ आश्वासन मिला। मैं समझता हूँ, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और हमें विश्वस्त होना चाहिए। यह सात लाख भीलों के अधिकार का सवाल है।....

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज़ !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मावली को शिड्यूल्ड एरिया डिक्लेअर कर दें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि इससे ज्यादा राजस्थान सरकार क्या करेगी सिवाय इसके कि केन्द्र पर बराबर अपना प्रभाव डाले, इसके सिवाय राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर सकती। जो कर सकती है, वह किया गया है।

श्री जर्नादनराय नागर : यह सब मामला खत्म मानें, साहब।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : प्रशासन के खर्चे का जिक्र किया गया कि प्रशासन पर खर्च बढ़ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि प्रशासन पर खर्चा जरूर बढ़ा है लेकिन विकास के कार्यों पर जितना खर्चा बढ़ा है और पब्लिक यूटीलिटी पर जितना खर्चा हो रहा है, उसके मुकाबले में प्रशासन का खर्चा नहीं बढ़ा है....

श्री हरिप्रसाद यादव : उदयपुर में शिड्यूल्ड एरिया के लिए

(घंटी)

(श्री हरिप्रसाद यादव)

मैंने कल निवेदन किया था....

(घंटी एवं हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरे ख्याल से माननीय सदस्य उस वक्त ध्यान नहीं दे रहे थे।

मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस साल बजट ६४ करोड़ ४६ लाख का है, जिसमें से कम से कम ४३ करोड़ ९० लाख पब्लिक यूटीलिटी पर खर्च हुआ है और १९५२-५३ में ५ करोड़ ४७ लाख कुल खर्चा हुआ है। १० साल में आठ गुना यह खर्चा बढ़ गया है। इसके मुकाबले में प्रशासन का खर्च १९५२ में २ करोड़ ३ लाख था, वह आज ३ करोड़ ३७ लाख है। यह खर्चा करीब ड्योढ़े के करीब हुआ है। जब विकास के कामों में और पब्लिक युटिलिटी में खर्चा आठ गुना बढ़ गया है, इससे आप जान जायेंगे कि यद्यपि स्टॉफ का, प्रशासन का खर्चा बढ़ा है लेकिन जिस प्रपोशन से खर्चा...

श्री पी० के० चौधरी : On a Point of information, Sir...

श्री अध्यक्ष : No interruptions please. No information at this stage.

श्री पी० के० चौधरी : On a Point of information only.

श्री अध्यक्ष : Let him speak for atleast a few minutes before any interuption is made.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह भी कहा गया है कि बजट के आंकड़ों में आमदनी को बढ़ा कर बताया गया है और खर्च को घटा कर बताया गया है, यह सही नहीं है। उसमें खास तौर से कृषि सिंचन कर की मिसाल दी गई। कृषि सिंचन कर की आमदनी बढ़ गई, वह कैसे बढ़ गई, जब कि आमदनी पिछले साल कम हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कृषि सिंचन कर की रकम २० लाख पिछले साल फूंकी गई। इसमें कई कारण हैं, जिसकी वजह से वह रकम वसूल नहीं हो पा रही है, पहली बात तो यह आती है कि असेसमेंट के बाद अपील करने का अधिकार दिया गया, उसके माफिक असेसमेंट के बाद अपीलें दायर हो गईं, इसलिए वह रकम रुक गई। उसके बाद पी. डी. आर. के मार्फत रुपया वसूल करने में देर हो जाती हैं। इसके अलावा जागीरदारों से रुपया वसूल करना था, उसमें देरी हो रही है। फिर भी तीन लाख रुपया प्राप्त किया है। इस साल आशा है कि पिछले साल के बकाया वसूली की इस साल जो कोशिश की जा रही है, उसकी वजह से शक नहीं है कि पांच लाख नहीं, पांच लाख से ज्यादा रुपये इस मद में वसूल कर लेंगे। बजटिंग के बारे में कहा गया कि हमारा बजट ढीला-ढाला है। मैं आपको दूसरी स्टेट्स के आंकड़े भी बता देता हूं कि जिनमें इस मामले में जो बजट के वैरीयेशन्स हैं उसमें राजस्थान का नम्बर सभी में ऊंचा है। राजस्थान के जो वैरीयेशन्स हैं वह ५.९ है, मद्रास के ७.५ है, पंजाब के ३०.८४, हैदराबाद के १८.३६ हैं, उड़ीसा के १७.३३ हैं, त्रावनकोर कोचिन के २४.१ हैं, आंध्र के ८.२ हैं और सेन्टर के वैरीयेशन्स ४१.१२ हैं। इससे आप अन्दाजा कर सकते हैं। बजट आखिर तो अनुमान ही हैं। यद्यपि

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

ये पिछले सालों के आंकड़े के आधार पर बनाये जाते हैं लेकिन फिर भी वह अनुमान है। तो जितने वैरीयेशन्स दूसरी स्टेट्स में हैं उनके मुकाबिले में हमारे यहां वैरीयेशन्स बहुत कम हुए है। इनवेस्टमेंट के बारे में कहा गया था, वह माननीय सदस्य यहां पर नहीं हैं, तो मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं कि इनवेस्टमेंट अपना काफी सेफ है। कुल इनवेसटमेंट २८३ लाख ५२ हजार के करीब है...

श्री भैरोंसिंह : २८३ लाख के कितने करोड़ हुए ?

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : २ करोड़ ८३ लाख हुए। अब याद रख लीजिए, भूलियेगा नहीं। इसके अन्दर इनवेस्टमेंन्ट जो है और जिस पर हम डिविडेन्ड देते हैं वह १ करोड़ ८४ लाख है। तो यह उन कन्सर्न में है जिनमें डिविडेन्ड मिलता हैं और जो प्राइवेट के थोड़े कन्सर्न चल रहे हैं वह हैं १६ लाख के जिनमें आपका रुपया इनवेस्ट है और न्यू इनवेस्टमेंट आपका १० लाख का है। अलबत्ता जो कन्सर्न लिक्वी-डेशन में चले गये हैं उनमें सिर्फ आपका ६ लाख रुपया है और कुछ इनवेस्टमेंट ऐसा है कि जिन्हों से कुछ आमंदनी नहीं हो रही है वह १५ लाख का है। तो १५ लाख और ६ लाख जो है इसके लिए हम यह नहीं मानते कि यह सारा ही डूबने वाला हैं लेकिन इसमें से कुछ रकम के लिए हम ऐसा मान कर चल सकते हैं कि वह सुरक्षित नहीं है। तो इस प्रकार से मैं आपको यह बताना चाहता था कि जो आपका केवल इनवेस्टमेंट २ करोड़ ८३ लाख का है, वह बहुत सुरक्षित है। आपको उसकी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

इसी तरह से रिकवरीज के बारे में कहा गया था तो इसके बारे में भी काफी ध्यान दिया जा रहा है और उसकी डिटेल्स में मैं आपको अभी नहीं ले जाना चाहता हूं क्यों कि समय भी हो गया है।

(समय सूचक घंटी)

तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो कुछ बातें रह गई थीं कि जिनता यहां स्पष्टीकरण करना जरूरी था, मैं समझता हूँ कि मैंने वह स्पष्टी-करण कर दिया है।

(हंसी)

श्री महेन्द्रसिंह : Sir, we should extend the time if the Hon'ble Finance Minister wants to give any important information.

श्री अर्जनदास : And if it is un-important ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, समय में वृद्धि कर दी जाये और माननीय वित्त मंत्री महोदय को इस सदन में भाषण देने का पूरा समय दिया जाये और अगर नहीं दिया गया तो यह उनके साथ अन्याय होगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इस कृपा के लिए माननीय सदस्य को धन्यवाद है। मुझे जो कहना था वह मैं कह चुका और मैं यही आशा रखता हूं कि जिस प्रकार से आपने सहयोग इसमें दिया है भाषण के

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

वादविवाद में और चर्चा करने में उसी प्रकार इसको कार्यान्वित करने में भी सहयोग देंगे।

(करतल ध्वनि)

श्री अध्यक्ष : अब सदन की कार्यवाही कल तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही म० प० ५ बजकर ५ मिनट पर, शुक्रवार, दिनांक ६ मार्च, १६५६ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, ५ मार्च, ५६)

भी सामान्य वाद-विवाद जारी रहे। वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :–

(१) श्री मूलचन्द डागा

(२) श्री महेन्द्रसिंहपंवार

(३) श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

(४) श्री मुक्तिलाल मोदी

(५) मेजर फतहसिंह

(६) डॉ० बहादुरसिंह

(७) राजा मानसिंह

(८) श्री परसराम

(९) श्री मुरलीधर व्यास

सरकार की ओर से श्री नाथूराम-मिर्धा, कृषि मन्त्री, श्री रामकिशोर व्यास, गृह मन्त्री, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री एवं श्री हरिभाऊ उपाध्याय; वित्त मन्त्री, ने बहस का उत्तर दिया।

शुक्रवार दिनांक, ६ मार्च, ५९ की कार्य सूची

१ वापस लिये गये विधेयक

(क) राजस्थान भू. राजस्व (संशोधन) विधेयक १९५८

(ख) राजस्थान लैंड रेवेन्यु (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७

(ग) राजस्थान लैंड रेवेन्यु (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५८

(घ) राजस्थान लैंड रेवेन्यु (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १९५८

२. राजस्थान लैंड रेवेन्यु (संशोधन) विधेयक १९५९ (पुर. स्थापन)

३. आय व्ययक १९५९–६० द्वितीय अवस्था अनुदानों की मांगों पर मतदान

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३२६ का उत्तर देखिये)

प्रस्ताव संख्या १

जयपुर खाद्यान्न समस्या सम्मेलन राजस्थान सरकार से यह मांग करता है कि प्रान्त से गल्ले की निकासी को अविलम्ब ही रोकने की व्यवस्था की जाय। सम्मेलन की यह मान्यता है कि गत कई वर्षों से प्रान्त में अच्छी फसल होती रही है किन्तु खाद्यान्नों के भाव दिनों दिन बढ़ते रहे हैं। इस वर्ष तो भावों में अत्यधिक तेजी आ गई है जिससे जनसाधारण का जीवन यापन कठिन हो गया है।

सम्मेलन की राय में इस संकट का प्रमुख कारण राजस्थान का पश्चिमी जोन में सम्मिलित होना है जिससे कि यहां से खाद्यान्न सामग्री जोन के अन्य प्रान्तों में निर्यात की जाती है। और यह उर्दवत प्रान्त अभाव ग्रस्त हो गया है।

राजस्थान सरकार को चाहिये कि यदि अपने आपको गल्ले की निकासी को रोकने में असमर्थ पाती है तो वह राजस्थान को पश्चिमी जोन से व उत्तरी जोन सम्मिलित किये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार को मजबूर करे।

प्रस्ताव संख्या २

जयपुर खाद्यान्न समस्या सम्मेलन राजस्थान सरकार द्वारा खाद्यान्न सलाहकार समितियों के गठन में बरती गई पक्षपात पूर्ण नीति की घोर निन्दा करता है।

उस सम्मेलन की स्पष्ट राय में खाद्य समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है जिसको हल करने के लिये सभी दलों को सहयोग लेना वांछनीय है, देश के प्रधान मन्त्री ने भी इसी आशय को दृष्टिगत रखते हुए सभी दलों के सहयोग की अपेक्षा की है तथा प्रान्तियस्तर पर भी ऐसी सर्वदलीय कमेटियां गठित करने को राज्य सरकारों से कहा है।

इस सम्मेलन की यह स्पष्ट मान्यता है कि इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने प्रान्त के समस्त दलों की अवहेलना कर चाटुकारिता की वृत्ति को प्रोत्साहन दिया है अतः यह सम्मेलन प्रस्ताव करता है कि सरकार को प्रान्तीय एवं जिला स्तर पर समस्त राजनैतिक दलों तथा व्यापारियों, सहकारी समितियों व टेड यूनियनों की संस्थानों के प्रतिनिधियों की सलाहकार समिति गठित करें।

प्रस्ताव संख्या ३

जयपुर खाद्यान्न समस्या सम्मेलन प्रान्त में व्याप्त खाद्य संकट के लिये राजस्थान सरकार की ढिलमिल एवं दोषपूर्ण नीति को जिम्मेदार ठहराता है।

यह सम्मेलन यह भी अनुभव करता है कि यह देश का दुर्भाग्य है कि प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षिय योजनाओं के बावजूद भोजन जैसी मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता भी हमारे नागरिकों को जिन्दा रहने के लिये उपलब्ध नहीं है अतः यह सम्मेलन इस सोचनीय स्थिति को समाप्त करने के लिये राजस्थान सरकार के समक्ष सुझाव रखती है कि :

(१) स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन की स्थापना की जाय जो खाद्यान्न की एक स्वशासित व्यापारिक प्रतिष्ठान की तरह का व्यापार करें। इस प्रतिष्ठान की तरह का व्यापार करें। इस प्रतिष्ठान की अपनी अधिकृत पूंजी हो जिसके पचास प्रतिशत हिस्से सरकार खरीदें कार्पोरेशन के लिये यह आवश्यक हो कि खरीदे हुये गल्ले का वह न्यूनतम लाभ पर सहकारी समितियां अथवा अपनी दुकानों द्वारा वितरण करें।

प्रस्ताव संख्या ४

जयपुर खाद्यान्न समस्या सम्मेलन राजस्थान सरकार की वितरण व्यवस्था को जन-विरोध मानता है जब्त किये हुये गल्ले का स्टाक समाप्त हो जाने से यह समस्या और भी जटिल हो गई है जिसकी जिम्मेदारी सीधी राज्य सरकार पर है क्योंकि उसके द्वारा जयपुर शहर में बाहर से गल्ला मंगवाने की कोई सुयोजित योजना नहीं बनाई और गल्ले की जब्ती का आंतक फैला कर खुले बाजार में गेहूं, जौ व चना भी अप्राप्त कर दिया गया। अतः यह सम्मेलन राज्य सरकार को सुझाव देता है कि इस संकटमय स्थिति पर काबू पाने के लिये :

(१) मौजूदां सस्ते गल्ले की दुकानों पर गेहूं के अतिरिक्त जौ, चना भी उपलब्ध किया जावे।

(२) खाद्यान्न के अन्तर जिला व्यापार पर भी किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध न हो और इस सम्बन्ध में लागू की गई पर्मिट प्रणाली अविलम्ब ही समाप्त कर दी जाय।

(३) गल्ले के वितरण में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाय।

(४) प्रान्त की मंडियों से खरीद कर सस्ते गल्ले की दुकानों व सहकारी समितियों द्वारा गल्ला वितरण करने में सरकार अनुदान दें।

प्रस्ताव संख्या ५

खाद्यान्न की सोचनीय स्थिति व अत्यधिक मंहगाई को अनुभव करते हुये यह सम्मेलन पूरे जो के शब्दों में मांग करता है कि सरकारी व गैर सरकारी श्रमिकों प्रशासनिक कर्मचारियों को राज्य द्वारा निर्धारित दरों से भी सस्ते दरों पर खाद्यान्न का प्रबन्ध करें।

प्रस्ताव संख्या ६

जयपुर खाद्यान्न समस्या सम्मेलन यह अनुभव करता है कि सरकार जनहित के नाम

रूपी अखाड़े में अपने चाटूकार व्यापारियों के साथ फ्री स्टाइल कुश्ती करके परवरिश परस्त की जो नीति अपनाई है वह जन साधारण के लिये घातक तो है ही अनैतिक भी है।

कतपय व्यापारियों को अनाज का आयात पर्मिट देना सहकारी समितियों के प्रति अत्यधिक अवहेलना पूर्ण दृष्टिकोण अपनाना पीढ़ियों से अनाज का व्यापार करने वाले व्यापारियों के लाईसेन्स रद्द करके नये व्यापारियों सूचित करना तथा अस्पष्ट आदेश प्रसारित करना आदि सरकार के अनैतिक नीति के ठोस प्रमाण हैं।

अतः यह सम्मेलन इस नीति की घोर भर्त्सना करते हुये मांग करता है कि सरकार अपने आदेशों को स्पष्ट करते हुये शीघ्रातिशीघ्र इस प्रकार के अव्यवहारिक नीति को समाप्त करें। दिनांक २१ व २२ दिसम्बर ५८ को आयोजित जयपुर खाद्यान्न समस्या सम्मेलन में प्रेरित प्रस्ताव।

बागड़ा ४३५६

परिशिष्ट २

(प्रश्न काल में न लिये जाने वाले प्रश्नोत्तर)

राजस्थान लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन्स्टीटयूट, जयपुर

३४७. (२१६। एल. एल. एम.) श्री दयाकृष्ण विजय, एम. एल. ए., (छबड़ा)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान लोकल सेल्फ गवर्नमेंन्ट इन्स्टीट्यूट, जयपुर नाम की कोई संस्था कार्य करती है ? यदि हां, तो इसकी कब स्थापना हुई तथा इस संस्था का क्या विधान है ? विधान की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह सही है कि इस संस्था के पारित प्रस्ताव क्रियान्वित करने हेतु सरकार के पास भेजे जाते हैं ? यदि हां, तो अब तक इस संस्था ने कितने प्रस्ताव सरकार के पास भेजे ? प्रस्तावों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) इस संस्था के द्वारा पारित प्रस्तावों में से कितने प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार किये हैं, कितने विचाराधीन हैं तथा कितने अस्वीकार कर दिये गये ?

(घ) क्या सरकार के द्वारा स्वीकृति तथा अस्वीकृति की सूचना इस संस्था को भी दी जाती है ?

उत्तर

(क) जी हां। स्थापना सितम्बर १९५५ में हुई। विधान की प्रति सदन की मेज पर रखवा दी गई है।

(ख) केवल द्वितीय अधिवेशन अजमेर व कार्यकारिणी की प्रथम बैठक में पारित प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं और वे सरकार के विचाराधीन है। प्रति सदन की मेज पर रखवा दी गई है।

(ग) इस का उत्तर खंड (ख) में है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अनाज निकासी पर प्रतिबन्ध

३४८. (१६।आर. एम.) रावराजा सरदारसिंह, एम. एल. ए. (उनियारा)—क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अनाज लाने व लेजाने पर बन्दिश लगा रखी है ?

(ख) यदि हां, तो किस २ किस्म के अनाज की और किन २ आधारों पर ?

उत्तर

(१) यह सही नहीं है।

(२) यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

माही सागर नदी पर पुल

३४६. (१०७। ए. टी. एम.) श्री दयाकृष्ण विजय, एम. एल. ए., (छबड़ा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार माही सागर नदी जिला डूंगरपुर पर गढ़ी व सागवाड़ा के बीच के मार्ग में पुल बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(२) क्या यह सही है बरसात में गढ़ी से सागवाड़ा जाने वालों को नदी आ जाने से २०० मील की यात्रा करके ७ मील की दूरी पार करनी पड़ती है ?

उत्तर

३४६

१. प्रस्ताव विचाराधीन है.

२. जी नहीं....।

नाव की सुविधा उपलब्ध होती है.

राजस्थान में बाजरे व गेहूं की उपज

३५०. (४५ए.ए. टी. एम.) श्री मुरलीधर व्यास, एम. एल. ए., (बीकानेर सिटी)—क्या खाद्य एवं रसद मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में प्रति वर्ष कुल कितने बाजरे व गेहूं की खपत होती है ?

(२) क्या राज्य में पैदा होने वाला बाजरा व गेहूँ राज्य की आवश्यकता के लिये पर्याप्त है ?

(३) सन् ५७-५८ में राज्य से कुल कितना गेहूं बाहर गया व बाहर से सरकारी तौर पर व व्यापारियों द्वारा देशी व विदेशी कुल कितना गेहूं राजस्थान में आया ? अलग अलग बतावें।

(४) क्या राज्य सरकार ने राजस्थान में एक जिले से दूसरे जिले में अनाज ले जाने

की कोई पाबन्दी लगाई है ? यदि हां, तो क्यों क्या इस प्रकार की पाबन्दी दूसरे राज्य में माल भेजने पर भी लगाई है ?

(५) ऐसी हालत में अकाल घोषित जिलों में अनाज देने की सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

उत्तर

१. राजस्थान में खाद्यान्नों की खपत के बारे में कोई सर्वे नहीं किया गया है इस कारण यह बताना मुमकीन नहीं है कि राजस्थान में गेहूं व बाजरे की खपत कितनी होती है। राजस्थान में बाजरे की औसतन ऊपज ७,००,००० टन रही है और सन् ५५–५६ में जब बाजरे की ऊपज औसत ऊपज के बराबर थी उस समय रेल द्वारा राजस्थान से १६,१५४ टन बाजरे का निर्यात हुआ था सड़कों द्वारा निर्यात के आंकड़े प्राप्त नहीं है और न इस प्रकार के आंकड़े एकत्रित करने की कोई ऐजेन्सी ही है।

२. जैसा कि पहले प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि खाद्यान्नों की खपत के बारे में कोई सर्वे नहीं किया गया है और इस प्रश्न का कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा सकता है। परन्तु इन दोनों खाद्यान्नों का राजस्थान में औसतन आयात से अधिक निर्यात हुआ है इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि औसतन ऊपज जो है वह खपत से अधिक ही है।

३. जो अनुमान इस बारे में जिलाधीशों से प्राप्त हुई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। सब चीजों का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्यों कि सरकार ने इस तरह के आंकड़े एकत्रित करने की कोई ऐजेन्सी सब जगह नहीं बना रखी है। विदेशी आयात किये हुये गेहूं राजस्थान में सन् ५७–५८ में २४,६२६ टन है।

४. राजस्थान में राज्य सरकार ने एक जिले से दूसरे जिले में अनाज ले जाने पर कोई पावन्दी नहीं लगाई है परन्तु केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के समस्त जिलाधीशो को एसेन्सियल कमोडिटिज़ एक्ट की धारा ३ (२) कलाज़ एफव एच. आई. जे. के. के अन्तर्गत जो अधिकार दिये हैं उनके तहत जिलाधीशों ने इस आसय से कि उनके जिलों में खाद्यान्नों के भाव अधिक न बढ़े और अनाज पर्याप्त मात्रा में मिल सके। कुछ आदेश अपने अपने जिले में दिये है। गेहूं राजस्थान से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है इस प्रकार की आज्ञा केन्द्रीय सरकार ने लगाई है और इसी प्रकार चना बीकानेर डिविज़न से तथा बाजरा चुरु, सीकर, झुन्झनू जिले से बाहर नहीं जा सकता है इस प्रकार की आज्ञा भी केन्द्रीय सरकार ने ही लागू की है।

५. जिन जिलों में अकाल जैसी स्थित है वहां पर आयात किया हुआ विदेशी गेहूं काफी मात्रा में भेजा जाता है तथा अन्य खाद्यान्न जो दूसरे जिले में सरप्लस है अकाल ग्रस्त जिलों में भेजने की व्यवस्था है। और अन्य प्रकार के खाद्यान्न भी भेजे जा रहे हैं।

मुद्रणालय कृपया सूची आगे देखिये

(कृपया प्रश्न संख्या ३५० का उत्तर देखिये)

	नाम जिला	खपत बाजरा	खपत गेहूं	५७–५८ में बाहर से आया गेहूँ	बाहर गया गेहूँ
१ :	झुन्झुनू	४२,२२,४४० मन	९९४५००	७११३७	—
२ :	सिरोही	१,३८,०००	६२७५०००	८०१००	४४४६
३ :	झालावाड़	१,४४,४८	४५५३४२	१२८८०	२८६१९
४ :	बाड़मेर	२८,८८,०३५	३४२१९०	३३२६०	—
५ :	भीलवाड़ा	—	२००००००	२२६४८	५८२४४
६ :	चित्तौड़गड़	—	—	५४९५	—
७ :	बूंदी	—	१००००००	—	—
८ :	डूंगरपुर	—	१६८०००	८१७६	—
९ :	गंगानगर	१००,०००	१००००००	१८७३८	१५०००००
१० :	सीकर	३०,४५,६००	१५२२८००	४९०५६	—
११ :	अलवर	८१,५०,९२	४९०५६	१८५५०	—
१२ :	पाली	१९३८१२	४००६१८८	५०३७	—
१३ :	बांसवाड़ा	—	२०००००	—	—
१४ :	नागौर	८,११,७१२	९०५८००	२८८४०	—
	कुल योग	१३,२२,९८,३९	१८२६१०२६ ६४००००	३४५०३७ ७६१८७	१५९२३७९ मन

२३-२-५६

चावल की पैदावार तथा उसका आयात एवं निर्यात

१५६. (६६। आर. एम.) डाक्टर बहादुरसिंह एम. एल. ए., (धौलपुर)— क्या खाद्य एवं रसद मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सन् ५५–५६ व ५६–५७ में राजस्थान के किस किस जिले में कितना कितना चावल पैदा हुआ ? सूची सदन में प्रस्तुत करें।

(ग) राजस्थान के किस किस जिले से कितना कितना चावल राजस्थान के बाहर गया ?

(ग) क्या यह सत्य है कि धौलपुर से चावल बाहर गया ? यदि हां, तो कितना तथा क्या सरकार की जानकारी में है कि व्यापारी सरकार को बगैर सूचना दिये ही चावल बाहर ले गये ?

—

उत्तर

(१) सन् ५५–५६ व ५६–५७ में राजस्थान में जितना चावल पैदा हुआ है उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत की जा चुकी है।

(२) सन् ५५–५६ में ३६,२८६ मन और ५६–५७ में ५३,५६५ मन चावल बाहर गया यह आंकड़े रेलवे से मिले हैं जिलेवार आंकड़े प्राप्त नहीं हुये हैं। और न प्राप्त हो ही सकते हैं। ट्रकों द्वारा चावल बाहर गया उनके आंकड़े एकत्रित करने की कोई ऐजेन्सी नहीं है।

(३) धौलपुर से बाहर चावल कितना गया इसके आंकड़े प्राप्त नहीं है राजस्थान से बाहर चावल जाने पर केन्द्रीय सरकार की तरफ से इन सालों में कोई रोक नहीं थी इसलिए व्यापारियों को सरकार को सूचित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

सन् १६५५–५६ व ५६–५७ में राजस्थान में जिलेवार चावल पैदा होने की सूची निम्न प्रकार है :—

	नाम जिला	५५–५६	५६–५७
१	चित्तौड़गढ़	१६३४ टन	११६५ टन
२	कोटा	२०४५ टन	२५२६ टन

१	२	३
३ डूंगरपुर	१५,४८७ टन	३१२१५ टन
४ उदयपुर	३२६० टन	६५२६ टन
५ भरतपुर	१८,६६६ टन	२६३५० टन
६ बूंदी	४३६ टन	५०२ टन
७ बांसवाड़ा	६१,३२६ टन	३६,६२० टन
८ गंगानगर	१६२७ टन	१६४२ टन

बागड़ा ३३५६

परिशिष्ट ३

(अतारांकित प्रश्नोत्तर देखिये)

१. १२४ (३४। ए. टी. एम.) दिनांक २०-२-५६

श्री गिरधारीलाल, एम. एल. ए., वि. सं० ४७-क्या सहकारी मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर जिले में कुल कितनी सहकारी समितियां हैं तथा किन २ स्थानों पर ?

(२) उपरोक्त सहकारी समितियों को सरकार की ओर से कितनी कितनी धनराशि मिली हुई है ? प्रत्येक समिति के सदस्यों सहित एक तालिका सदन की मेज पर रखी जावे ?

(१) सूची संलग्न है।

(२) सूची संलग्न है।

(सूची अत्यधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

२ १८६ (६७। आर. एम.) दिनांक २४-२-५६

डॉ० बहादुरसिंह, एम. एल. ए. वि, सं० १० क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) धौलपुर उप-जिले में कितना गल्ला वितरण कराया गया है और किस २ महीने में

(२) वितरण की क्या व्यवस्था की गई थी ?

उत्तर

(१) धौलपुर उप जिले में अगस्त सन् १६५८ से फरवरी १६५६ तक कुल १५४३ टन विदेशी गेहूं व १०० टन मिलो (milo) वितरण किया गया जो महिने वार इस प्रकार हैं :—

अगस्त	५२ टन
सितम्बर	१०३ ,,
अक्टूबर	८६ ,,
नवम्बर	८४ ,,
दिसम्बर	४१८ ,,
जनवरी	२८६ ,,
फरवरी	५१४ ,,

तथा मिलो माह सितम्बर में १०० टन।

(२) उक्त गल्ला सस्ते अनाज की दुकानों द्वारा वितरण किया गया।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक ५ मार्च, १९५९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
२३८४	१९	डाइरेक्टर	डाइरेक्ट
२४०३	२	शासन मंत्र	शासन मंत्री
२४३३	६	निकस्थ	निकटस्थ
२४४५	अन्तिम से २	पच साल	पांच साल
२४५२	अन्तिम से ६	मैं हम	में हम
२४५३	२२	में उस	मैं उस
२४६२	४	राज्जों	राज्यों
२४६२	१८	हमापा शिक्षा मंत्रीलय	हमारा शिक्षा मंत्रालय
२४९९	१९	wouid	would
२५३७	१३	नहीं भांगे	नहीं मांगे
२५३९	२४	आप उटा देंगे	आप उठा देंगे
२५४३	अन्तिम से १	n the House.	in the House
२५४३	अन्तिम से २	if order	of order
२५६३	१३	मैंने और	मेन हैं और
२५८६	१	यह जान	यह जानकारी
२५९१	१	(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)	(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)
२५९७	७	कटिन	कठिन
२६०२	१५	औतसन	औसतन